खण्ड-166, अंक-3
बुधवार, 10 फाल्गुन, शक संवत् 1877
(29 फरवरी, 1956 ई0)

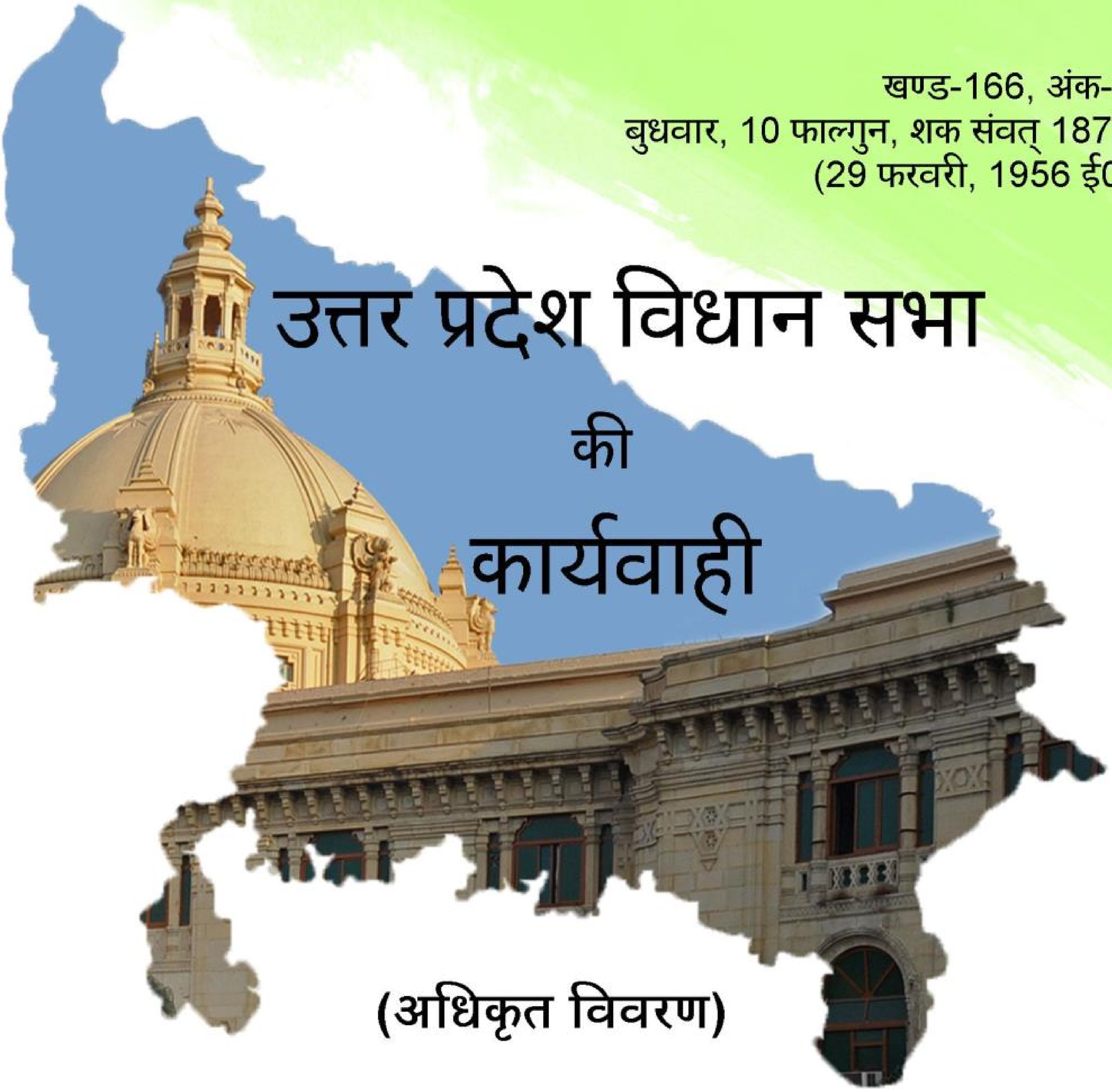

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 166 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

LEGISLATURE
25 JUL 1956

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २९ फरवरी, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२०)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री

जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीका राम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिमअली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन बाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री

मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार सिंह तिवारी, श्री
रामअधीन यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामंजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सत्यनारायण, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान ख़ां हकीम, श्री
हमीद ख़ां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुक्कुमसिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २९ फरवरी, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य के विभिन्न स्थानों में खनिज-पदार्थों की खोज के लिए मांग

**१—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)—क्या डाइरेक्टर आफ जियालोजी और माइनिंग को प्रदेश का सर्वे करने में यह पता चला है कि इस प्रदेश में लोहा और तांबे की अच्छी खानें हैं? यदि हां, तो इस बात को और पक्की तरह से पता लगाने के लिये सरकार क्या कार्रवाई कर रही है?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—जी हां, गढ़वाल और अल्मोड़ा जिले के कुछ क्षेत्रों में तांबा और लोहे की कुछ खानों का पता चला है। इस सम्बन्ध में और अधिक अन्वेषण भविष्य में कराया जायगा।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी को सूचना मिली है कि मिर्जापुर जिले में सोन नदी के दक्षिण कैमूर पर्वत श्रेणी में कलना पहाड़ी, छिकड़ा टीला, कुसियरा पहाड़ी (निंगाई गांव के पास) में लोहे व पत्थर की खानें हैं।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जिन स्थानों का जिक्र है उनकी ब्योरेवार मेरे पास कोई सूचना नहीं है। हमारा जियोलोजी का विभाग इस कार्य में लगा हुआ है और सर्वे कर रहा है। यदि माननीय सदस्य के पास कोई ऐसी सूचना है तो उसे जियालोजी विभाग को दें जिससे वह मालूम कर सके।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या डायरेक्टर आफ जियोलोजिकल सर्वे ने कोई सर्वे बुन्देलखंड में भी कराया है, और यदि कराया है तो वहां कौन कौन से खनिज-पदार्थ पाये जाने की संभावना है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी इस सम्बन्ध में सीमित काम हुआ है, क्योंकि इन डायरेक्टर महोदय के तत्वावधान में जिन टैक्नीकल असिस्टेंटों की नियुक्तियां की थीं उनकी संख्या कम थी, इसलिये अभी वे अपना विशेष ध्यान पहाड़ी इलाकों में ही अधिक दे सके हैं। भविष्य में इनका कार्यक्षेत्र बढ़ाया जा रहा है तथा अधिक टेक्नीकल असिस्टेंट और जियोलोजिस्ट्स की नियुक्ति की जायगी। बांदा में एक प्रकार की सैन्ड पाये जाने के बारे में जानकारी करायी गयी है।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि पर्वतीय इलाकों के किन-किन जिलों का सर्वे किया गया है?

श्री बनारसीदास— अल्मोड़ा और गढ़वाल के अन्दर किया गया है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)— क्या यह सही है कि बस्ती के उत्तरी हिस्से में सरकार को कोयले का पता चला है?

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ श्री व्रजभूषण मिश्र ने पूछा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अभी तो जैसा मैंने बताया डायरेक्टर महोदय का कार्यक्षेत्र सीमित रहा है, क्योंकि उनके पास उतनी संख्या में व्यक्ति नहीं हैं जो अधिक स्थानों पर अनुसंधान के कार्य में लगाये जा सकें। ज्यों ज्यों कार्यकर्तागण बढ़ते जायंगे त्यों-त्यों प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में जहां-जहां खनिज-पदार्थ पाये जाते हैं या पाये जाने की सम्भावना है, या अनुमान लगाया जाता है कि वहां मिल सकते हैं, वहां-वहां अन्वेषण का कार्य उनके द्वारा कराया जायगा।

श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)---क्या सरकार को मालूम है कि बिजनौर जिले में लालधान के पास कोयला पाया जाता है? क्या इसकी खोज का कार्य शुरू हो गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मेरे पास तो यह सूचना नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे यह सूचना डायरेक्टर महोदय के पास भेज दें जिससे वे अपनी जानकारी को अधिक बढ़ा सकें।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार को मालूम है कि अल्मोड़ा में तांबे और लोहे के अतिरिक्त अभ्रख और जिप्सम भी पायी जाती है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जितनी चीजें वहां पायी जाती हैं डायरेक्टर महोदय उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद सरकार को उससे सूचित करेंगे और यह भी बतायेंगे कि उनके बारे में क्या-क्या किया जा सकता है।

तारांकित प्रश्न

चित्रकूट के विकास के लिए उत्तर प्रदेश तथा विन्ध्य प्रदेश की सामूहिक योजना

*१---श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चित्रकूट के विकास की योजना क्या है, उसमें कितना धन व्यय होगा और विन्ध्य प्रदेश सरकार उसका कितना भार वहन करेगी?

श्री बनारसीदास---चित्रकूट के विकास की योजना का प्रश्न उत्तर प्रदेशीय और विन्ध्य प्रदेशीय सरकार के विचाराधीन है। उत्तर प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश सरकार की एक ज्वाइन्ट डेवलपमेंट कमेटी चित्रकूट के आसपास के इलाके का विकास करने के लिये बनाने का विचार है। यह भी राज्य सरकार के विचाराधीन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चित्रकूट से लेकर सीतापुर तक तीन मील लम्बी पक्की सड़क बनाई जाय।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह चित्रकूट योजना कब से आरम्भ की गई है और कौन-कौन से सज्जन इस योजना में विचार कर रहे हैं?

श्री बनारसी दास---इसका उत्तर दिया जा चुका है। दोनों सरकार की ओर से एक ज्वाइंट कमेटी बनाने का विचार है।

श्री श्रीचन्द्र---कौन-कौन से सज्जन हैं?

श्री बनारसीदास---मैंने बतलाया सज्जन तो जब होंगे जब वह कमेटी बनेगी। अभी तो विचार हो रहा है।

आगरे में ताजमहल के आसपास विकास-कार्य

*२---श्री देवकीनन्दन विभव---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा के ताजमहल के चारों ओर के क्षेत्र के विकास के लिये उसके अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को देखते हुये कोई योजना बनाई जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बनारसीदास—ताजमहल के भीतर तथा बाहर के क्षेत्र को सुधारने में शासन की ओर से प्रयत्न जारी हैं। इसी के लिये एक नलकूप भी बनाया गया है जिससे ताज के भीतर के उद्यान काफी सुधर गए हैं। सड़कों पर भी विद्युत प्रकाश की व्यवस्था कर दी गई है।

ताजमहल को जाने वाली मेकडोनल सड़क की मरम्मत और तारकोल के प्लास्टर के लिए सरकार ने ३७,५०० रु० भी स्वीकार किया है, जो कि शीघ्र ही व्यय किया जायेगा।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि ताजमहल के आसपास गन्दी बस्तियां उत्पन्न हो गई हैं और शहर से वहां तक कई सड़कें आती हैं उनकी दशा भी बहुत खराब हो गई है। तो क्या माननीय मंत्री जी इसके सुधार के लिये कुछ प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह कार्य तो, जो वहां का डेवलपमेंट बोर्ड है उसको करना है, और उसका ध्यान इस ओर आकर्षित कराया जाय।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ताजमहल देखने के लिये जो भी लोग बाहर या फारेन कंट्रीज से आते हैं वे चाहते हैं कि दो-चार रोज ताजमहल के पास विश्राम कर सकें। तो क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि कोई अच्छी श्रेणी का विश्रामालय वहां बनाया जाय?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी कुछ गेस्ट हाउसेज बनाने की योजना हमारे समक्ष है लेकिन अभी यह निश्चय नहीं हुआ है कि कहां-कहां गेस्ट हाउसेज ऐसे स्थानों के लिये बनाये जायं।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि ताजमहल की देखरेख प्रान्तीय सरकार के सुपुर्द है या केन्द्रीय सरकार के?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—केन्द्रीय सरकार के आर्चियोलाजिकल डिपार्टमेंट के सुपुर्द उसकी देखरेख है।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार को इस बात का ख्याल है कि जब गेस्ट हाउसेज वह बनायेगी, तो ताजमहल के पास गेस्ट हाउस बनाने के लिये प्रथम प्राथमिकता देगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस सुझाव के ऊपर सरकार अवश्य सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

आजमगढ़ जिले के चर्खा केन्द्रों में सूत का उत्पादन

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में कितने सरकारी चर्खा केन्द्र कहां-कहां हैं?

श्री बनारसीदास—आजमगढ़ जिले में निम्नलिखित स्थानों में १२ सरकारी खादी केन्द्र चल रहे हैं—

१—जहानागंज
२—करहा
३—घोसी

नोट—तारांकित प्रश्न ३—५ श्री झारखंडे राय ने पूछे।

४—दोहरीघाट
५—मार्टिनगंज
६—कोयलसा
७—भैरोदासपुर (महाराजगंज)
८—कोपागंज
९—बरूआगोदाम
१०—मुहमदाबाद
११—रौनापार
१२—मेहनाजपुर

*४—श्री रामसुन्दर पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रत्येक केन्द्र पर कितने-कितने कार्यकर्ता हैं और उन्हें वेतन कितना-कितना मिलता है ?

*५—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५४-५५ तथा १९५५-५६ में प्रत्येक केन्द्र पर अलग-अलग मनों में सूत की खरीद क्या है ?

श्री बनारसी दास—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४८ पर)

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि अन्य स्थानों से भी चर्खा केंद्र खोलने के लिये प्रार्थना-पत्र सरकार के पास आये हैं ?

श्री बनारसी दास—पहले सूत खरीदने में दिक्कत थी इसलिये बड़े-बड़े क्षेत्रों में ही केंद्र सैंक्शन किये गये थे। जब और केंद्र बढ़ाये जायेंगे तो जिन स्थानों की मांग है उन पर भी विचार किया जायगा।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि अतरौलिया और अहरौरा के लोगों ने प्रार्थना-पत्र माननीय मंत्री और डायरेक्टर महोदय के पास दिये थे ?

श्री बनारसी दास—आशा की जाती है कि इन दोनों स्थानों पर केंद्र शीघ्र ही स्थापित हो जायेंगे।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि चर्खा संघों को अगर गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है तो उनके कपड़े के ऊपर २ आना रुपया की छूट नहीं मिलती ?

श्री बनारसीदास—इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां पर खादी बनायी जाती है तो उसकी बिक्री पर सभी जगह गवर्नमेंट की तरफ से रिबेट दिया जाता है।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो सूत क्रय होता है वह गांधी आश्रम के द्वारा क्रय किया जाता है। क्या उस खरीद में केंद्रों पर सिखाने वालों का सहयोग प्राप्त किया जाता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सहायता सभी से ली जाती है। जहां तक गांधी आश्रम के कार्यकर्त्तागण हैं वे इस कार्य में विशेषज्ञ समझे जाते हैं इसलिये बहुत कुछ कार्य तो उनकी सलाह से ही होता है।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या सरकार ने इन चरखा केंद्रों में बिनाई का प्रबन्ध भी किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उनका सूत बिनाई केंद्रों में भेजे जाने की व्यवस्था की जा रही है। अभी तक सूत गांधी आश्रम ही लेता है और बुनाई के केंद्रों पर भिजवा देता है।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी के पास इस तरह की शिकायत आई है कि गांधी आश्रम के लोग जो सूत खरीदते हैं वह जिस नम्बर का सूत होता है उस से सूत का नम्बर घटाकर सूत खरीदते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरे पास तो कोई ऐसी सूचना नहीं आई है, लेकिन मैं समझता हूं कि गांधी आश्रम के कार्यकर्त्ताओं के प्रति ऐसी शंका करना एक ऐसी भावना को प्रकट करना है जो वास्तविकता में है नहीं, जिसका मतलब यह है कि वह ऐसे व्यक्तियों के प्रति जो अच्छा काम करें अपनी किसी भावना के कारण अनुदार हो गये हैं और इसीलिये वे ऐसा आरोप लगाने के लिये उद्यत हुये।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाढ़पीड़ित क्षेत्र में जो सूत बदलाया जाता है उसमें गुन्डी पीछे सरकार कितनी छूट या सहायता देती है ?

श्री बनारसीदास—सरकार की ओर से २ आना प्रति गुन्डी के हिसाब से छूट दी जाती है।

*६—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)—[१४ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

कोयले की तौल के सम्बन्ध में शिकायत

*७—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि रेलगाड़ी के डिब्बों से जिस जगह कोयला गिराया जाता है उस स्थान पर उसी समय कोयला तौलने का कोई प्रबन्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। केवल कुछ प्रमुख स्टेशनों पर ही तौलने की मशीनों का प्रबन्ध है। अन्य स्टेशनों पर उनकी उपयोगिता से कहीं अधिक खर्च इन मशीनों के लगाने में होगा जो रेलवे विभाग उठाने के लिये तैयार नहीं है।

*८—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (अनुपस्थित)—क्या कोयला के हिसाब में जो त्रुटियां देखी गई हैं उन पर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है ? यदि हां, तो उनमें मुख्य-मुख्य त्रुटियां क्या हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बड़ी रेलवे लाइन से छोटी रेलवे लाइन के डिब्बों में माल लादने की क्रिया में कमी की शिकायतें हुई हैं। किन्तु यह कमी कोई ज्यादा नहीं है। विशेष मामलों में परिस्थितियों के अनुसार विचार किया जाता है।

उन्नाव जिले में अस्पताल बढ़ाने की प्रार्थना

*९—**श्री देवदत्त मिश्र** (जिला उन्नाव)—क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले में कितने राजकीय साधारण और जनाना एलोपैथिक अस्पताल, तथा कितने आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सालय हैं ?

श्री बनारसीदास—इनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १४९ पर)

*१०—**श्री देवदत्त मिश्र**—क्या चिकित्सा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ५३–५४ और ५४–५५ वर्ष में इन अस्पतालों और चिकित्सालयों को कितना रुपया सरकार ने औषधियों के लिये दिया और उनमें से कितना-कितना रुपया सुमेरपुर और भगवन्तनगर अस्पतालों को दिया गया ?

श्री बनारसी दास—इन चिकित्सालयों को सन् १९५३–५४ में कुल २५,०४८ रुपया और १९५४–५५ में ३४,६१५ रुपया मिला। भगवन्तनगर और सुमेरपुर चिकित्सालयों को १९५३–५४ में १,२६७ रु० और १९५४–५५ में १,५०० रु० प्रति चिकित्सालय मिला।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या जिला नियोजन समिति की सिफारिशों को देखते हुये माननीय मंत्री, दक्षिण पुरवा निर्वाचन क्षेत्र में, जहां यूनानी और आयुर्वेदिक अस्पताल नहीं हैं, जगतपुर और बारा में होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह प्रश्न जो आपने किया इसमें आपने बहुत से नाम गांवों के लिए, तो गड़बड़ सी हो गयी है।

श्री देवदत्त मिश्र—दो गांवों का नाम लिया है। जिला प्लानिंग कमेटी की सिफारिश भी हुई है वहां खोलने के लिये, दक्षिण पुरवा तो निर्वाचन क्षेत्र है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कितनी सिफारिशें जिला नियोजन समितियों से आयी हैं जब यह निर्णय करने बैठेंगे कि अगले वर्ष में कहां कहां अस्पताल खोलने हैं, तो उन सारी सिपारिशों के ऊपर विचार करेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री इन अस्पतालों में प्रतिदिन रोगियों की संख्या देखते हुए सहायतार्थ रकम बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तहत में सारे अस्पतालों के विषय में, जहां रोगियों की संख्या अधिक है और जहां उनकी आवश्यकतायें अधिक हैं, कुछ अनुदान बढ़ाने की योजना है और इसलिये इस अस्पताल के संबंध में भी इस बात के ऊपर विचार करेंगे।

चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के कर्मचारियों को सुविधायें

*११—**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि अभी तक चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के कर्मचारियों के हेतु कोई स्टैंडिंग आर्डर नहीं बने हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—फैक्ट्री के लिये स्टैंडिंग आर्डर बनाये जा चुके हैं और श्रम कमिश्नर कानपुर को Industrial Employment (Standing orders) Act, 1946 के अन्तर्गत प्रमाणित करने के हेतु भेजे गये हैं। प्रमाणित हो जाने पर ये आज्ञायें लागू कर दी जायेंगी।

*१२—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के उच्चस्तरीय तथा निम्नस्तरीय स्टाफ को क्या-क्या वेतन तथा अन्य सुविधायें मिलती हैं ?

श्री बनारसीदास—फैक्ट्री के स्टाफ के वेतन तथा अन्य सुविधाओं का ब्योरा संलग्न तालिकाओं में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १५०–१५५ पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि श्रम कमिश्नर, कानपुर के द्वारा चुर्क सीमेंट फैक्ट्री को स्टैंडिंग आर्डर कब भेजा गया ?

श्री बनारसीदास—इसको भेजे हुये काफी समय हुआ है। उसके अन्दर कुछ कमियां थीं। बाद में लेबर कमिश्नर से सलाह-मशविरा किया गया। अब अंतिम रूप से उनके पास तमाम कागजात ठीक करके भेज दिये गये और आशा की जाती है कि बहुत जल्दी रजिस्ट्री हो जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मेरा प्रश्न यह था कि प्रथम बार यह स्टैंडिंग आर्डर श्रम कमिश्नर के पास कब फाइनलाइज करके भेजा गया ?

श्री बनारसी दास—गत वर्ष १९५५ में अप्रैल के महीने के करीब भेज दिये गये थे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री में श्रमिकों के कितने क्वार्टर बन चुके हैं?

श्री अध्यक्ष—क्वार्टरों के बारे में तो पंदरहवां प्रश्न है बाद में। इसमें नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—सुविधा इस में है, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—जब इस संबंध में प्रश्न १५ प्रत्यक्ष मौजूद है तो उस वक्त पूछ लीजियेगा।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतलायेंगे कि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री में निम्नस्तरीय कार्यकर्त्ता कुछ ऐसे भी कार्य करते हैं जिससे उनके स्वास्थ्य को दिन प्रतिदिन हानि हुआ करती है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वैसे तो फैक्ट्री में जो कार्य होते हैं वह काफी मेहनत के काम होते हैं और प्रत्येक मेहनत के काम में कुछ न कुछ स्वास्थ्य को धक्का लगता है, नुक्सान पहुंचता है।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अन्य जो कर्मचारी हैं वहां उनसे कुछ अधिक वेतन उन्हें दिलाने पर विचार करेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वेतन तो सब किस-किस तरह के कार्य हैं उन सबको देखकर और उन पर विचार करके रखा जाता है, और उसमें यह समझ लिया जाता है कि अमुक व्यक्ति अमुक कार्य के ऊपर नियुक्त है, तो उस अमुक व्यक्ति की तनख्वाह उसी के अनुसार होनी चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार का विचार केसा की तरह चुर्क सीमेंट फैक्ट्री में भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट लागू करने का है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वह सारी सुविधायें जो कि मजदूरों को और क्षेत्रों में मिली हुई हैं उन सब को सरकार इस सीमेंट फैक्ट्री में लागू करने के ऊपर विचार कर रही है, और उन्हें लगाना भी चाहती है।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या यह सही है कि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री में जो निम्नवर्ग के कार्यकर्त्ता काम करते हैं उनके लिये क्वार्ट्र्स बनाने के बजाय पार्क और गारडेंस बनाने को प्राथमिकता सरकार दे रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मकान भी बन रहे हैं और पार्क्स इत्यादि के बनाने की व्यवस्था भी की जा रही है, क्योंकि पार्क्स वगैरह की व्यवस्था उनके बच्चों के लिये की जाती है, और उसकी भी आवश्यकता उतनी ही है जितनी कि आवश्यकता उनके मकानों के बनाने की है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि अभी वहां के जो कर्मचारी हैं उनकी सर्विसेज रेगुलराइज नहीं हुई है, नियमित नहीं करार की गई है, और वह कब तक हो जायंगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जितनी जगह परमानेंसी के लिये सैंक्शन कर दी गई है उन सब पर जो व्यक्ति वहां नियुक्त हैं उनकी सारी सर्विसेज रेगुलराइज हो रही हैं और कुछ हो भी गई हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार चुर्क सीमेंट फ़ैक्ट्री के श्रमिकों को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन की भी कोई सुविधा देने जा रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक चुर्क फैक्ट्री का संबंध है वह तो एक पब्लिक सेक्टर की फैक्ट्री है। इसलिये उसमें तो वैसे भी जो कार्य होता है और उसका संचालन होता है वह श्रमिकों के प्रतिनिधि ही करते हैं, और जो लोग सरकारी भी काम करते हैं वह भी एक प्रकार के श्रमिक होते हैं। ताहम केन्द्रीय सरकार ने कुछ अब नयी नीति इस विषय में निर्धारित की है। सरकार उस नीति को अपनाते हुये इस फैक्ट्री में वह सब चीजें लागू करेगी जो कि केंद्रीय सरकार ने अभी अपनी घोषणा में घोषित की है।

*१३—श्री नारायणदत्त तिवारी—[७ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

गवर्नमेंट सीमेंट फैक्टरी, मिर्जापुर के सम्बन्ध में पूछताछ

*१४—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बतायेगी कि गवर्नमेंट सीमेंट फैक्ट्री (मिर्जापुर जिला) अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है? यदि नहीं, तो क्या सरकार बतायेगी कि किस कानून के मातहत वह फैक्ट्री का संचालन कर रही है?

श्री बनारसीदास—फैक्ट्री की रजिस्ट्री के लिये अप्रैल, सन् १९५५ में फैक्ट्रियों के मुख्य निरीक्षक के पास कागज भेजे गये थे, किन्तु कुछ सामान्य आक्षेपों के कारण नियमानुसार लाइसेंस अभी तक प्राप्त नहीं हो सका। फैक्ट्री का कार्य फैक्ट्री ऐक्ट के अनुसार ही हो रहा है।

*१५—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार बतायेगी कि सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिये कितने क्वार्टर्स बने हैं?

श्री बनारसीदास—फैक्ट्री में कर्मचारियों तथा श्रमिकों के लिये ३२१ क्वार्टर्स बने हैं।

*१६—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार बतायेगी कि सीमेंट फैक्ट्री में जो पिछली हड़ताल हुई थी उसमें सरकार को कितना घाटा हुआ था?

श्री बनारसीदास—पिछली हड़ताल के कारण सरकार को लगभग १४,००० रुपये का घाटा हुआ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी बतायेंगे कि वह सामान्य आक्षेप क्या हैं जिनके आधार पर वह अब तक रजिस्टर्ड नहीं हुई?

श्री बनारसीदास—वह सामान्य का मतलब यह है कि टेक्निकल थोड़े बहुत आक्षेप थे, लेकिन वह आक्षेप रहे नहीं, पूरे कर दिये गये।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी बतायेंगे कि ३२९ क्वार्टर्स में कितने मजदूरों के हैं और कितने कर्मचारियों के?

श्री बनारसीदास—इसमें अलग तो इसका विवरण नहीं है। लेकिन करीब-करीब वहां पर जितनी स्ट्रेन्थ फैक्ट्री के अन्दर है उसमें ३५ फीसदी आदमियों के लिये क्वार्टर्स उपलब्ध है, और आगे कुछ इस वर्ष में चालू वर्ष में और कुछ अगले वर्ष में मंजूर किये गये हैं। बैचलर्स के लिये भी और-और लोगों के लिये भी क्वार्टर्स बनाये जा रहे हैं, और आशा यह की जाती है कि सब लोगों के लिये वहां शीघ्र ही क्वार्टर्स प्राप्त हो जायंगे।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी बतायेंगे कि वहां पर कितने दिन तक हड़ताल रही और उसमें कितने मजदूरों ने हिस्सा लिया और हड़ताल का क्या कारण था?

श्री बनारसीदास—हड़ताल का मुख्य कारण तो यही था कि जो एजीटेशन हो रहा था उसमें ८२ आदमियों को निकाला गया। उनका कहना यह था कि उनको रखा जाय। हड़ताल एक सप्ताह रही।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी जो हड़ताल के कारण क्षति हुई उसका विवरण बताने की कृपा करेंगे?

श्री बनारसीदास—लगभग १४ हजार रुपये का नुक्सान हुआ, क्योंकि वहां पर उत्पादन नहीं हो पाया। वैसे अगर इसमें वह भी शामिल करें कि जितना रुपया इस फैक्ट्री में लगा हुआ है उसका सूद और पुलिस को वहां अलग पोस्ट करना पड़ा, तो पुलिस विभाग का व्यय हुआ, और कुल एक लाख के करीब क्षति हो सकती है।

श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के श्रमिकों के क्वार्टर्स ऐसी जगह बने हुये हैं कि फैक्ट्री की कोल डस्ट क्वार्टर्स में जाती है जो उनके स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सही है कि जिस स्थान पर क्वार्टर्स बने हुये हैं उसी के नजदीक फैक्ट्री है और वहां पर कोल डस्ट जाती थी। लेकिन अब वहां पर एक स्क्रीनिंग वाल लगा दी गयी है जिससे अब वह नहीं जा सकेगी।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी बतायेंगे कि चुर्क में जो क्वार्टर्स बने हुये हैं वह कितनी कैटेगरीज के हैं और हरेक कैटेगरी का क्या मूल्य है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस समय तो सूचना नहीं दे सकता हूं। यदि आप नोटिस देंगे तो बता सकूंगा कि किस-किस क्लास के क्वार्टर में कितना-कितना व्यय हुआ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि पूंजीपति डालमियां इस फैक्ट्री का सफल संचालन न करने देने के लिये इंटेरेस्टेड हैं और ऐसा प्रयत्न भी करते रहते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हमारे पास कोई जाब्ते की शिकायत तो नहीं आई है, लेकिन कभी-कभी वह सज्जन जो हड़ताल आदि में जरा ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं वह इस प्रकार की बातें हमारे समक्ष आकर कहते हैं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो क्वार्टर बने हैं इनकी कुल लागत क्या है, और प्रत्येक क्वार्टर का क्या मूल्य है ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दिया जा चुका है।

जोया तथा नौगवां एन० ई० एस० ब्लाक, मुरादाबाद के कार्य

*१७—**श्री मुहम्मद तकी हादी** (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जोया एन० ई० एस० ब्लाक, मुरादाबाद में क्या-क्या कार्य अब तक हो चुके हैं ?

श्री बनारसीदास—इस ब्लाक में किये गये कामों की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १५६ पर)

*१८—**श्री मुहम्मद तकी हादी**—क्या सरकार बतायेगी कि नौगवां एन० ई० एस० ब्लाक, मुरादाबाद में कब तक काम शुरू हो जायेगा ?

श्री बनारसीदास—ब्लाक में काम शुरू हो चुका है, इसका हेडक्वार्टर अमरोहा रक्खा गया है।

श्री मुहम्मद तकी हादी—क्या मंत्री जी मेहरबानी करके बतलायेंगे कि इन ब्लाक्स में अब तक कुल कितना रुपया खर्च हो चुका है ?

श्री बनारसीदास—वैसे ये ब्लाक सन् ५४ में स्वीकृत किये गये थे, और एक ब्लाक के लिये पूरे कार्य काल के अन्दर करीब-करीब १ लाख रुपया होता है। तो जो काम किया गया है उसकी सूची तो आपको दे दी गयी है कि कितना रुपया अब तक व्यय हुआ। इसकी सूचना तो यदि माननीय सदस्य चाहें तो बाद में दी जा सकती है।

श्री मुहम्मद तकी हादी—क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतलायेगी कि इन ब्लाक्स को सरकार कब से इंटेसिव ब्लाक में तब्दील कर रही है ?

श्री बनारसीदास—इसी साल इस पर विचार किया जायगा ।

श्री रामदास आर्य—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि कौन-कौन से उद्योग-धंधे इस एन० ई० एस० ब्लाक में जारी किये गये हैं ?

श्री बनारसीदास—अभी तो नहीं, वैसे आई० डी० ब्लाक के अन्दर इसके लिये विशेष रूप से रखा जाता है ।

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि १५ लाख रुपये की रकम आई० डी० ब्लाक, कम्युनिटी प्रोजेक्ट और एन० ई० एस० ब्लाक के लिये है जिसमें करीब साढ़े ७ लाख रुपया वह होता है ।

श्री अध्यक्ष—वह १५ लाख नहीं साढ़े ७ लाख है ?

श्री बनारसीदास—जी हां ।

राज्य के एन० ई० एस० ब्लाक्स तथा कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स

*१९—**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के किस-किस जिले में कितने-कितने एन० ई० एस० ब्लाक्स व कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स हैं ?

श्री बनारसीदास—इसकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १५७–१६० पर)

*२०—**श्री रामचन्द्र विकल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २६ जनवरी, सन् ५६ को किस किस जिले में नये एन० ई० एस० ब्लाक्स व कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स खोले गये ?

श्री बनारसी दास—यह सूचना भी सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई सूची में मौजूद है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १५७–१६० पर)

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किसी जिले में पांच-पांच एन० ई० एस० ब्लाक्स और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स हैं, और किसी में एक, इसका मुख्य कारण क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पहले जब सामुदायिक विकास योजना स्थापित की गयी तो कुछ ऐसे स्थान छांटे गये जहां शिक्षा इत्यादि का प्रबन्ध अधिक उत्तमता से हो सकता था और जहां अधिक साधन उपलब्ध थे । और इसलिये किन्हीं-किन्हीं जिलों में पांच-पांच ब्लाक्स की स्थापना हो गयी । झांसी और इलाहाबाद ही ऐसे जिले हैं जहां पांच-पांच ब्लाक्स स्थापित हो चुके हैं और अन्य स्थानों में पांच-पांच नहीं हैं । पिछली मरतबा हमने इस बात की चेष्टा की कि तीन-तीन ब्लाक्स प्रत्येक जिले में हो जायं और उसी नीति की तहत में हम अब कार्य कर रहे हैं, और उनका वितरण अब इस हिसाब से कर रहे हैं कि जो नियोजन समितियां प्राथमिकता दे कर ब्लाक्स के संबंध में सिफारिश भेजती हैं उन्हीं को स्वीकार करके हम प्रत्येक जिले में उस संख्या के अनुपात में जो संख्या कि एक वर्ष के लिये इन ब्लाक्स को खोलने की निर्धारित की गई है उनका वितरण करेंगे ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन्हीं जिला प्लानिंग कमेटियों की सिफारिशों के विरुद्ध भी जिलों में एन० ई० एस० ब्लाक्स खोले गये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जब से मैंने यह कार्यभार संभाला है तब से तो कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि कोई ब्लाक जिला नियोजन समितियों की सिफारिशों के बावजूद भी किसी स्थान पर दिया गया हो।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी को यह भी विदित है कि जिलों के जो पिछड़े हुये भाग हैं और जिनका सर्वे कराया गया, सरकार की तरफ से उनको अभी तक एन० ई० एस० ब्लाक्स नहीं मिल पाये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--बहुत से ऐसे स्थान होंगे, लेकिन नियोजन समितियों से यह आशा की जाती है कि वे सारी बातों पर गौर करके इन ब्लाक्स के संबंध में अपनी सिफारिशें भेजेंगी।

श्री रामहेत सिंह--क्या मंत्री महोदय खासतौर से ऐसे क्षेत्रों के बारे में भी विचार करेंगे कि जहां हर साल बाहर से यात्री काफी तादाद में आते रहते हैं और जहां की हद दूसरे राज्यों से मिलने के कारण और भी खासियत रखती है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोई ऐसे आदेश गये हैं कि नये ब्लाक्स जो खुलेंगे उसमें तहसील हेडक्वार्टर्स को प्राथमिकता दी जायगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--ऐसे आदेश जरूर गये हैं कि किसी क्षेत्र में यदि ब्लाक खुले तो उसका केंद्रीय स्थान यदि तहसील का हेडक्वार्टर बनाया जा सके तो उसके बनाने का प्रबन्ध होना चाहिये, और वह इसलिये कि इन ब्लाक्स में कुछ मकानों के बनाने के लिये धनराशि रहती है। प्रदेशीय सरकार ने ऐसा महसूस किया कि तहसीलों के हेडक्वार्टर्स में यदि कुछ इमारतें बन जायं तो वह धनराशि जो कि उन ब्लाक्स की तहत में रहती है कदाचित ठीक तरह से उपयोग की जा सकेगी और उन तहसील हेडक्वार्टर्स में छोटे-छोटे टाउनशिप्स बन जायेंगे जिससे कि अपने अधिकारियों को स्थान देने की जो जिम्मेदारी सरकार की है उसमें भी कमी लायी जा सकेगी।

श्री रामकुमार शास्त्री--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सदन के समक्ष सूची उपस्थित है उसमें बस्ती में कितने एन० ई० एस० ब्लाक्स और कम्युनिटी प्रोजेक्टस खुले हैं और अल्मोड़े में कितने खुले हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--बस्ती में एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट खुला है और दो एन० ई० एस० ब्लाक्स खुले हैं, और अल्मोड़ा में दो कम्युनिटी प्रोजेक्टस और ४ एन० ई० एस० ब्लाक्स खुले हैं ?

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा में जो एन० ई० एस० ब्लाक्स की चर्चा की गई है उनमें से कोई रानीखेत नार्थ में खुले हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह तो मुझे मालूम नहीं है कि मदनमोहन जी उपाध्याय की कांस्टीटुएंसी में कोई ब्लाक खुला है या नहीं, लेकिन यह सही है कि यह नियोजन समिति की सिफारिश के अनुसार खुलते हैं। किस क्षेत्र में खुले हैं और किस में नहीं खुले हैं, यह व्याख्या इस समय मेरे सामने नहीं है।

अल्मोड़ा जिले में औषधालयों की संख्या बढ़ाने की मांग

*२१--**श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट**--क्या सरकार यह बतलायेगी कि इस समय अल्मोड़ा जिले में कितने आयुर्वेदिक तथा एलोपैथिक औषधालय हैं और वे कहां-कहां हैं ?

श्री बनारसीदास--सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १६१ पर)

*२२--**श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट**--क्या सरकार की नीति पर्वतीय जिलों में भी ५ मील की दूरी पर औषधालय स्थापित करने की है? यदि हां, तो यह कब तक कार्यान्वित हो सकेगी?

श्री बनारसीदास--जी हां। आशा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक प्रायः सभी जिलों में ५ मील की दूरी पर चिकित्सालय स्थापित किये जा सकेंगे।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि पर्वतीय इलाकों में ऐसे स्थान हैं जहां २०-२० मील तक किसी औषधालय की व्यवस्था नहीं है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या मंत्री जी पूर्वी जिले अल्मोड़ा में दो आयुर्वेदिक और एलोपैथिक अस्पताल खोलने का वायदा कर चुके हैं वह कब तक कार्यान्वित हो जायगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस वर्ष तो अल्मोड़ा में चार अस्पताल खोले जा चुके हैं, कौसानी में एक, बाराछीना में एक, धारा चुल में एक और तेजम में एक। आपके जिले में यदि ५ मील के दायरे में एक अस्पताल खुलने वाली स्कीम को माने तो ६९ अस्पताल खुलने चाहिये और ५१ खुल चुके हैं। जैसे-जैसे हमारे यहां की स्वास्थ्य योजना बढ़ती जायगी त्यों-त्यों ५ मील के दायरे में जहां-जहां अस्पतालों की आवश्यकता होगी वह खुलते जायेंगे।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अल्मोड़े के बारे में उन्होंने पश्चिमी जिले अल्मोड़ा का जिक्र किया। उन्होंने चम्पावत, वाराकोट, गुरना और ओड्टा में जो अस्पताल खोलने का वायदा किया था उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मेरा वायदा जो है वह इस योजना के तहत में अवश्य पूरा किया जायगा जिसका वर्णन मैंने किया है। जो खास अस्पताल या स्थानों का जिक्र किया जाता है उनके ऊपर अगले वर्ष विचार किया जायगा, और जो अस्पताल खुले हैं वह उस क्षेत्र में खुले हैं जहां कि बहुत दूर तक अस्पताल स्थित नहीं है।

श्री रामेश्वरलाल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि अल्मोड़ा के मदनमोहन उपाध्याय जी के क्षेत्र में कोई भी अस्पताल नहीं खोला गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--औषधालय किसी माननीय सदस्य की कांस्टीटुएंसी के लिये नहीं खोले जाते हैं बल्कि आवश्यकता देखकर खोले जाते हैं। और किस क्षेत्र में कितनी दूर पर आने जाने के साधन उपलब्ध हैं या नहीं, इसको देखकर खोले जाते हैं।

गोरखपुर जिले के हड़हाघाट में आबकारी पुलिस द्वारा गांजा पकड़ा जाना

*२३--**श्री जोरावर वर्मा**--क्या सरकार को मालूम है कि नौतनवां से ४ मील दूर हड़हाघाट, जिला गोरखपुर में आबकारी पुलिस ने लगभग ६ मन नाजायज गांजा पकड़ा है?

मादक-कर मंत्री (श्री गिरधारीलाल)--जी हां।

*२४--**श्री जोरावर वर्मा**--क्या सरकार बतायेगी कि इस संबंध में कितने व्यक्ति पकड़े गये हैं और वे कहां-कहां के हैं?

श्री गिरधारीलाल--इस संबंध में कुल १५ व्यक्ति पकड़े गये थे। इसमें से ८ व्यक्ति ग्राम शम्भूपुर, जिला बस्ती, थाना छावनी के, ३ व्यक्ति ग्राम बेतहा, जिला बस्ती, थाना

छावनी के, १ व्यक्ति ग्राम मच्छा, थाना परसरामपुर, १ व्यक्ति ग्राम लकरी, थाना दावानी, १ व्यक्ति ग्राम मलाला थाना छावनी, १ व्यक्ति ग्राम सौरी थाना छावनी के रहने वाले रिपोर्ट किये गये हैं।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस गांजे की क्या कीमत आंकी गई है या वास्तव में है ?

श्री गिरधारीलाल—इसकी तो अभी मुझे कोई इत्तला नहीं है।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि क्या यह सही है कि यह गांजा नैपाल से लाया जा रहा था ? और यदि हां, तो क्या सरकार ने नैपाल सरकार को इस संबंध में कुछ लिखा है ?

श्री गिरधारीलाल—यह प्रश्न अभी कोर्ट में है, इसलिये अभी उन सवालों का जवाब देना ठीक न होगा।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या इस प्रकार का कोई अन्तर प्रांतीय गिरोह है जो इस प्रकार की नाजायज चीजों का व्यापार करता है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—इस किस्म का गिरोह हो सकता है, और जहां-जहां ऐसे गिरोह पकड़ में आते हैं उनको पकड़ कर उनका चालान किया जाता है, उन गिरोहों को तोड़ने की कोशिश भी की जाती है।

हमीरपुर जिले में प्लानिंग विभाग द्वारा व्यय में असावधानी

*२५—**श्री जोरावर वर्मा**—क्या सरकार बतायेगी कि हमीरपुर जिले में प्लानिंग विभाग द्वारा कुल कितना कितना रुपया सन् १९५४–५५ में किस-किस मद पर खर्च किया गया, और कितना हर मद में बच गया है और क्यों ?

श्री बनारसीदास—सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १६२–१६३ पर)

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह भी था कि कुछ बचा है ? अगर बचा है तो उसका कारण क्या है ?

श्री बनारसीदास—इसकी तो वजह यह है कि आमतौर से गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से जो ग्रान्ट्स मिलती हैं वह काफी देर में मिलती हैं, इसलिये सप्लीमेंटरी बजट के बाद ही उनको दिया जा सकता है, इसलिये बाकी रह जाता है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या यह सच है कि इसको देखने से मालूम पड़ता है कि सन् १९५३–५४ का जो बैलेंस था वह भी सन् १९५४–५५ में खर्च नहीं किया गया है, क्रम संख्या ३,४,७ और ८ से ऐसा प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास—वह तो मैंने अभी निवेदन किया, क्योंकि बाद में सूचना मिलती है तो इस वक्त के बैलेंस को उसके पर्सनल लेजर के अन्दर भेज देते हैं।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह रुपया जो खर्च होने के लिये रहता है प्लानिंग कमेटीज में, और जो खर्च नहीं होता वह इसलिये भी नहीं हो पाता है कि राज्य सरकार की ओर से इंफारमेशन जल्दी नहीं पहुंचती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—राज्य सरकार की ओर से, जैसा कि अभी सचिव ने बताया कि कभी-कभी केंद्रीय सरकार से आदेश देर में आते हैं और जब देर में आदेश आते हैं तो वह धनराशि भी वहां देर में पहुंचती है, और जब तक सरकार से धन नहीं आ जाता है तब तक यदि कोई योजना

जिले से बन कर आती है और उसमें धन न आने की वजह से कोई आपत्ति होती है तो उसमें देरी अवश्य हो जाती है।

तीन से अधिक राष्ट्रीय प्रसार सेवा केन्द्र वाले जिले

*२६—श्री अनन्तस्वरूप सिंह (जिला फतेहपुर)—क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के किन-किन जिलों में तीन या उससे अधिक राष्ट्रीय प्रसार सेवा केंद्र खोले जा चुके हैं ?

श्री बनारसीदास—ऐसे जिलों की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १६४–१६६ पर)

इन्टेंसिव ब्लाक वाले राष्ट्रीय प्रसार सेवा केन्द्र

*२७—श्री अनन्तस्वरूप सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य के किसी जिले का कोई राष्ट्रीय प्रसार सेवा केंद्र Intensive Block अभी तक बनाया गया है या नहीं ?

श्री बनारसीदास—राष्ट्रीय प्रसार सेवा केंद्र, इन्टेंसिव ब्लाक बनाये जा चुके हैं। इन का ब्योरा सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई सूची में है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १६४–१६६ पर)

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जितने भी एन० ई० एस० ब्लाक्स प्रदेश के अन्दर खोले जायेंगे उनकी एक सूची बन कर तैयार हो गई है और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज को यह आदेश दे दिये गये हैं कि उन सब ब्लाक्स में शैडो ब्लाक के रूप में काम किया जाय और ३०-३० हजार रुपया ब्लाक को दिया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूची तो अभी कतई कोई नहीं बनी है, लेकिन यह अवश्य आदेश जिला प्लानिंग समिति को गया है कि किन-किन ब्लाक्स को प्राथमिकता देना चाहते हैं। जिनको प्राथमिकता देना चाहते हैं उनमें अवश्य कुछ कार्य आरम्भ कर दिया जाय जिससे जब ब्लाक्स सैंक्शन हो तो वहां पर कार्य उत्साह और उमंग के साथ होने लगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने का कष्ट करेंगे कि अगर सूची लम्बी हो तो प्रदेश में कितने इन्टेंसिव ब्लाक्स हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पहले तो २६ कम्युनिटी प्रोजेक्ट थे। इस साल हमने २८ इंटेंसिव ब्लाक्स इसी जनवरी से खोले हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस नये वर्ष में कितने और नये इंटेंसिव ब्लाक्स सरकार का खोलने का इरादा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस वर्ष तो नहीं, किन्तु अगले वर्ष २५-२६ इंटेंसिव ब्लाक्स और ९९ एन० ई० एस० ब्लाक्स खुलेंगे।

*२८–३०—श्री रामसुमेर (जिला फैजाबाद)—[२१ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

फतेहपुर जिला प्लानिंग कमेटी को विकास कार्यों के लिए स्वीकृत धन न मिलने की शिकायत

*३१—**श्री अनन्तस्वरूप सिंह**—क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला फतेहपुर में जिला प्लानिंग कमेटी द्वारा विकास कार्यों के लिये जो रुपया ६ मास से अधिक हुये स्वीकृत हुआ था उसका विवरण इसलिये अभी तक नहीं हो पाया कि अभी वितरण एवं स्वीकृति का Sanction सरकार द्वारा नहीं दी जा सकी है ।

श्री बनारसीदास—जी नहीं। स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

*३२-३३—**श्री वासुदेवप्रसाद मिश्र** (जिला कानपुर)—[४ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

करघों का रजिस्ट्रेशन

*३४—**श्री बशीर अहमद हकीम** (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में किन-किन जिलों में करघों के रजिस्ट्रेशन का काम चालू है और वहां कितना काम हो चुका है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—राज्य के समस्त जिलों में हाथ करघों के रजिस्ट्रेशन का काम चालू है। १० फरवरी, १९५६ तक कुल १८,६४६ हाथ करघे रजिस्टर हो चुके हैं।

*३५—**श्री बशीर अहमद हकीम** (अनुपस्थित)—यह काम सरकार के जिस आदेश के अनुसार चल रहा है वह क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह कार्य उत्तर प्रदेश हैन्डलूम रजिस्ट्रेशन आर्डर, १९५५ के अनुसार चल रहा है ।

झांसी जिले में कूप-निर्माणार्थ सहायता

*३६—**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला झांसी में तीन सालों के अन्दर कितने कुओं की सबसिडी मंजूर की गई और उनमें से कितने रुपयों का भुगतान हो गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त जिले में १९५१-५२ से १९५३-५४ तक जितने कुओं की सब्सीडी मंजूर की गई तथा जितने रुपयों का भुगतान हो गया है वह इस प्रकार है :—

वर्ष	सबसिडी के लिये स्वीकृत कुओं की संख्या	सबसिडी की धनराशि जिसका भुगतान हो चुका है रु०	आ०	पा०
१९५१-५२ ..	२४	४,७४४	०	०
१९५२-५३ ..	५०	१२,७०४	०	०
१९५३-५४ ..	२०२	४१,५९६	८	०
कुल	२७६	५९,०४४	८	०

श्री गज्जूराम—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि २७६ कुओं में जो यह ६९,०४४ रु० दिया गया है यह सबसिडी मंजूरी की गई है या भुगतान किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सूची में दिया हुआ है कि सबसिडी की धनराशि जिसका भुगतान हो चुका है।

श्री गज्जूराम—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि २७६ जो कुयें हैं इनमें सबसिडी कितनी मंजूर की गई है ?

श्री बनारसीदास—यह तमाम इन सालों का विवरण दिया गया है वह भिन्न-भिन्न प्रकार से दिया गया है। सबसे पहले सन् १९५० में ५०० रुपया प्रत्येक कुयें के हिसाब से देते थे। बाद में उसको ४०० रुपया कर दिया, और बाद में रोक दिया। फिर इसको घटाकर ३०० कर दिया, और अब भी इसके अतिरिक्त ऐसा है कि जिसको सब प्रकार से सबसिडी मिलती है वह एक बटा तीन के हिसाब से मिलती है। इसमें कुल इसका विवरण है।

श्री गज्जूराम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि २७६ कुयें जो मंजूर हुये हैं। इन कुओं में और भी रकम अदा करना है ?

श्री बनारसीदास—यह उन कुओं का जिकर किया गया है जिनको देख लिया गया है और जिन्होंने नियम के अनुसार सारा रुपया व्यय किया है, यह तो उनका जिकर है। बाकी कुओं के अन्दर ऐसे कुयें भी जरूर हैं जो बन चुके हैं, लेकिन अभी उनकी पूरी रिपोर्ट नहीं आयी है, उसकी सूचना इसमें शामिल नहीं है।

रामपुर रियासत के कारखानों की खराब हालत

*३७—**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि विलयन के पहले रियासत रामपुर में कितनी फैक्टरियां कौन-कौन से पन्य (कमोडिटी) पैदा करती थी ?

श्री बनारसीदास—विलयन के पूर्व रियासत रामपुर में लगभग १९ फैक्टरियां तथा औद्योगिक कम्पनियां थीं जिनमें रामपुर राज्य का आर्थिक साझा था।

यह संस्थायें युद्धकाल में अनेक वस्तुओं का उत्पादन कर रही थीं, जैसे इंजीनियरिंग का सामान, बच्चों की तीन पहिये वाली गाड़ियां, साइकिल के पुरजे, मुद्रण सामग्री, माडी (स्टार्च) तेल, अनाज, कपास, साबुन, आदि कोल्ड स्टोरेज, कपड़े, धातु की वस्तुयें (मेटलवेयर), कृषि तथा दुग्धशाला, शराब तथा परिशोधित स्प्रिट, यातायात का कार्य, चीनी, बर्फ, दियासलाई, चमड़ा कमाना तथा जूते बनाना, बनस्पति, लकड़ी तथा खराद का कार्य इत्यादि।

युद्धोपरान्त और विशेषतः विलयन के समय अधिकांश कारखानों की दशा बिगड़ चुकी थी और अनेक कारखाने बन्द हो चुके थे। जो कारखाने चल रहे थे उनकी स्थिति भी संतोषप्रद न थी और वे भीषण आर्थिक कठिनाइयों तथा बाजार की मंदी के शिकार थे।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो कारखाने आर्थिक संकट में पड़ गये थे उन्हें संभालने के लिये सरकार ने कोई उपाय किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार ने अवश्य इस बात की चेष्टा की थी कि जो लोग उन विषयों की जानकारी रखते हैं या जो उद्योग-धंधों में लगे हुये हैं वे उन्हें चलावें, परन्तु मंदी के कारण कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया और इसलिये जो कारखाने मंदी के कारण खत्म से हो चुके थे वे चलाये नहीं जा सके।

श्री उमाशंकर—क्या यह सच है कि इन १९ कारखानों में से कुछ को रामपुर से हटाकर और जगह स्थापित किया जा रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी तक तो किसी कारखाने को हटाने का निर्णय नहीं लिया गया है। एक शुगर फैक्ट्री के बारे में ऐसी बातचीत रही है। केंद्रीय सरकार उस फैक्ट्री

को उत्तर प्रदेश से बाहर ले जाने की इजाजत दे रही थी, और उसका लाइसेंस प्रदान कर रही थी। उस समय प्रदेशीय सरकार और मिल मालिकों से बातें हुई जो कि उसे मैसूर या और किसी स्थान पर ले जाना चाहते थे, और उनसे बातचीत का निष्कर्ष यह निकला कि यदि केंद्रीय सरकार उत्तर प्रदेश में ही किसी स्थान पर ले जाने का लाइसेंस देगी तो वह उस कारखाने को उत्तर प्रदेश में ही रखेंगे। इस विषय में भी अब प्रदेश की सरकार ने कुछ ऐसा सुझाव दिया है जिससे कदाचित यह कारखाना यहां से उठ कर दूसरी जगह नहीं जायगा।

श्री उमाशंकर—आजकल रामपुर में कौन-कौन से कारखाने चल रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—२ शुगर फैक्ट्रियां, एक इंजीनियरिंग का कारखाना, एक मेज का कारखाना भी है जो कि अभी तक बन्द पड़ा था और वह चलने वाला है। ज्वाला फ़ैब्रिक्स रामपुर बनस्पति, और एक आइस कोल्ड स्टोरेज और रामपुर टैनरी और टिम्बर का कारखाना है।

श्री उमाशंकर—रामपुर में चीनी के कारखाने क्या घाटे में चल रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—एक के विषय में ऐसा बताया गया है कि वह घाटे में चल रही थी क्योंकि काफी मात्रा में गन्ना नहीं मिलता था। परन्तु पिछले वर्ष से गन्ना पूरी मात्रा में मिल रहा है और घाटे का अब कोई प्रश्न नहीं है।

*३८-३९—**श्री उमाशंकर**—[१४ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

बिजनौर जिले के सरकारी जनाना अस्पताल की शोचनीय दशा

*४०—**श्रीमती चन्द्रवती** (जिला बिजनौर)—क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जिला बिजनौर के सरकारी जनाना अस्पताल की दशा बहुत ही शोचनीय है और वहां मरीजों के लिये बेड्स और कर्मचारियों के लिये रहने के स्थान की भारी कमी है ?

श्री बनारसीदास—जी हां।

*४१—**श्रीमती चन्द्रवती**—यदि हां, तो क्या स्वास्थ्य मंत्री उक्त अस्पताल की दशा सुधारने के लिये शीघ्र ही कोई प्रबन्ध करने पर विचार करेंगे।

श्री बनारसीदास—राजकीय महिला चिकित्सालय, बिजनौर में निम्नलिखित सुधार किये जा रहे हैं :

(१) कुछ equipment अस्पताल के काम के लिये इस साल दिया जा रहा है।

(२) औषधियों की वार्षिक ग्रांट वर्तमान आर्थिक वर्ष १९५५-५६ में १,७०० से बढ़ाकर २,५०० रु० कर दी गई।

आर्थिक वर्ष (१९५६-५७) में निम्नलिखित प्रगति होने की आशा है :

(१) सारे अस्पताल की विशेष मरम्मत।

(२) दो प्राइवेट वार्डों तथा दो नर्सेज क्वार्ट्र्स का निर्माण।

(३) अस्पताल कर्मचारियों के लिये नये क्वार्टर्स का निर्माण।

(४) आठ बिजली के पंखे दिये जायेंगे।

(५) वर्तमान शैयाओं में वृद्धि।

श्रीमती चन्द्रवती—क्या माननीय मंत्री इस बात को बतलायेंगे कि बिजनौर में महिला चिकित्सालय और मरदाने अस्पताल को एक में मिलाकर बनाने की योजना सामने है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पहले ऐसा विचार हुआ था लेकिन स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं में कुछ कमी की गई। इसलिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई ऐसी बात नहीं है जिसके तहत में हम इन दोनों अस्पतालों को कम्बाइन्ड रूप में निर्मित कर सकें।

श्रीमती चन्द्रवती—क्या आगामी वर्ष में कुछ और जनाने अस्पताल खोलने की योजना सरकार के सामने है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आगामी योजना में ६५ अस्पताल खुलेंगे, कदाचित १३ अस्पताल अगले वर्ष खुलेंगे ।

बिजनौर जिले में जनाने अस्पतालों की संख्या बढ़ाने की मांग

*४२—**श्रीमती चन्द्रवती**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिजनौर जिले में कुल कितने जनाने अस्पताल हैं ?

श्री बनारसीदास—बिजनौर जिले में कुल ५ जनाना अस्पताल हैं ।

श्रीमती चन्द्रवती—क्या आगामी वर्ष में कुछ और जनाना अस्पताल खोलने की योजना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—एक शायद हल्दौर में खुलने को है ।

श्रीमती चन्द्रवती—वह क्या जनता की सहायता से है या पूरा व्यय-भार राजकीय कोष से होगा ?

श्री बनारसीदास—जिला बोर्ड द्वारा उसके भवन का निर्माण हो रहा है, और फिर सरकार उसे लेने पर विचार करेगी ।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या सरकार नगर पालिकाओं के अन्य स्थानों में जहां जनाने अस्पताल नहीं हैं, वहां खोलने पर विचार करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अगली योजना में शायद सभी नगरपालिकाओं में तो नहीं खोले जा सकेंगे ?

श्री रामकुमार शास्त्री—जो जनाना अस्पताल बिजनौर में सदर मुकाम पर है उसमें कितने बेड्स हैं ?

श्री बनारसीदास—१४ बेड्स हैं ।

*४३–४५—**श्री श्रीचन्द्र**—[४ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

अतारांकित प्रश्न

फर्रुखाबाद जिले में श्रमदान द्वारा निर्मित सड़क को पक्की करने की योजना

१—**श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी** (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बतायेगी कि फर्रुखाबाद जिले में श्रमदान द्वारा निर्मित सबसे लम्बी सड़क कौन-सी है जिसको सरकार की सहायता से पक्का बनाने की योजना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—खिमसेपुर-धीरपुर सड़क ।

सदन में लोहे और पत्थर के टुकड़े बांध कर लाये जाने पर व्यवस्था

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि क्या किसी माननीय सदस्य के लिये यह उचित है कि वह सदन में पत्थर और लोहे के टुकड़े बांध कर लाये ? यह श्री ब्रजभूषण मिश्र बांध कर लाये हैं । (सदस्य महोदय ने पोटली दिखाई ।)

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं यह उचित नहीं है लेकिन अगर वह गुप्त रीति से रखे थे और बदनियती से नहीं रखे थे तो कोई विशेष चिन्ता की बात नहीं है।

श्री व्रज भूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---अध्यक्ष महोदय, कोई गलत बात न समझ ली जाय इसलिये मैं बता दूं कि अभी हाल में मुझे घूमते हुये जो खनिज-पदार्थ के टुकड़े मिले थे वही मैं यहां दिखाने के लिये ले आया था।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, किसी को उनसे कोई खतरा नहीं था।

शनिवार, ३ मार्च, १९५६ को सदन की बैठक करने के सम्बन्ध में संकल्प (संशोधित रूप में स्वीकृत)

श्री अध्यक्ष---जो प्रस्ताव कल उपस्थित हो चुका है और आज उसके बारे में निर्णय होना था। वह क्या आपस में तय हो गया ?

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कल कहा था कि एक शनिवार का दिन होगा यह तो निश्चित ही है, अब चूंकि पहला शनिवार ३ तारीख को पड़ता है उस के विषय में मैंने दूसरे दलों के लोगों से भी बातचीत की है और हम लोगों की यही राय है कि ३ को न रखा जाय और फिर १० की बात आई तो मालूम हुआ कि १० को तो शिवरात्रि की छुट्टी है। इसलिये अगर सरकार को कोई विशेष असुविधा न हो तो १७ तारीख को जो शनिवार पड़ता है उस दिन के लिये रख लिया जाय। कांग्रेस के भी बहुत से भाई कहते थे कि ३ तारीख सूट नहीं करती इसलिये १७ तारीख को ही रखने में सब को सुविधा होगी और किसी को तकलीफ न होगी और अगर कोई ज्यादा मजबूरी हो तो जैसा सरकार उचित समझे करे।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---हमने ३ तारीख को इसीलिये अख्तयार किया था कि आगे की किसी तारीख के लेने में बहुत सी तब्दीलियां करनी पड़ती थीं और यह तारीख इसलिये रखी थी कि अगर इस रोज बैठक हो जायगी तो आगे का प्रोग्राम वैसे ही चल जायगा जैसे कि वह कायम हुआ है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि जैसा मदन मोहन जी ने कहा कि ३ तारीख को तो हम सब लोग पहले से ही अपने दूसरे प्रोग्रामों में एन्गेज हैं और १६ को कोई प्रोग्राम होगा भी तो उसको हटाने की व्यवस्था अभी से की जा सकती है इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर मंत्री जी १७ को ही रख लें तो सुविधा होगी। जो ३ के लिए प्रोग्राम है उसी को १७ के लिए बदल दिया जाय तो मुनासिब होगा। अगर १७ को कोई प्रोग्राम सरकार की ओर से हो या हमारा कोई प्रोग्राम है तो उसको अभी समय है बदला जा सकता है और ३ को तो हमें बड़ी असुविधा होगी।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय तीन तारीख की जगह पर १७ तारीख का सुझाव स्वीकार कर लें क्योंकि तीन को हम लोगों के भी बहुत से प्रोग्राम बने हुये हैं।

श्री श्यामलाल (जिला गोंडा)---अध्यक्ष महोदय, तीन तारीख में एक बात और भी है। क्योंकि दूसरे शनिवार को छुट्टी पड़ती है और आगे का होली का त्योहार है, पैसे की जरूरत है इसलिये जरूरी है कि तीन तारीख को हटा दिया जाय।

श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी वित्त मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि क्योंकि हाउस का सुझाव ज्यादातर १७ के लिये है, १० तारीख को सरकार का भी प्रोग्राम है और छुट्टी भी है, इसलिये जिन लोगों के प्रोग्राम

[श्रीमती चन्द्रवती]

तीन तारीख को बन चुके हैं उनके लिये बड़ी असुविधा रहेगी। १७ तारीख को कोई बाधा भी नहीं रहेगी।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—तो दोबारा इसमें संशोधन कर लिया जय कि पहले और दूसरे शनिवार को छोड़ कर कोई और शनिवार रख लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—(श्री मदन मोहन उपाध्याय से) आप संशोधन कर दें और (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम से) आप उसे स्वीकार कर लें।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं इसलिये अर्ज करता हूं कि इस वक्त जब तक यह बात शुरू नहीं हुई थी मेरे इल्म में यह था कि आपने यह मंजूर कर लिया है और इस वजह से मैंने प्रोग्राम को इस नजर से नहीं देखा है। अब जहां तक मुमकिन होगा १७ ही को कर दूंगा अगर किसी वजह से कोई ऐसी सूरत आ पड़े और उसे करना पड़े तो उस वक्त आसानी रहेगी।

श्री अध्यक्ष—तो बात यह है कि संकल्प तो अब रखा यों ही नहीं रह सकता। कोई संकल्प ऐसा लटका तो नहीं रह सकता। संकल्प है, होना ही होगा अगर उसको बदलने की आवश्यकता होगी तो फिर दुबारा बदल सकते हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—ठीक है फिर तीन के बजाय १७ इसमें कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं संशोधित रूप में उसे लिये लेता हूं।

"प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ११(२) के अनुसार शनिवार को विधान सभा की बैठक नहीं होती तथापि १९५६–५७ के आय-व्ययक एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) को ३१ मार्च, १९५६ के पूर्व पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह संकल्प किया जाता है कि सदन की बैठक अपने नियत समय पर शनिवार तारीख १७ मार्च, १९५६, को भी होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब इसका परिणाम जो होगा उसकी सूचना मैं सदन को दे दूंगा।

१ मार्च, १९५६ को कार्य सूची में "प्रश्नोत्तर" न रखने का सुझाव

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—श्रीमन्, मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूं कि बहुत से लोग आम बजट के विवाद में हिस्सा लेना चाहते हैं इसलिये कल क्वेश्चन आवर का एक घंटा अर्थात् कल क्वेश्चन्स न लिये जायं उसके बजाय जेनरल डिबेट हो।

श्री अध्यक्ष—इसमें किसी को कोई आपत्ति है?

(नहीं की आवाजें)

तो यह हो जायगा प्रश्न नहीं लिये जायंगे।

१९५६–५७ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—अध्यक्ष महोदय, जब मैं कल बोल रहा था तो ट्रेजरी बेंच की तरफ से शायद माननीय गुप्त जी ने कहा कि अब समाजवाद के बाद शायद लोहियावाद का नारा लगायें। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सोशलिस्ट पार्टी में किसी व्यक्तिवाद की गुंजायश नहीं है इसलिये वहां लोहियावाद जैसी कोई चीज नहीं है यह तो कांग्रेस पार्टी की परम्परा है जहां व्यक्तिवाद हो सकता है। फिर भी मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस सरकार या उसके मंत्रिगण सोशलिस्ट पार्टी की बढ़ती हुई ताकत और डाक्टर

लोहिया के बढ़ते हुये जोर को देख कर यह कह सकते हैं कि अब लोहियावाद अपनावेंगे। मालूम होता है कि रात को मंत्रीगण ने आप को ट्रेनिंग दी है शोर करने की.....

श्री अध्यक्ष––आपका कोई आक्षेप हो तो मेरा ध्यान आकर्षित कर के कहें, सीधे उन लोगों से बातचीत न करें।

श्री रामसेवक यादव––माननीय अध्यक्ष महोदय, कल श्री गेंदा सिंह जी ने अपनी दौराने तकरीर में फरमाया कि उन्हें कुछ आशा थी कि बजट में समाजवादी झलक मिलेगी, लेकिन बजट के पढ़ने से मालूम हुआ कि इसमें कुछ नहीं, निराशा ही निराशा है। अध्यक्ष महोदय, यह तो गेंदा सिंह जी का खयाल था। जहां तक सोशलिस्ट पार्टी और हम लोगों का ख्याल है हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इसमें समाजवाद मिलेगा तो निराशा का प्रश्न ही हम लोगों के लिये नहीं था। मैंने बाराबंकी के चुनाव में मंत्रियों का रवैया देखा है खास कर डा० सीताराम जी ने.....

श्री अध्यक्ष––मैं समझता हूं कि असंगत हो रहा है। आप बजट पर भाषण दे रहे हैं। चुनाव का जिक्र यहां नहीं आना चाहिये।

श्री रामसेवक यादव––समाजवाद शब्द का बजट में बहुतायत के साथ जिक्र किया गया है, लेकिन सीताराम जी ने बाराबंकी में चुनाव के समय फरमाया था कि हमारे यहां तो समाजवाद आ ही नहीं सकता और कांग्रेस के मेनिफेस्टो में समाजवाद का जिक्र है। यह तो समाजवाद नहीं धोकावाद है समाजवाद का क्या अर्थ होता है? समाजवाद वह है जिससे गरीबी को दूर किया जाय, उपज के साधनों पर, ––रोजी रोटी के साधनों पर आम जनता का अधिकार हो, सम्पत्ति का बटवारा हो, राजनैतिक सत्ता का विकेन्द्रीयकरण हो। अगर इस कसौटी पर इस समाजवादी बजट को कसते हैं तो यह बजट खरा नहीं उतरता। इसमें समाजवाद की कहीं गुंजायश नहीं। न कहीं इसमें कम तनख्वाह पाने वालों की तनख्वाह बढ़ाने का जिक्र है। सेक्रेटेरियट में जहां कि चपरासी लोग रात दिन मंत्रियों की सेवा करते हैं कहीं उनकी तनख्वाह बढ़ाने का जिक्र नहीं। हम लोग पुलिस की बहुत निन्दा किया करते हैं लेकिन साथ-साथ हम यह भी सोचते हैं कि वे ईमानदार हों तो उनकी तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत है। चौकीदार जिसकी तनख्वाह ५ रुपये है उसकी तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं किया गया। या कांस्टेबिलान जो तनख्वाह कम पाते हैं उनकी तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं किया गया। तो किस तरह से यह समाजवादी बजट हो सकता है।

भूमि के सम्बन्ध में हमारे मंत्रिगण और कांग्रेस के सब लोग बिनोवा भावे के पद चिन्हों पर चलने की प्रतिज्ञा करते हैं और कहते हैं कि भूमि का वितरण होना चाहिये, लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जमीन का वितरण क्यों नहीं करते? एक जगह जिक्र किया गया कि कांग्रेस सरकार ने जमींदारी खत्म करके इन्कलाबी क़दम उठाया है जो समाजवाद की तरफ ले जायगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि एक कोटेशन आपके सामने रखूं जो डाल्टन साहब ने फरमाया था: "If the terms of tenancy are the same it makes no substantial difference to a tenant whether his landlord is a public authority or a private person." जमींदारी के खात्मे से किसान का क्या फायदा हुआ? कितना लगान घटा, कितने हरिजनों को जमीन दी गई? हरिजनों के लिये ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से हरिजन सदस्यों के द्वारा कहा जाता है और बैकवर्ड क्लासेज के लिये कहा जाता है। मगर कितनी जमीनें हरिजन परिवारों को या बैकवर्ड क्लासेज को मिली? यह जमींदारी कानून कितना प्रतिक्रियावादी कानून है, यह इससे जाहिर है जिसमें यह कोशिश की गई है कि किसानों को किसानों

[श्री रामसेवक यादव]

से लड़ाया जाय। आखिर इस समाजवादी युग में यह भूमिधर, सीरदार और अधिवासी ये तीन प्रकार के किसान कहां से आते हैं? आप तो समानता और समता की बराबर बात करते हैं लेकिन उसकी इसमें कोई झलक नहीं आती है। आपके इस समाजवादी बजट में बड़ी डींग हांकी गई है पंचवर्षीय योजना की कि पंचसाला योजना हमारी सफल हुई। अब दूसरी पंच वर्षीय योजना शुरू होने जा रही है। उसके पूरा होते ही सारे देश में सुख और शांति का साम्राज्य स्थापित हो जायगा। अगर आप पंच-वर्षीय योजना के सही रूप को देखें, जानने की कोशिश करें, कागज के स्टैटिस्टिक्स को नहीं कहता हूं। देहात की तरफ जायं असलियत को देखें, तो मालूम होगा कि इस पंच-वर्षीय योजना से किसी तरह की कोई तरक्की नहीं हुई है। कुछ अस्पताल बन गये होंगे, एक आध सड़क बन गयी होंगी, कुछ डैम बन गये होंगे। अगर इसको समाज की प्रगति कहा जाय तो शायद अंग्रेजों के जमाने में भी सड़कें बनी हैं, स्कूल खुले हैं, रेलवे लाइन बनी है, तो वह समाजवाद हो सकता था। क्या जरूरत थी कि अंग्रेज जायं यहां से? लेकिन समाजवाद का अर्थ दूसरा है और वह यह कि रोजी, रोटी के साधनों पर समाज का अधिकार होना चाहिये और जब हम बजट को देखते हैं, तो उसमें इशारा मात्र भी नहीं है, कदम तो दूर रहा। दूसरी पंच-वर्षीय योजना में माननीय वित्त मंत्री ने स्वयं अपनी स्पीच में यह कहा है कि हमारे पास कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, हमारे पास कोई तथ्य नहीं है कि कितने लोग बेकार हैं, कितने खेतिहर मजदूर हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने अनपढ़ लोग हैं, कितने टेक्नीशियंस बेकार हैं? तो कैसी प्लानिंग, भाई? आपके पास कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है, कितने लोगों को खेती पर बसाएंगे, कितने लोगों को नौकरियां देंगे, कितने को कारखानों में लगायेंगे यह कोई प्लान नहीं है। अगर इसको प्लान की संज्ञा दी जा सकती है तो यही कहा जा सकता है कि यह मिनिस्टर्स फैमिली प्लान है, कुछ विशेष लोगों को खपाने की बात होगी। इससे न देश आगे बढ़ेगा, न बढ़ा है। फूड प्राबलम के बारे में बड़ी खुशी मनायी जाती है कि सेल्फ सफीशेंसी हो गयी है। समस्या दरअसल क्या है? जितने स्टैटिस्टिक्स आपके पास हैं, कि उपज बढ़ गयी है, वह असलियत से दूर हैं। मान लिया कि उपज कुछ बढ़ी भी है तो बारिश के कारण। अगर कहीं आसमान ने आपके ऊपर कृपा की है, कुछ गल्ला बढ़ गया है तो उससे खुशी न मनाइये। उधर जब बाढ़ आ जाती है तो आप उसको दोष देते हैं, और अगर फसल अच्छी हो जाय अच्छी बारिश के कारण तो उसका श्रेय आप ले लेने को तैयार रहते हैं। तो फूड प्राबलम में बड़ी खुशी मनाने की बात नहीं है। आपने बजट स्पीच में कहा कि देश तरक्की की तरफ जा रहा है, खुशहाली है। खुशहाली का टेस्ट क्या है? खुशहाली का चिन्ह क्या है? जब मुल्क खुशहाल होता है तो इंटरटेनमेंट टैक्स में वृद्धि होती है। जरा आप इंटरटेनमेंट के टैक्स के फीगर्स को देखिये, घटे हैं या बढ़े हैं। दूसरे प्रासपेरिटी अगर बढ़ी है तो सेल्स टैक्स को देखिये, उसमें वृद्धि हुई है या कमी हुई है। इसलिये सीधी बात है कि आम जनता की क्रय शक्ति घटी है। अगर उसकी परचेजिंग पावर होती तो सेल्स टैक्स की आमदनी बढ़ी होती। दूसरे जितने भी मध्यम श्रेणी के रोजगारी हैं, दूकानदार हैं, वह आज शिकायत करते हैं कि खरीदने वाले नहीं हैं, उनकी बिक्री नहीं होती, इसलिये कि आज आम जनता की क्रयशक्ति घट गयी है तो किस तरह से हम कह सकते हैं कि बड़ी खुशहाली है, चारों तरफ। हां, यह हो सकता है कि मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर या इस सदन के सम्मानित सदस्यों की खुशहाली बढ़ी है, हमने यह कोशिश की है कि कुछ अपनी तनख्वाहों को बढ़ा लें, दवा दारू के सिल-सिले में भी अपनी सुविधायें बढ़ा लें। लेकिन देश की तस्वीर देखनी है तो देखिये कि आखिर रिक्शा पुलर्स की तादाद क्यों बढ़ी, वेश्याओं की तादाद क्यों बढ़ती जाती है? यही खुशहाली का नतीजा है? अगर इस खुशहाली के नतीजे पर गौर करें तो मुल्क की तस्वीर सामने आ जायगी और वह ऐसी नहीं है जो आपने बना रखी है। आप दरअस्ल समाजवाद नहीं चाहते हैं, आपको तो चाहिये वोट। वोट के लिये आपको चाहे समाजवाद का नारा लगाना पड़े, चाहे जातिवाद का नारा लगाना पड़े, चाहे धर्मवाद का नारा लगाना पड़े।

श्री अध्यक्ष—आप अपना भाषण पार्लियामेंटरी ढंग का रखिये। आप नियत के ऊपर हमला मत कीजिये।

श्री रामसेवक यादव—अध्यक्ष महोदय, बाहरी विदेशी लोगों को बुलाकर यह सर्टिफिकेट लेना कि समाजवाद आ रहा है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर समाजवाद चाहते हैं तो सीधे-सीधे कदम उठना चाहिये। जमीन का वितरण, नौकरी की तनख्वाहें १०० रु० से कम न हों और एक ऊपरी भी मर्यादा कायम करो कि एक हजार से ज्यादा न हो। राज्य सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो, पंचायतों के अधिकारों को बढ़ाओ, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधिकारों को बढ़ाओ। लेकिन परम्परा बिलकुल विपरीत है आज। आज पंचायतों को जो पुराने जमाने में अधिकार थे वह भी नहीं प्राप्त हैं। न्याय पंचायतों के पंचों की नियुक्ति कौन करेगा, अधिकारी करेंगे, कलेक्टर करेगा, यह कौन सा विकेन्द्रीकरण का उसूल है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधिकारों में कमी, म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकारों में कमी, जहां देखो वहीं हस्तक्षेप। इसी सिलसिले में गोंडा की म्युनिसिपैलिटी की तरफ भी इस सदन के सम्मानित सदस्यों का ध्यान जाना चाहिये। उसको भी सुपरसीड किया गया। तो यह कौन सा तरीका है समाजवाद लाने का, जम्हूरियत को पनपाने का। ला एण्ड आर्डर के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा कि सेटिस्फैक्ट्री है। लेकिन सदन के सम्मानित सदस्य और स्वयं मंत्रिगण भी अपने दिल में महसूस करते होंगे अखबारों के जरिये से जो अखबारें रोज रोज आती हैं, जो हमारे बीच में ही चारों तरफ वाकयात होते हैं, उनसे साफ़ जाहिर हो जाता है कि ला ऐण्ड आर्डर की सिचुएशन कैसी है। मुझे तो साफ तौर से कहना है। बाराबंकी में हुई घटनाओं की तरफ इशारा मैं करूंगा। इसी सदन के दो सम्मानित सदस्य बाराबंकी में इस अराजकता के शिकार हुए फिर भी ला ऐण्ड आर्डर की सिचुएशन सेटिस्फैक्ट्री कही जाय तो फिर यह कहां तक सही है। पुलिस का बजट एक तरफ बढ़ता जाता है, अधिकारी बढ़ते जाते हैं और उसी के साथ-साथ उसी अनुपात में, उसी तेजी से अराजकता, अनैतिकता और भ्रष्टाचार बराबर बढ़ते जाते हैं। तो अगर इसी का नाम ला ऐण्ड आर्डर में तरक्की है तो ठीक है, दे डालें इसको यही संज्ञा। लेकिन असलियत कुछ और है, श्रीमन्, आज न्याय की व्यवस्था की तरफ आप जाकर देखें, कचहरियों में क्या हालत है। इस सरकार ने पुराने वादे को, सेपरेशन आफ जुडिशियरी फ्राम एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी को एक्जीक्यूटिव से अलग करने के वादे को पूरा नहीं किया जो कि जम्हूरियत और प्रजातंत्र का सबसे पहला माना हुआ सिद्धान्त है। उसके अतरिक्त आज अगर देखा जाय तो न्याय प्राप्त करने में रिश्वत और तमाम तरह की परेशानियां आज जनता को उठानी पड़ती हैं। हर जगह उसको घूस देनी पड़ती है और अगर उसको न्यायालय न कह कर ठगालय कहा जाय तो अनुचित न होगा। अब वह न्यायालय नहीं रह गये हैं।

*__श्री गोपीनाथ दीक्षित__ (जिला इटावा)—अध्यक्ष महोदय, काफी कहना चाहता था अपने माननीय वित्त मंत्री से लेकिन मैं अपना कर्त्तव्य पूरा न करूंगा यदि कुछ सैद्धान्तिक प्रश्न जो हमारे विरोधी दल के नेता माननीय गेंदा सिंह ने कल और माननीय यादव जी ने आज उठाये हैं उन पर कुछ न कहूं। कल भी कहा गया और आज भी कहा गया कि इस बजट में हमको कहीं समाजवाद की छाया नहीं दिखायी पड़ती। जब समाजवाद पढ़ा था हमने और जब हम सुनते थे समाजवाद की बात तो पहले एक शब्द यह साम्यवाद इस्तेमाल हुआ करता था और साम्यवाद को लोग समझते थे बराबर बांटना। अगर कोई आदमी काना है तो वह यही समझता था कि शायद साम्यवाद या समाजवाद यही होगा कि तमाम इन्सान काने हो जायं और अगर एक आदमी की शादी नहीं हुई है तो फिर बीबी किसी के पास नहीं होनी चाहिये। लेकिन अगर समाजवाद का अर्थ यह है तो मैं भी इस बात को मानने के लिये तैयार हूं कि इस बजट में कहीं समाजवाद नहीं है। लेकिन अगर समाजवाद

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोपीनाथ दीक्षित]

का अर्थ विकेन्द्रीयकरण से है, जिसको हमने किताबों में पढ़ा है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस बजट में कि इसमें समाजवाद की तरफ ज्यादा तेजी से कदम है जितना मैं खुद नहीं चाहता। मैं आप से अर्ज करूं, मैं अभी आप के सामने पेश करता हूं और जो समाजवाद पढ़े हैं, जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं समाजवाद की उनको राजी करवा दूंगा कि यह समाजवाद का बजट है। मैं अर्ज करूं आपसे कि बाबू सम्पूर्णानन्द जी सन् १९३४ में इटावा गये थे शहादत देने राजनैतिक मुकदमें में और गवर्नमेंट कौंसिल ने उनसे सवाल किया कि समाजवाद क्या है? उन्होंने अंग्रेजी में उसका जवाब दिया कि "सोशलाइजेशन आफ़ मीन्स आफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रिब्यूशन ऐण्ड एक्सचेंज"। रामसेवक यादव जी ने तजकिरा तो उसका किया और गेंदा सिंह जी ने उसका अर्थ नहीं बतलाया लेकिन जितनी तकरीर की उससे उसका कोई वास्ता नहीं था। जरा इस बजट को उठा कर देखिये कि इसमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रिब्यूशन—विनिमय, एक्सचेंज से राज्य सरकार का कोई वास्ता नहीं है — लेकिन उत्पत्ति और वितरण की ओर जो कदम उठाया गया है वह सोशलाईजेशन की तरफ कदम है या नहीं? ये बिजली के कारखाने राज्य चला रहा है, राज्य बना रहा है और तकरीबन १६ करोड़ रुपया इस बजट में बिजली पर राज्य की ओर से लगाये जाने पर यह सोशलाइजेशन आफ प्रोडक्शन की तरफ कदम है या नहीं? और अगर इरिगेशन, सिंचाई पर १६-१७ करोड़ रुपया रखा गया है तो वह प्रोडक्शन का सोशलाइजेशन है कि नहीं? आप एक के बाद एक आइटम उठा कर इसमें से देखिये, जंगलात पर नजर डालिये। यह जंगलात राज्य की संपत्ति है और यह सोशलाइजेशन है मींस का। आगे बढ़िये कि जो कंट्रोल्ड इकनामी है, यह आप के सोशलाइजेशन का नुस्खा है। राज्य वितरण करता है चीजों का। यह सोशलाइजेशन हुआ या क्या? अनाज परचेज और डिस्ट्रिब्यूशन राज्य की तरफ से हो यह सोशलाइशन हुआ या क्या हुआ? जो समाजवाद आपने पढ़ा है मैं उसी को पढ़कर बताना चाहता हूं। यह गवर्नमेंट डेरीज जो खुली हुई हैं, ये जो फिशरीज हैं, यह जो आपकी फैक्टरी सीमेंट की खोली गयी जिसमें २ करोड़ रुपये के अधिक खर्चे की बात कही गयी और गेंदा सिंह जी ने भी कहा कि यह बहुत मुनासिब है, यह सोशलाइजेशन है या क्या? यह रोडवेज जो सारे सूबे में चल रही है, जो मोटरें चल रही हैं या सोशलाइजेशन है या क्या है? मैं आप से अर्ज करता हूं कि जो आज प्राइवेट फ़ैक्टर में कंट्रोल है, हमारी सरकार खुलने दें या न खुलने दें, यह सोशलाइजेशन की तरफ कदम है या क्या चीज है? मैं गांव में जाता हूं, जो गांव समाज को परती भूमि दे दी गयी है यह किधर का कदम जा रहा है? मैं आपसे पूछता हूं कि जिले-जिले में जो भट्टे खोले गये हैं कोआपरेटिव के बेसिस पर, यह सोसाइटी के कब्जे की बात है या इंडिविजुवल के कब्जे की बात है? लेकिन जिस चीज की तरफ आप स्वयं इशारा करते हैं उसके होने पर भी आप उसको दाद नहीं देते। आप भी तो उस वेलफ़ेयर स्टेट की मांग करते हैं जिनको हमने विधान में कहा और जिसको कांग्रेस कहती है। जिस समाजवाद की बात आप कहते हैं, वह मौजूद है और जो खराबियां आप उसमें बताते हैं उनकी तरफ हमारी निगाह है और उनको हम दूर करना चाहते हैं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—आप अबादी गये थे?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—आप वहां जाइये और वहां से सबक लाइये। हम लाहौर भी गये थे उस वक्त जबकि आप नहीं जाते थे। तो अर्ज यह है कि जहां तक आप बजट की तरफ़ निगाह डालें चन्द साल पहले यह ५२ करोड़ का था और अब १४५-४७ करोड़ के करीब है . . . .

श्री मदनमोहन उपाध्याय—जरा शूगर फ़ैक्टरीज के बारे में भी कहिये।

श्री गोपीनाथ दीक्षित—आप अगर इजाजत देंगे और मौका हुआ तो वह भी कहूंगा।

श्री अध्यक्ष--आप उनकी तरफ़ ध्यान मत दीजिये, अपनी बात कहिये ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित—तो जब यह चौगुना बजट हो गया तो यह समाजवाद का ही उसूल है कि व्यक्ति न चलाये, समाज की तरफ से सारी चीजों का इन्तजाम हो। यही हो रहा है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं । हमारे साथी इसमें यकीन करते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन आफ़ पावर हो । डिसेन्ट्रलाइज्ड सेल्फ़ सफिशेन्सी में, सर्वोदय में, उनका खयाल है कि इससे कुछ चीजें भिन्न होतीं तो अच्छा था । और सबसे बड़ा सुझाव जो मैं देता हूं वित्त मंत्रीजी को वह यह कि मुनासिब होता अगर हम खर्चे के मामले में यह पालिसी अपनाते इस उत्तर प्रदेश में कि जिस तरह से सूर्य अपनी किरणों से पानी खींचता है और जब पानी बरसता है तो मुल्क में एक तरह से बरसता है । अच्छा होता कि जो पैसा खर्च हो उसको इस तरह से करते कि मुकामी लोगों पर इस बात की जिम्मेदारी होती और जो आप की स्कीम्स हैं, प्लान्स हैं उनका ऐसा बटवारा होता कि हर जगह के लोग यह महसूस करते कि जो पैसा उनसे टैक्स के रूप में लिया जा रहा है वह उनकी निगाह में, उनके तरीके से और डिसेंट्रलाइज्ड सेल्फ़ सफिशेन्सी के लिये खर्च हो रहा है । हमारी निगाह ऐसी होती कि जो चीज जिस जरूरत की जहां के लिये है वह चीज वहां उस जिले में उस तरीके से पैदा हो रही है । इसलिये मैं अपनी भारतीय फ़िलासफ़ी, डिसेन्ट्रलाइज्ड सेल्फ सफीसेंसी की दाद देता हूं और आप से दरख्वास्त करता हूं कि जो आपका खर्चा है वह डिसेन्ट्रलाइज्ड सेल्फ़ सफ़िशेन्सी की तरफ जाना चाहिये ।

मैं अर्ज करूंगा कि चन्द दिन पहले एक सभा हुई थी जिसमें हमारे देश के सुप्रसिद्ध नेता जयप्रकाशजी ने भाषण दिया था । उसमें जो उन्होंने कहा था वह मैं आज यहां दोहरा देना चाहता हूं और मुनासिब होगा कि जयप्रकाश नारायण जी जिसकी दाद देते हैं, आप भी जिसकी दाद देते हैं और हम भी जिसकी दाद देते हैं उसी को मान कर समाजवाद शब्द की जगह पर सर्वोदय का शब्द हम ले आयें । जब सर्वोदय की भावना उन तमाम खयालात का मजमूआ है जिनको समाजवाद के नाम पर आप भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं तो क्यों न हम उस नुक्तेनजर से देखें और आगे को समझ लें कि हमारा लक्ष्य सर्वोदय है और उसके लिये सत्ता का विकेन्द्रीकरण ही सब से अच्छा रास्ता है । तो मैं आप से अर्ज करूं कि उसके लिये लाजिम है कि जो रुपया आपने मन्जूर किया है यह बहुत बड़ा बजट है और हमारी सरकार ने एक बड़ा जबर्दस्त कदम उठाया है, काफ़ी टेक्स लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है और जब आन दि ईव आफ़ ऐलक्शन्स ऐसा हो तो बड़ी हिम्मत चाहिये उन लोगों में जो इस तरह का बजट पेश करें । हमारे माननीय गेंदा सिंह जी ने कल कहा था कि हमारे माननीय गुप्तजी बड़े पार्टीबाज हैं । मैंने तो यह महसूस किया कि माननीय गेंदा सिंहजी से होशियार पार्टीबाज कोई नहीं । जब चुनाव होने जा रहे हैं और जब यह सरकार यह जिम्मेदारी लेने जा रही है कि इस प्रदेश को उठाने के लिये इतना बड़ा काम करे और उसमें खतरा ले इस बात का कि हमारे विरोधी दल लोगों के सामने मुल्क को बनाने का सवाल नहीं है बल्कि उनकी टोपी उछालने का सवाल है जो आज जान खपा रहे हैं मुल्क की तरक्की के लिये उससे बढ़ कर पार्टीबाज कोई नहीं होता । और मैं इस बात की दाद देता हूं कि माननीय विरोधी दल के नेता ने बहुत ठीक काम किया । उनकी निगाह एलेक्शन की तरफ़ थी, बजट की तरफ़ नहीं थी । तो उन्होंने भी मुनासिब और सही किया । यह सही है कि हमारे मंत्री महोदयों के पास काम बहुत ज्यादा है लेकिन एक आग है उनके दिलों में । जिस हौसले से उन्होंने रहबरी की मुल्क को आजाद कराने की उसी से वह अपनी जिन्दगी रहे चाहते हैं कि मुल्क की तस्वीर को बनायें और उसमें जो कुछ उनसे बन पड़ता है वह करते हैं और जब तक उनकी जिन्दगी है उस में लोग रहना चाहते हैं । लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो रुपया आपने बजट किया है उसमें एक बड़ा खतरा है आपके सामने । एक बड़ी भारी रकम को जब हम टेक्स से लेने जा रहे हैं तो आपकी निगाह इस तरफ़ होनी चाहिये कि एक एक पैसा सही तौर पर खर्च हो और जिस

[श्री गोपीनाथ दीक्षित]

तरीके पर आज यह पैसा खर्च करना आपके हाथ में नहीं है—बड़ी लम्बी एजेन्सियां हैं आपकी—और जिस तरीके से यह पैसा खर्च होता है और जिस तरीके से उस खर्च में खराबियां होती हैं ऐसी हर बात हमारे खिलाफ़ जाती है। और अगर आप इस खर्च पर निगाह नहीं रख सकते हैं और एक-एक पैसा सही तौर पर खर्च नहीं कर सकते हैं तो हर चीज आपके खिलाफ़ जाती है और हमारे दोस्त उसका इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ़ करते हैं। इसलिये यह आपकी यह चेष्टा होना चाहिये कि कैसे एक एक पैसा ठीक तरह खर्च हो। मैं समझता हूं कि हर जिले में जो विधान सभा के सदस्य हैं, जो विधान परिषद के सदस्य हैं और जो हमारे विरोधी दल के सदस्य हैं, उनको भी अधिकार दें, उनको भी जिम्मेदारी सौंपें कि उनका फ़र्ज होगा कि जो रूपया खर्च होता है वह सही होता है या गलत होता है उसको वह देखें और अगर वह समझते हैं कि रूपये का गलत इस्तेमाल हो रहा है और वह इत्तला देते हैं तो आपको साथी जांच करके कदम उठाना चाहिये। यदि आपने यह किया और रूपया सही तौर पर खर्च किया तो आपको बावजूद विरोधों के कामयाबी हासिल होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करूंगा कि एक मिनिस्टरी औफ़ ऐक्सपेंडीचर जरूर कायम की जाय। एक मंत्री आप का सिर्फ इसी काम को देखने के लिये होना चाहिये कि आपका रुपया सही तौर पर खर्च हो रहा है या नहीं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे सरकारी मुलाजिमीन में बहुत से निहायत अच्छे हैं, उनके दिल में आग है और ऐसे लोग भी हैं जो आपकी बढ़ती हुई रकम में से नायाब मौका समझते हैं कि उसमें से रकम दबा ली जाय। आजकल ब्लेक मारकिटिंग का क्लास खुलता जा रहा है जो कम से कम दस फ़ीसदी १५ फ़ीसदी रुपया जमीदोज करते हैं क्योंकि वह रूपया बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जो लोग इमानदार हैं उनको आप प्रोत्साहन दें और उनको तरक्की दें और जो गलत काम करते हैं उनके ऊपर कड़ी निगाह रखें।

समय बहुत कम है, एक दो सुझाव देने के बाद बाकी सुझाव मैं फिर दूंगा। इस समय अर्ज यह है कि भाई गेंदा सिंह जी ने बहुत सी अच्छी बातें पेश की थीं और मैं समझता हूं कि उन पर तवज्जुह होनी चाहिये और जो बातें अच्छी हैं उनको मंजूर करना चाहिये। मैं आपसे अर्ज करना चाहता था कि यह बजट हमारे लिये बैस्ट है और अब इलेक्शन का जमाना है इसलिये मेरी दरख्वास्त यह है कि जो बड़ी से बड़ी कुरबानी हम लोग कामयाबी हासिल करने के लिये कर सकें, जैसे कि विरोधी दल के नेता ने भी कहा था वह हमें करना चाहिये और हमें हिन्दुस्तान की सरकार पर अपने यहां इंडस्ट्रीज बढ़ाने के लिये दबाव डालना चाहिये। मैं समझता हूं कि उनकी बात मानने के काबिल है और कोई तरकीब निकल सकती है तो जरूर निकाली जाय और कोई ऐसा रास्ता निकाला जाय जिसमें सदन के सदस्य और सरकारी मुलाजमीन पैगाम उठायें कुरबानी का और अगर वह कुरबानी का रास्ता अख्तियार करते हैं तो सारे सूबे से कहें कि वह भी कुरबानी करे। अगर कोई रास्ता निकलता हो तो निकाला जाय। मैं इसकी दाद देता हूं। इतना कहकर मेरे और सुझाव हैं वह मैं माननीय वित्त मंत्री जी को लिख कर उपस्थित करूंगा। मैं समझता हूं कि जो उन्होंने बजट पेश किया उसके लिये भी उनको बधाई देता हूं।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो अपना बजट भाषण दिया उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। हम सभी जानते हैं कि ३१ मार्च को प्रथम पंच वर्षीय योजना समाप्त हो जायगी और पहली अप्रैल से द्वितीय पंच वर्षीय योजना का काम शुरू हो जायगा। इस माने में यह बजट द्वितीय पंचवर्षीय योजना का पहला बजट है। जहां तक हमें मालूम है हमारी सरकार ने इस योजना को एक बड़े पैमाने पर बनाया था और इसका खर्चा ७०० करोड़ रुपये के लगभग होने वाला था लेकिन हमारे सूबे की बदकिस्मती है कि केन्द्रीय सरकार से जितनी आशा हम करते थे उतनी आर्थिक सहायता हमको नहीं मिल सकी। जो भी कारण रहे हों लेकिन हमें अपनी यह योजना २४८ करोड़ पर लानी पड़ी। मैं नहीं जानता

कि हमारी प्रान्तीय सरकार ने कितना जोर केन्द्रीय सरकार पर दिया या क्या कारण थे मगर मेरा अपना यह निश्चित मत है कि हमारे इस प्रदेश के साइज को देखते हुये, इसकी आबादी को देखते हुये जो हमको अब तक सहायता केन्द्र से मिली है और आगे वह किसी माने में भी उचित नहीं है ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में एक बार नहीं कई बार इस सदन में जिक्र काफी हो चुका है । हमारे सामने जितने लक्ष्य थे करीब-करीब सभी को हमने प्राप्त किया । बहुत से क्षेत्रों में तो हम अपने लक्ष्य से भी आगे चले गये हमारे सामने जो कठिनाइयां थीं, जो दिक्कतें आयी, जो खामियां थीं, मैं समझता हूं कि हमने उनसे कुछ सीखा है और उस अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पहली योजना के मुकाबिले में कहीं अधिक सफल होंगे ।

मैं उन प्रोजेक्ट्स के बारे में और उनके डिटेल्स के बारे में नहीं जाना चाहूंगा, जो कि इस बजट में दिये हुये हैं । मैं केवल दो चार बातें इस भवन के सामने रखना चाहता हूं । मुझे दुख है कि जब हम इस बजट को इस्टीमेट्स कमेटी के प्वाइन्ट आफ व्यू से देखते हैं तो हमें थोड़ी सी निराशा होती है । भवन जानता है कि आज से साढ़े तीन या चार साल पहले इस भवन ने एक इस्टीमेट्स कमेटी का निर्माण किया, उसको बनाया । जिस समय वह कमेटी बनी उस समय हमारे प्रदेश में एक बड़ी आशा पैदा हुयी कि इस कमेटी के द्वारा इस बजट के ऊपर एक फाइनेंशियल कंट्रोल होगा । उस कमेटी ने अब तक इस भवन को ९ प्रतिवेदन पेश किये । बावजूद इसके कि मैंने भी सरकार को याद दिलाया और दूसरे साथियों ने भी याद दिलाया और सरकार ने भी हम से वायदा किया कि हमारा फैसला जो आपकी सिफारिशों के ऊपर होगा, हम भवन में पेश करेंगे, लेकिन आज इतना समय बीत जाने के बाद भी हमको पता नहीं चल सका कि सरकार ने उस पर क्या फैसला किया । लेकिन जो आइटम्स आज इस बजट में हैं उनको देखते हुये मैं सोचता हूं कि सरकार ने उन सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया और मैं यदि यह कहूं कि उनकी विशेषरूप से अवहेलना की है तो भी अनुचित न होगा । मैं उन डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा कि कौन सी सिफारिशें हमारी खास-खास थीं जिनकी तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया ।

मैंने देखा कि आज भी अगर हम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो मालूम होगा और हम जानते हैं कि जब नये विकास के कार्य किये जायेंगे या प्लानिंग का कोई काम होगा तो नयी भर्तियां की जायंगी, नये विभाग खोले जायेंगे, लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह भी देखता हूं कि इस बजट के अन्दर हर दिन नयी जगहें पैदा की जाती हैं, नये विभाग पैदा किये जाते हैं और उसमें कई विभाग व जगहें ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह से कामों में डुप्लीकेशन और ट्रिप्लीकेशन होता चला जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन का बोझ जनता पर दिन प्रति दिन बढ़ता चला जाता है ।

मैं इस सम्बन्ध में यह भी महसूस करता हूं कि आज चार साल से तो हम देखते हैं कि बराबर इस बात पर जोर दिया गया कि हमारे सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहों में कमी होनी चाहिये, मगर मैं नहीं जानता कि इसका कोई असर क्यों नहीं हो पाता है । हमको बताया जाता है कि हमारी कुछ बेबसी है क्योंकि कुछ कर्मचारी ऐसे हैं कि जो हमारी सरकार के अन्तर्गत नहीं आते और केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आते हैं, जैसे आई० ए० एस० । मुझे हैरानी होती है यह देख कर कि जब केन्द्र में और प्रदेश में और सारे देश में कांग्रेस पार्टी के हाथ में शासन सत्ता है तो मैं नहीं समझ पाया कि इस के सम्बन्ध में कोई स्टेप केन्द्रीय सरकार की ओर से क्यों नहीं उठाया गया । हमारे प्रदेश के बहुत से नेता जो मंत्रिमंडल में हैं, वह कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेम्बर भी हैं । क्या वजह है कि वहां इस समस्या को नहीं उठाया जाता है । मुझको यह मालूम कर परेशानी है कि पी० सी० एस० आफिसर्स का जो कि प्रदेशीय सरकार के ही तहत में हैं ग्रेड भी कुछ ऊंचा किया जा रहा है शायद ८५० के बजाय १,२५० रु० तक ले जाया जा रहा है । इसमें कोई शक नहीं कि पिछले साल आपने हमारे छोटे कर्मचारियों की तनख्वाहों में कुछ बढ़ोत्तरी की, लेकिन जब तक आप नीचे की तनख्वाहों में बढ़ोत्तरी करने के साथ-साथ ऊपर की तनख्वाहों को कम नहीं करेंगे तब तक सामंजस्य नहीं होने वाला है ।

[श्री नवल किशोर]

सरकार की जो एक्सटेंशन की नीति है उसको भी मैं समझ नहीं पाया। हम देखते हैं कि जितने भी हमारे मंत्रिगण हैं और उनके जितने पी० एज० हैं जब उनके रिटायरमेंट का वक्त आता है तो उनको ओ० एस० डीज० बना दिया जाता है। मैं नहीं समझ पाता कि सरकार को इतने ओ० एस० डीज० की क्या जरूरत पड़ जाती है। मैं यह बात नहीं कहता कि यह फेवरिटिज्म है और इसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं होंगे लेकिन मान्यवर दूसरे लोग जब इस बात को कहते हैं कि इसके पीछे फेवरिटिज्म है तो उनको जवाब देने के लिये हमारे पास कोई शब्द नहीं होता है।

जहां तक ब्यूरोक्रेसी का ताल्लुक है। कुछ भाइयों ने इसकी बाबत कहा। मुझे इस बात का ज्ञान है कि डेमोक्रेसी के अन्दर ब्यूरोक्रेसी होती है लेकिन मेरी फीलिंग यह है कि अगर प्रजातंत्र को सफलतापूर्वक चलाना है तो जितनी भी जनतांत्रिक शक्तियां हमारे प्रदेश के अन्दर हैं उनको ब्यूरोक्रेसी से ऊपर उठाना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर यह अवश्य है कि यह प्रजातंत्र आगे नहीं चल सकता है। कल हमारे एक सम्मानित सदस्य ने बताया था कि आज स्थिति यह है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट—मैं सब के लिये नहीं कहता—लेकिन जब वह गांवों में जाते हैं तो उनको २१ बंदूकों की सलूट दी जाती है। उनकी कार के आगे पायलेट चलता है। मुझे इससे कोई विशेष शिकायत नहीं है लेकिन इसके पीछे जो मनोवृत्ति है, मेंटल मेक अप है उसको प्रजातंत्र राज्य के लिये खतरनाक समझता हूं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बातों को सरकार को नजरन्दाज नहीं करना चाहिये बल्कि उसकी इन्क्वायरी करने के बाद इस तरह के सख्त आदेश देने चाहिये कि इस तरह की गलत बातें सरकार बरदाश्त करने को तैयार नहीं हैं।

जहां तक उद्योगधंधों का सम्बन्ध है हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना में १७ करोड़ रुपया उसके लिये रखा गया है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इस प्रदेश के लिहाज से वह रुपया बहुत कम है। बहरहाल जो भी है उसके अन्दर ५।। करोड़ रुपया पब्लिक सेक्टर के अन्दर रखा गया है, बड़े उद्योग धंधों के लिये रखा गया है। ९.७६ करोड़ रुपया हमारे कुटीर उद्योग के लिये रखा गया है। इस सम्बन्ध में मुझे एक बात कहना है। मैं इसकी ज्यादा एकेडेमिक बहस में नहीं जाऊंगा कि समाजवादी व्यवस्था की उससे स्थापना होगी या नहीं लेकिन मेरा यह विश्वास है और अगर मुझसे पूछा जाय तो मैं यही कहूंगा कि इससे समाजवाद चाहे न आता हो लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि सरकार की यह नीयत है और प्रयास है और उसके लिये उसका यह एक ठोस कदम है कि हम समाजवाद की स्थापना अपने इस प्रदेश में करें। लेकिन इसके साथ मुझे एक बात यह कहना है कि जहां तक सरकारी सेक्टर को बढ़ाने का प्रश्न है वह एक अच्छी बात है लेकिन यह भी सोचना पड़ेगा कि केवल दो कारखाने के सरकारी संचालन से ही हमारे प्रदेश में समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती है। हमारे सामने इस प्रकार के उदाहरण हैं कि बृटिश सरकार के जमाने में यहां पर तमाम रेलें बनायी गयीं और सरकारी संचालन भी था लेकिन कोई भी नहीं कहता था कि यहां पर समाजवाद की स्थापना वह करना चाहते हैं। तो किसी भी इंडस्ट्री का संचालन सरकार के हाथ में होने या लेने के मायने यह नहीं है कि समाजवाद की स्थापना हो गयी। मैं उद्योगधंधों के सम्बन्ध में इतनी बात कहना चाहता हूं कि यह मानी हुयी बात है कि आज हमारे पास इंडस्ट्रियल परसोनेल नहीं है। हमारे जितने सरकारी कर्मचारी हैं वह ब्यूरोक्रेटिक माइन्ड के हैं। मैं उनकी कोई आलोचना नहीं करता लेकिन उनको कोई ट्रेनिंग नहीं है कि वह इंडस्ट्री का संचालन कर सकें। इसलिये हमको इंडस्ट्रीयल परसोनेल पैदा करनी पड़ेगी।

दूसरी बात यह है कि जो हमारे मजदूर हैं जिसके विषय में मंत्री जी ने कहा कि हमारे सरकारी कर्मचारी भी एक तरह के मजदूर हैं और इस माने में श्रमिकों का हाथ मैनेजमेंट में है सेन्टीमेन्ट से यह बात अच्छी है और मैं चाहता हूं कि यदि ऐसे ऊंचे स्तर के मजदूर हमारे देश में पैदा हो सकें तो वह दिन बहुत अच्छा दिन होगा लेकिन मेरा कहना यह है कि मजदूरों के अन्दर यह एहसास पैदा किया जाय यह क्षमता पैदा की जाये जिससे वह इन उद्योगधंधों के इन्तजाम में बराबर का हिस्सा ले सके। इस तरफ हमको कदम बढ़ाना चाहिये।

तीसरी बात हम देखते हैं कि हमारी जो मौजूदा फाइनेंशियल हैन्डबुक है वह आउट आफ डेट हो गयी है। उसको चेन्ज करना पड़ेगा। उन रूल्स की वजह से दिक्कत होती है उन रूल्स की वजह से कुछ कन्सर्न में काफी कठिनाई हो जाती है। उनकी वजह से जिन लोगों के हाथ में इंडस्ट्री के काम को सौंपा गया है, उनको बड़ी दिक्कत होती है। अब वक्त आ गया है जबकि फाइनेंशियल कंन्ट्रोल को कुछ ढीला करना पड़ेगा और उसके रूल्स व रेगुलेशन्स में शासन को थोड़ी तरमीम करनी पड़ेगी।

इसके साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल कंसर्न के इंचार्ज हैं, चाहे वे मैनेजर हों चाहे डायरेक्टर हों, उनके लिये एक टारगेट मुकर्रर कर दिया जाना चाहिये कि उनको एक वर्ष में या किसी निर्धारित समय में इतनी सीमा तक उत्पादन को पहुंचाना होगा और इसी पर उनकी कार्यक्षमता की कामयाबी और गैरकामयाबी आंकनी चाहिये।

जहां तक एजूकेशन का सम्बन्ध है, इसमें कोई शक नहीं कि एजूकेशन का बजट दिन प्रति दिन बढ़ता ही जा रहा है। यह अच्छा संकेत है लेकिन मेरा ख्याल यह है कि बावजूद इसके कि तालीम बढ़ती जाती है, हजारों और लाखों की तादाद में प्रदेश के बच्चे पढ़ते जा रहे हैं, अभी तक उसका पैटर्न नहीं बन पाया है यानी हमारी शिक्षा की नीति निर्धारित नहीं हो पायी है। आज हम जिस समाजवाद की स्थापना करन चाहते हैं उसकी सबसे बड़ी बुनियाद तालीम ही है। हमें यह सोचना चाहिये कि जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, हमारे अध्यापक हैं जो हमारे नौजवान बच्चों को पढ़ाते हैं, उनमें भी वास्तविक समाजवाद के विचार है या नहीं है, उनकी लाइफ या सोशल वेल्यूज सोशलिस्टिक लाइफ और वेल्यूज से मिलते भी हैं या नहीं, उनके जीवन में भी समाजवाद की व्यवस्था हो पायी है या नहीं। मैं समझता हूं कि नहीं। मैं यह मानता हूं कि हमने चहुंमुखी विकास किया है उस दिशा में हमने बहुत बड़ा प्रयास किया है और उसमें बड़ी सफलता भी हमें मिली है। हमारे प्रदेश ने काफी प्रगति की है और कई क्षेत्रों में काफी विकास हुआ है लेकिन नये समाजवाद की स्थापना के लिये सबसे आवश्यक चीज हमारा दृष्टिकोण है, अप्रोच है, सामाजिक व आर्थिक दर्शन है। जब मैं देखता हूं कि जिनके हाथों से हमारी बड़ी-बड़ी योजनाओं का ऐक्जीक्यूशन होता है, जो हमारी योजनाओं के नियोजक हैं, जो हमारी सरकार की एजेंसी हैं, उनके अन्दर, मैं समझता हूं, इन बुनियादी चीजों की बड़ी कमी है।

टैक्सेज के बारे में भी मैं एक बात कहना चाहता हूं। टैक्स कोई बुरी चीज नहीं है। प्रदेशों में टैक्सेज लगा ही करते हैं लेकिन इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि जो कंस्ट्रक्शन्स होते हैं, जो योजनायें हमारी कार्यान्वित की जाती हैं, उनसे हमारा अनुभव यह है कि अगर उनके सुपरविजन में जरा सख्ती से काम लिया जाय तो ८ या १० प्रतिशत की बचत हो सकती है। जैसा कि एक साथी ने कहा कि टैक्शेशन कीजिये और वह आपको करना ही पड़ेगा मगर मैं यही चाहता हूं कि हर पाई जो हम खर्च करते हैं उस एक-एक पाई को हमें देखना चाहिये कि वह अच्छे ढंग से खर्च की जाती है। अंत में एक चीज जो हमारे सामने बार-बार आती है वह कनवेयेन्स की है। सरकारी गाड़ियों की है। इसका उपयोग बहुत गलत होता है। हम यह साफ तौर से जानते हैं कि ५ मील के अन्दर अफसरान को इन गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिये मगर कोई भी इस गलत इस्तेमाल से वंचित नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि लोगों को गाड़ियों का शौक पैदा हो गया है और हम भी कर्मचारियों को गाड़ियाँ देने की कोशिश करते हैं। इसलिये सरकारी गाड़ियां देने के बजाय यदि लोगों को अपनी गाड़ियां खरीदने के लिये ऐडवान्स देकर प्रोत्साहित किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

अन्त में मैं इस बात की अपील करूंगा कि यह हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का पहला बजट है इसलिये उसमें हमें छिद्रान्वेषण के बजाय पारस्परिक सहयोग से इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि हमारा प्रदेश प्रगति पथ पर अग्रगामी बन सके।

*श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप ने बजट पर बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया। आज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामदास रविदास]

हमारे वित्त मंत्री जी भी इस बजट के लिये बधाई के पात्र हैं और जिस समय हमारा यह बजट कार्य-रूप में परिणित होगा और जनता इस से लाभ उठावेगी उस वक्त माननीय मंत्री जी को जनता की ओर से भी हार्दिक धन्यवाद प्राप्त होगा आज हमारे प्रदेश का यह १ अरब ४७ करोड़ का बजट है, इसमें बहुत सी ऐसी बातें रखी गयी हैं जो जनता के लाभ की हैं और इससे यह आशा होती है कि हमारा प्रदेश दिन प्रति दिन उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। यहां की इतनी बड़ी आबादी है कि यहां के रहने वालों की संख्या और प्रदेशों से अधिक है और यह सौभाग्य की बात है कि हम तरक्की की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं जिस देश या प्रदेश का इतना बड़ा बजट होगा उस में कार्य भी अधिक होंगे इस में कोई २ राय नहीं हो सकतीं कि हमारे यहां दिन पर दिन कार्य बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारी माननीय सरकार ने जनता को सुख शांति पहुंचाने का बहुत सुन्दर प्रयत्न किया है। अगर देखा जाय तो किसानों की उन्नति जितनी इस प्रदेश में हुयी है और जितनी सुविधा उन को सिंचाई आदि की प्राप्त हुयी हैं वह शायद अभी तक किसी सूबे के लोगों को प्राप्त नहीं हो सकी हैं और आगें के लिये भी ऐसी बहुत सी स्कीमें हैं जैसे बिजली की है और दूसरे विभागों की हैं, हमें हर तरफ उन्नति दिखाई पड़ती है और आशा बंधती है कि आगे इस से भी अधिक उन्नति होगी।

हां, मैं इस बात का जरूर एहसास करता हूं कि आज इस उन्नति से हमें यह तो अन्दाजा होता है कि हमारा प्रदेश दिन प्रति दिन आगे बढ़ता जाता है लेकिन जो वास्तविक कमी है उसकी तरफ हम ठीक ढंग से अभी अपना अमली कदम नहीं उठा सके हैं। वह सवाल है यहां की गरीबी और बेकारी दूर करने का, यह सब से बड़ा काम है जो हमें अभी करना है। आज हमारे यहां साढ़े ६ करोड़ की आबादी है और इसमें से पौने ४ करोड़ के करीब लोग पिछड़े हुये और परिगणित जाति के लोग हैं उनके उत्थान का जो कार्य हो रहा है उस में अधिक प्रगति की आवश्यकता है। हम यह मानते हैं कि उनके लिये कार्य यहां हो रहा है लेकिन इसको और भी उत्तम तभी मानेंगे जबकि हम देखेंगे कि वह पूरे तरीके से उन्नत हो रहे हैं। आज भी हमारे यहां गरीबी के कारण बहुत से लोगों के रहने के लिये स्थान नहीं है। हमारे यहां चक बन्दी हुयी हमें आशा हुयी थी कि ऐसे लोगों को रहने के लिये स्थान मिलेगा लेकिन उस में भी लोगों को रहने का स्थान नहीं मिल रहा है। आज भी ऐसी दशा है कि बहुत से लोग सड़कों पर पड़े रहते हैं और उन के रहने के लिये स्थान नहीं है और लाखों आदमी भूख से मर रहे हैं और उनको दो वक्त का खाना भी नहीं मिलता, उनकी ओर हमें विशेष ध्यान देना होगा और वहां अभी तक सुख शांति का चिरागे रोशनी नहीं जल सका है वहां भी आप को रोशनी पहुंचाना है। आप को आजादी का चिराग गरीबों के घरों में भी जलाना है और वहां भी वह रोशनी करनी है। आज वह भी केन्द्रीय सरकार से और इस सरकार से आशा लगाये बैठे हैं कि हमारी ओर भी कभी कृपा दृष्टि होगी और हमारा भी उन दुखों से छुटकारा होगा। उन की सेवा की ओर भी हमें ध्यान देना है। आज हमारे यहां अगर २० आदमी पढ़ते हैं तो उन में हरिजन जाति से केवल १ ही व्यक्ति पढ़ता है, ऐसी दशा में जो लोग अभी सम्पन्न नहीं हैं उनको भी हमें हर प्रकार की उन्नति का मौका देना है। हम चाहते हैं कि उन की भी सामाजिक, आर्थिक और भौतिक सभी प्रकार की उन्नति हो।

यह तभी बन सकते हैं जब कि हमारे देश में उद्योगधंधों और विशेष कर घरेलू धंधों का विकास अधिकाधिक हो और उनसे बनी हुयी चीजों को बाहर भेजा जा सके और उनके लिये ठीक प्रकार से कच्चा माल मिल सके। । हमारी सरकार ने जो प्लान रखा है उसमें इन चीजों को स्थान दिया है। जो छोटे घरेलू धंधे हैं जैसे चमड़े का काम, कम्बल बुनने का काम, खिलौने बनाने का कार्य और इसी तरह से और हस्तकला के कार्य हैं जो घरों में किये जा सकते हैं और उनके द्वारा हजारों आदमियों को रोजगार मिल सकता है उनकी हमें व्यवस्था करनी है उद्योग धंधों के द्वारा भी और जमीन की सीलिंग करके भी। चकबंदी हमने की उससे लोगों को फायदा हुआ लेकिन उन लोगों का भी हमें ध्यान रखना है जिनके पास रोजगार नहीं है। जैसे यह है कि १८०

बीघे से ज्यादा जमीन वाले जमीन नहीं खरीद सकते उसी तरह से हमें यह भी करना चाहिये कि एक आदमी के पास कितनी जमीन रहनी चाहिये। हम समझते हैं कि अगर एक आदमी के पास सवा ६ एकड़ से ज्यादा जमीन न रहे और जैसा हमारी सरकार का मंशा भी है तो अगर उसको कार्यरूप दिया जाय तो दूसरों को भी रोजगार मिलेगा। आज हालत यह है कि एक आदमी तो दस-दस प्रकार के रोजगार करता है और एक आदमी को एक भी रोजगार मिलने की गुंजाइश नहीं है। तो अगर एक एक आदमी के पास एक ही रोजगार रहे तो दूसरों को भी जिनके पास रोजगार नहीं है रोजगार करने का मौका मिल सकता है। आज एक आदमी नौकर है, उसके पास जमीन भी है और एक आदमी है जिसके पास न जमीन है और न नौकरी। इसका असर दूसरे आदमियों पर पड़ता है। जब एक आदमी की आमदनी इस प्रकार से ज्यादा है तो लामुहाला दूसरे की आमदनी कम हो जायगी। हमें इसको आर्थिक दृष्टि से देखना है। जो हमारे समाज में ऊंचा है वह जरा नीचे को आये और नीचे का आदमी जरा ऊपर आये तो समता का ज्ञान पैदा हो जाये। तो उन लोगों को जिनके पास रोजगार के साधन कम हैं उनको रोजगार दिया जा सके ताकि हमारे देश से भुखमरी मिट सके, गरीबी दूर हो और नंगे भूखे जो आपकी तरफ आशा लगाये हुये हैं उनको सुविधायें हों। मैं तो समझता हूं कि उन्होंने सरकार को बनाया है और उससे इसलिये वह आशा लगाये हैं कि वह उनका जरूर ख्याल रखेगी। गरीब जनता की वजह से कांग्रेस जिन्दा है, अगर उसको बल मिला है तो गरीब जनता का और इसलिये उस गरीब जनता के दुखों को दूर करना उसका प्रमुख कर्तव्य है। अस्पृश्यता निवारण कानून हमने यहां से पास किया लेकिन हमारे प्रदेश में उसका कितना असर है। आज हरिजन भाई मंदिरों से भी वंचित हैं और कहीं कहीं तो होटलों और ढाबों से भी वंचित रखा जाता है। काशी विश्वनाथ जी का मंदिर जो संसार भर में विख्यात मंदिर है उस पर भी हरिजन को चढ़ने का अधिकार नहीं है तो आपने जो इस भवन से कानून पास किया उसका क्या लाभ है? आशा यही की जाती है कि जो कानून पास हो उस पर कार्य हो। बेगारी का कानून पास हुआ लेकिन कहीं कहीं यह देखा जाता है कि गरीब भाइयों से बेगारी के रूप में कार्य लिये जाते हैं और उनको कोई वेतन नहीं मिलता।

इन सब चीजों पर हमें ध्यान देना है कि जो कानून हमने पास किया उसको हमारी जनता कितना मानती है जनता में उसका कितना आदर हो रहा है। मैं मानता हूं कि केवल कानूनों के बन जाने से काम नहीं चला करता है बल्कि जब तक हम जनता के हृदय को परिवर्तित नहीं कर सकते अपने प्रेम, मोहब्बत और पूज्य बापू के आदर्शों को कामयाब नहीं बनाते तब तक हम जितने भी सदस्य हैं चाहे वे किसी भी पार्टी के हों उन सबका कर्त्तव्य है कि वे इस बात के लिये प्रयत्नशील हों कि सबको इन्सानियत का दर्जा प्राप्त हो। तो जब यह प्राप्त नहीं है और इसमें कहीं भी हम त्रुटियां देखते हैं तो यह हमारी कमजोरी है। इस कमजोरी को दूर करने के लिये सदस्य हैं वे अपने क्षेत्र में इस बात का ध्यान रक्खें कि जितने कानून पास किये थे उनमें कोई इस प्रकार की खराबियां न हों जिनको मानने में जनता को दिक्कत हो। हमें यह करना चाहिये कि हम स्वयं अमली कदम उठायें। काम सदैव अपने से होता है। इंसान जिस चीज का स्वयं मनवाना चाहता है उसे खुद भी माने और खुद भी अमल करे तभी उसकी समस्यायें हल हो सकती हैं। पूज्य गांधी जी ने यह आदेश दिया था कि पहले अपने आप अमल करो, तब दूसरों से कहो। अपने आप अमल करने की बात है और बातें कहने को तो बहुत हैं। जो हम कहें वह करना आवश्यक होता है। सोशल वेलफेयर की बात हम कहते हैं। सुधार की बात कहते हैं। उसका डिपार्टमेंट बना और उसका मिनिस्टर बना लेकिन वे उन्हीं का सुधार करना चाहते हैं जो सुधरे हुये हैं। उनको नहीं सुधारा जाता जिनको सुधारने की आवश्यकता है। उन गरीबों से हम सम्पर्क स्थापित करें जिन्हें समाज में ऊंचा उठने का मौका नहीं मिला है, उन्हें कंधे से कंधा मिला कर चलायें। जो बातें हम यहां लाते हैं उन्हें उनकी जानकारी करायें तो वे भी समझें कि हमारी सरकार यह कह रही है। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि इस पर अमल होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, प्रस्तुत बजट के साथ साथ हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति एक नये अध्याय में प्रवर्तित होती है और हम सब को गम्भीरतापूर्वक विचार करना पड़ता है कि एक समाजवादी बजट का प्रकार

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

क्या होगा। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो आज बजट बनाने का तरीका है और जो एकाउंटिंग का तरीका है उसे किसी मानी में एक समाजवादी बजट का तरीका नहीं कहा जा सकता। पुराने जमाने में अंग्रेजी काल में जो बजट बनाने की प्रणाली थी उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम होता था अर्थात पूंजी का व्यय कम होता था और राज्य की व्यापार योजनायें नहीं के बराबर थीं। आज जब पूंजी व्यय बहुत बढ़ गया है राज्य की व्यापार योजनायें बढ़ गई हैं तो यह पुराने बजट बनाने का तरीका अब नहीं चल सकता। अभी अन्य राज्य सरकारों ने इस ओर ध्यान दिया और विशेष रूप से बम्बई की सरकार ने अपना बजट बनाने की प्रणाली को बदल दिया है। उन्होंने सारे घाटे को ओवरआल डेफिसिट को अपने यहां दिखाया है। जो रेवेन्यु डिफिसिट हम देखते हैं उसमें कैपिटल डेफिसिट जो हमारा होता है उसको हम अपने डेफिसिट के आंकड़ों में नहीं जोड़ते। तो मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले वह एक हाई पावर कमेटी नियुक्त करे। 'बजटिंग' के 'पेटर्न' में क्या संशोधन होना चाहिये एकाउन्टिंग के तरीके में सब-हेड से जो इधर-उधर बदलने की आवश्यकता होती रहती है कभी कैपिटल एकाउन्ट से रेवेन्यु एकाउन्ट में और कभी रेवेन्यु एकाउन्ट से कैपिटल एकाउन्ट में मदों का टांसफर किया जाता है और जो कैपिटल और रेवेन्यु एकाउन्ट में खाई पाटी जा रही है फर्क मिटता जा रहा है उसके ऊपर विचार करने के लिये हमें एक हाई पावर कमेटी बनानी चाहिये जो एक ऐसी वित्तीय प्रणाली बनाये जिसको सब लोग आसानी से समझ सकें। आप किसी विशेष आइटम को निकालने की कोशिश करें इस बजट के अन्दर तो इस बजट के अन्दर उसको जल्दी व बिना सहायता के ढूंढ निकालना किसी साधारण नागरिक के लिये बहुत मुश्किल हो जायगा। शायद माननीय मंत्री भी बिना अपने सेक्रेटेरियट की मदद के इसमें आसानी से ऐसे आइटम नहीं निकाल सकते। यह एक बजट के 'पेटर्न' और एकाउन्ट के सिलसिले में मेरा सुझाव है। एक सबसे बड़ी गलती जो शायद इस बजट में हुई है उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस बजट में कहा गया है कि नेट बजट १४७ करोड़ ४० लाख रुपये का है। पहले श्रीमन् आप देखेंगे कि बजट के पेज ४ और मेमोरेंडम में जो सारा वित्त तमाम राज्य का दिया गया है उसके अनुसार यह बजट १४७ करोड़ ५० लाख का न हो कर सम्भवतः १३७ करोड़ ८९ लाख का होना चाहिये। सरकार ने क्या गलती की बजट में कि सवा ९ करोड़ की धनराशि रेवेन्यु एकाउन्ट में और कैपिटल एकाउंट दोनों स्थानों में जोड़ दी। कैपिटल एकाउन्ट वास्तव में केवल ४२ करोड़ ९८ लाख है लेकिन वह ५२ लाख ५० हजार दिखा दिया गया। सवा नौ करोड़ का घाटा केवल रेवेन्यु की मद में है। कैपिटल की मद में नहीं है। एक तरफ कैपिटल की मद में सवा नौ करोड़ शामिल कर लिया गया है और दूसरी तरफ रेवेन्यु डेफिसिट में भी वह शामिल कर लिया गया है। इतनी बड़ी गलती नेट बजेटिंग की बजट के भाषण में है यह माननीय वित्त मंत्री और सरकार के सोचने की बात है।

दो तीन और गलतियां बजट में देखने में आती हैं। जैसे सिंकिंग फंड में जो रुपया होता है वह रेवेन्यु एकाउन्ट से ही ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन आज पहली बार कैपिटल एकाउन्ट से एक करोड़ ७३ लाख रुपया सिंकिंग फंड में ट्रांसफर किया जा रहा है जो आज तक कभी नहीं हुआ। पहली बार इस बजट में इस प्रणाली को बदली हुई देख रहे हैं। एक दूसरी गलती यह है कि कंसालिडेटेड फंड पब्लिक एकाउन्ट आदि में हम को अलग अलग ओपिनिंग और क्लोजिंग बैलेन्स कितना है नहीं मालूम होता। फंड अलग बना दिया है लेकिन कोई पता नहीं कि ओपिनिंग

और क्लोजिंग बैलेंस कितना है। फंड अलग अलग है तो तीनों का बैलेंस भी अलग-अलग होना चाहिये। लेकिन आज तक बैलेंस नहीं बन सका कि किसका कितना क्लोजिंग और ओपेनिंग बैलेंस है। बजट में इसको माना गया है कि हम नहीं बना सके हैं।

अब राज्य की वित्तीय स्थिति के ऊपर ध्यान डालें। हम योजना अवश्य बना रहे हैं। लेकिन साथ ही राज्य की आर्थिक स्थिति की कमर तोड़ रहे हैं। इसकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। राज्य के कर्जे की हालत आप देखिये। १९५१ में हम पर कर्जा बहुत कम था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्दर पांच साल के अन्दर हमारे राज्य का कर्जा १३२ करोड़ ४० लाख रुपया बढ़ा है। और आज हमारे राज्य के ऊपर कुल २३३ करोड़ ७९ लाख रुपया का ग्रास डेट है जब कि लोंस ऐंड ऐडवांसेज जो कि सरकार के बैलेंसेज हैं ये केवल इसके मुकाबले में ऐसेट के रूप में ३९ करोड़ के लगभग हैं। १३२ करोड़ देना है और केवल ३९ करोड़ लेना है। हमारी रेविन्यू रिजर्व फंड जो हैं पिछले सालों में हमने उस रिजर्व फंड से खूब रुपया लिया। प्रथम पंच वर्षीय योजना के शुरू होने से पहले रेवेन्यु रिजर्व फंड १२ करोड़ ९८ लाख रुपया था वहां अब इस बजट में घटा कर ८ करोड़ ६५ लाख रह गया है। यह फंड बढ़ना चाहिये। लेकिन हमारी इस सुरक्षित निधि से भी लगातार रुपया निकाला जा रहा है। ऐसे ही फेमिन रिलीफ फंड की स्थिति है। उसका रुपया तो अलग होना चाहिये लेकिन उसको हमने समाप्त कर दिया है और ऊपर से १ करोड़ २५ लाख रुपया इस रिलीफ फंड से ओवर ड्रा कर लिया है। बैलेंसेज में माइनस लगा हुआ है। उसको कर्जे में चला दिया फंड से लेकर। इर्रीगेशन डेप्रीसिएशन फंड में बहुत बड़ी रकम थी जो मार्च, १९५५ में १ करोड़ ५० लाख रुपया थी जो कि नये बजट में केवल ३० लाख रहने वाली है। उत्तर प्रदेश हास्पिटल फंड में १८१ लाख रुपया था। वह घट कर ३९ लाख रुपया हो जाने वाला है। इन सभों से साबित होता है कि हमारा जो रिजर्व है आज जो बेज ऐंड मीन्स पोजीशन हमारे पब्लिक एकांउन्ट मे रिफलेक्ट होती है पूरा पूरा उसका ह्रास होता जा रहा है हम अपनी निधि को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी तरफ जो हमारे राजकीय अंडरटेकिंग्स हैं जो राज्य व्यापार योजनायें हैं जो प्रोफार्मा एकाउन्ट्स हैं उनमें भी इसी प्रकार की स्थिति है। ट्यूबवेल्स का प्रोफार्मा एकाउन्ट आप लें। इसमें १ लाख ६१ हजार रुपये का घाटा था ५०–५१ में। वह सन् ५६–५७ में १३१ लाख हो गया। गवर्नमेन्ट सीमेंन्ट फैक्ट्री और प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्ट्री तथा इस प्रकार की दूसरी जो राज्य की योजनायें हैं जो राजकीय अंडरटेकिंग्स हैं उनका प्रोफार्मा एकाउन्ट्स तो देखने को मिलता ही नहीं। तो यह संक्षेप में जो हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति है उससे यह स्पष्ट होता है कि हम कितने अधिक सेंट्रल गवर्नमेन्ट के लोन्स पर भी एक प्रकार से डिपेंड करने लगे हैं। आप सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की इन्डेपेन्डेन्स को लीजिए कि मार्च, १९५१ में हमें कुल ३,१४० लाख उनको देना था। अब सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को हमें १३,०९८ लाख रुपया देना पड़ेगा। १३० करोड़ ९८ लाख रुपया, इतना हमें केवल केन्द्रीय सरकार को देना है। तो मैं यह नहीं कहता कि हम कर्जा न लें। मैं तो केवल यह दिखला रहा हूं कि हम अपने रिसोर्सेज को भी देखें। हम समाजवाद की बात कर रहे हैं लेकिन हम साधनों का केन्द्रीयकरण नहीं करने जा रहे हैं। कोई करे केन्द्रीय सरकार ही करे। राज्य सरकार दबाव डाल सकती है केन्द्रीय सरकार के ऊपर। जब तक हम आर्थिक साधनों का समाजीकरण नहीं करेंगे तब तक हम समाजवादी योजनायें ही नहीं बना सकेंगे और इसको मैं जानता हूं यह शक्ति केन्द्रीय सरकार के हाथ में आज विधान के अनुसार है। लेकिन हम दबाव तो डालें। दूसरी और टैक्सेशन का प्रश्न लीजिए। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि पर कैपिटा टैक्स ३.२४ रुपया लगता है यू० पी० में। लेकिन टैक्सेशन

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

इन्क्वायरी कमीशन दूसरे आंकड़े देता है। टेबिल नम्बर ११ पेज ७५ पर उसमें दिया है – यू० पी० में पर कैपिटा टैक्स ५.९८ है। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन यह कहता है और आप कहते हैं ३.२४ । तो किसकी बात सही मानी जाय ?

श्री अध्यक्ष—अब आप बाद में जारी रखेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, ५ मिनट आप और देने के लिये अवश्य कह जायं ।

श्री अध्यक्ष—वह बाद में देखा जायगा ।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं यह निवेदन कर रहा था कि बजट स्पीच में यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति टैक्स ३.२४ रुपया पड़ता है ।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—श्रीमन, एक प्वाइंट आफ आर्डर में यह रखना चाहता हूं कि मैं यह जानना चाहता हूं कि यहां कोई मेज के ऊपर ग्लास रखा जा सकता है जैसा कि एक सदस्य पानी का भरा हुआ रखे हुए हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—चूंकि मौसम गरमी का आ गया है इसलिये यह रियायत करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं यह निवेदन कर रहा था कि जहां बजट स्पीच में माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में टैक्स प्रति व्यक्ति ३·२४ रुपया पड़ता है वहां टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में वाल्यूम १ में पृष्ठ ७५ पर यह स्पष्ट लिखा है कि यू० पी० में पर कैपिटा टैक्स ५.९८ प्रति व्यक्ति पड़ता है । अब श्रीमन्, यह जो सूचनाएं हैं सन् १९५३–५४ की हैं तो माननीय मंत्री जी मना तो नहीं कर सकते कि टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन को भी उन्हीं की सरकार ने रिपोर्ट दी। सन् १९५३–५४ के मुकाबले में टैक्स घटा तो नहीं है तो किस आधार पर उन्होंने यह कहा कि ३.२४ पर कैपिटा टैक्स यू० पी० में पड़ता है यह स्पष्ट नहीं है ।

दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है टैक्सेशन प्रणाली के सम्बन्ध में वह यह कि यू० पी० एक कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां पर लैन्ड रेवेन्यू पर कैपिटा सबसे अधिक पड़ता है वह सारे हिन्दुस्तान की 'ए' स्टेट्स से ज्यादा है प्रति व्यक्ति लैन्ड रेवेन्यु भी सब से अधिक है। मिसाल के लिए आसाम में पर 'कैपिटा' पर लैन्ड रेवेन्यू २.७५ है, बिहार में १.११ है, बम्बई में ३.६० है, मध्यप्रदेश में ३.७४, मद्रास में २.८० और उड़ीसा में एक रुपया है। पंजाब में २.१८ रुपया है और वेस्ट बंगाल में १.२१ रुपया है । लेकिन यू० पी० में ४.३७ रुपया पर कैपिटा है । इसी प्रकार पर एकड़ लैन्ड रेवेन्यु भी यहां सब से ज्यादा है। जब कि यू० पी० में ४.४२ पर एकड़ लैन्ड रेवेन्यू है। आसाम में केवल २.४२ रुपया, बिहार में १.५, बम्बई में २,४२ और वेस्ट बंगाल में १.५, मद्रास में १.८४ रुपया है। तो इस से क्या बात स्पष्ट होती है कि जहां हम मद्रास और बम्बई की तरह यहां सेल्स टैक्स में रेवेन्यू बढायेंगे तो हमें यह भी ध्यान में रखना है कि मद्रास आदि में पर कैपिटा लैन्ड रेवेन्यू का टैक्सेशन यू० पी० के मुकाबले में एक तिहाई है। पर कैपिटा और पर एकड़ लैन्ड रेवेन्यु वहां यहां के मुकाबिले में कम है तो यह कहना कि निम्न श्रेणियों में ज्यादा टैक्सेशन की यहां

गुंजायश है यह स्पष्ट नहीं होता । पिछले साल जब हमने कोई टैक्स नहीं लगाया तो साढ़े नौ करोड़ रुपया लोन यू० पी० को मिला। साढ़े छः करोड़ की मांग की थी लेकिन ९·३४ लाख रुपये के करीब उनको मिला। इस साल आपने १० करोड़ रुपये की मांग की है लेकिन अगर माननीय वित्त मंत्री यह समझते हैं कि ज्यादा टैक्स बढाकर उनको सेविंग्स या लोन में ज्यादा रुपया मिलने वाला है तो उनकी यह धारणा गलत है। जितनी बार उन्होंने इस प्रदेश में टैक्स बढ़ाया उतनी ही बार सेविंग्स ड्राइव और लोन में रुपया कम मिला और जब पिछले साल टैक्स नहीं बढाया तो उनका पूरा-पूरा लोन वसूल हो गया और करीब-करीब दूना मिला। इसलिये इस विषय पर पूर्ण रूप से विचार करने की आवश्यकता है। सेल्स टैक्स इन्क्वायरी कमेटी एक साल से बैठी है और उसने अभी अपनी कोई रिपोर्ट नहीं दी है। मैं नहीं समझता कि बिना उस कमेटी की सिफारिश के सरकार ने कैसे यह फैसला ले लिया कि सेल्स टैक्स बढ़े। मैं तो यह मांग करूंगा कि जो यह नया फाइनेंस कमीशन संथानम् साहब के नेतृत्व में बैठ रहा है उससे यह मांग की जाय कि इस राज्य की आबादी को देखते हुये इन्कम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी या और जो सेन्ट्रल रेवेन्यू है उनसे इस प्रदेश का अधिक रुपया मिलना चाहिये । मैं समझता हूं कि इस प्रकार हमारे रेवेन्यू कुछ बढ़ सकते हैं।

एक दूसरी बात मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय के सम्मुख उपस्थित करना चाहता हूं जो कि बम्बई में हो चुकी है। वहां पिछले एक साल से बजट में प्रत्येक जिलेवार कितनी आमदनी होती है और कितना खर्चा होता है इसके भी एस्टीमेट्स पेश किये जाते हैं। स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट को देखते हुये बम्बई सरकार ने यह फैसला किया । जो ५१ जिले इस प्रदेश में हैं उनका बजट साफ नहीं होता है। तो प्रत्येक जिले से कितनी आमदनी और कितना खर्चा उस पर होता है यह भी माननीय वित्त मंत्री जी को अगले साल से अपने बजट में रखना चाहिये । मैं जानता हूं कि इसमें दिक्कतें होंगी लेकिन फिर इसे अगले साल से पेश करने की चेष्टा करनी चाहिये।

इसके अलावा इस बजट में एक खास बात यह भी है कि बहुत से ऐसे आइटम्स प्लान के बता दिये गये हैं जो वास्तव में नान-प्लान आइटम्स थे। प्लान आइटम्स अलग लिखे हुये हैं और नान-प्लान आइटम्स का अलग उल्लेख है। योजना के अन्दर ऐसी-ऐसी मांगें भी मांगी गयी हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स के वेतन को बढाना, लेबर कमिश्नर के कार्यालय में टेलीफोन एक्सचेन्ज का इंस्टैलेशन करना वगैरह-वगैरह, ये सारी ऐसी मदें हैं जो प्लान से सम्बन्धित नहीं हैं । ये नान-प्लान आइटम्स जरूर हो सकती हैं, लेकिन योजना से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसकी ओर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये ।

साथ ही साथ में कुछ शब्द जो माननीय मंत्री जी ने माली खुशहाली के बारे में कहे हैं उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं । किसी भी माननीय सदस्य को अगर राज्य में वास्तविक माली खुशहाल होती है तो अवश्य खुशी होगी । लेकिन वास्तव में अगर ऐसा हो तभी तो । आप यह देखेंगे कि जो पर कैपिटा फीगर्स दी गयी हैं इसका जो नया बुलेटिन रखा गया है वह आज की कीमतों के आधार पर नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में जो फीगर्स दी हैं वे सन् ४८-४९ की कीमतों को ध्यान में रखकर दी हैं । हमें तो आज की कीमतों को ध्यान में रख कर देखना है । इस हिसाब से हम देखते हैं कि ४८-४९ में जब कि प्रदेश की पर कैपिटा इन्कम २४९.४ रुपये थी वह घटकर ५४-५५ में २१२.७ रह गयी यानी ३६.७ पर कैपिटा इन्कम में कमी हुई है। इसी प्रकार देहाती क्षेत्रों में पिछले साल ५५-५६ में ५०.२ पर कैपिटा में कमी हुई है। जब कि ४८-४९ में २०० रुपये पर कैपिटा इन्कम थी वह ५४-५५ में घट कर १५०.७ रह गयी।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

इस प्रकार से शहरी क्षेत्रों की पर कैपिटा इन्कम घटती जा रही है। १९४९-५० में ६०६.२ थी वह घटकर १९५४-५५ में ६०४.७ रह गई यानी २.५ की शहरी क्षेत्रों की पर कैपिटा इन्कम में कमी हुई। इस पर कैपिटा इन्कम के आंकड़े दूसरी तरह से भी नापे जा सकते हैं।

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में एक ऐग्रीकल्चरल पैरिटी इंडेक्स का जिक्र किया है। यह माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण के ३४ पृष्ठ पर दिया हुआ है। उसमें उन्होंने स्वयं माना है कि अगर पहले पेरिटी इंडेक्स १०० था तो वह घटकर ७१ रह गया यानी काश्तकार को २९ रुपया अपने जेब से देना पड़ता था। काश्तकार जब १०० रुपया देता था तो उसको ७१ रुपये मिलते थे यानी २९ रुपये काश्तकार की जेब से जाते थे। फिर समझ में नहीं आता कि पर कपिटा इंकम ११ प्रतिशत कैसे बढ़ गई। इसमें जो माननीय वित्त मंत्री जी ने आंकड़े दिये हैं उनसे स्पष्ट होता है कि वास्तव में माली खुशहाल का चित्र स्पष्ट नहीं है। अन्त में मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि जो बजट का प्रकार हो और उसके तथ्य हों वह ऐसे हों जो विकासशील प्रदेश के सहायक बन सकें और हमारी वित्त स्थिति को देखते हुये उसका उचित चित्रण कर सकें।

श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो १९५६-५७ का बजट इस सदन में उपस्थित किया है उसके लिये मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, जब बजट पर हम सरसरी निगाह डालते हैं और शुरू से आखिर तक हम इसको देखते हैं तो हमारे सामने एक चीज आती है कि हमारी सरकार समाजवादी ढांचे का समाज बनाना चाहती है, उसकी झलक ही नहीं बल्कि हम धीरे-धीरे समाजवाद की ओर आगे बढ़ रहे हैं, यह चीज हमारे सामने आती है। हमारे मित्र अगर कलर्ड चश्मा उतारकर शुद्ध हृदय से देखें तो उन्हें भी यह चीज मिलेगी अवश्य।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे वह मित्र जो विरोधी बेंचेज पर बैठे हुये हैं, जब यह कहते हैं कि इस पंचवर्षीय योजना से हमें कोई लाभ नहीं हुआ। मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूं जब मुझे प्रथम पंचवर्षीय योजना से पहले की हालत की याद आती है। इस प्रथम पंचवर्षीय योजना से पहले हमारे प्रदेश की, हमारे राज्य की क्या दशा थी। यह हमारे किसी मित्र से छिपी नहीं है। हम थोड़े से अन्न के लिये, कपड़े के लिये तथा अन्य आवश्यकता की वस्तुओं के लिये कितने मोहताज थे। इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमारा उत्पादन बढ़ा है, हमारी चीजें बढ़ी हैं और हम इस परेशानी से बच पाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बजट का मसला है हमारी सरकार जिस भावना से पैसा खर्च कर रही है इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी सरकार चाहती है, हम लोग चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की तरक्की हो हम आगे बढ़े और हम आगे बढ़ने की कोशिश कर भी रहे हैं और हम आगे बढ़ भी रहे हैं लेकिन उसमें कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं। जब तक हम उन पर मुस्तैदी से ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारे लिये आगे बढ़ना मुश्किल होगा। हम देखते हैं कि हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनकी भावनायें हैं कि हम प्रगति करें, हमारे देश की तरक्की हो, हम आगे बढ़ें, हमारे देश में नव-निर्माण हो, लेकिन आज हम देखते हैं कि जिलों के अन्दर हमारे वे कर्मचारी कि जिन से हमें खास तौर से काम पड़ता है और जिन के ऊपर हमारे प्लान की कार्यवाही का भार है देहातों के अन्दर, जहां वे काम करते हैं, उनकी भावना अभी भी ठीक नहीं है। मैं देखता हूं और अपने जिले इटावा की बात कहता हूं कि वहां पर जो काम वे करते हैं वह ज्यादातर पार्टीबंदी के लिहाज से या किसी और दूसरे स्वार्थ वश उनका वह काम होता है। जब उनकी शिकायत होती है तो जो जिले के उच्चाधिकारी हैं वह भी उसकी परवाह नहीं करते। यह देखकर मुझे दुख होता है और मैं सोचता हूं कि सरकार क्या चाहती है। आज उनके दिमाग के अन्दर क्या चीज है? मैं मिसाल के तौर पर आपको बताऊं कि हमारे पंचायत इंस्पेक्टरों

का वह काम है कि जहां से हम आगे बढ़ते हैं। हम उनसे काम कराते हैं। उनकी हालत जब हम देखते हैं तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है। हमारे यहां एक पंचायत राज इंस्पेक्टर की शिकायत ऐन्टी करेप्शन कमेटी में हुयी जिसकी जांच आज दो वर्ष से चल रही है। उन्होंने गबन किया, उन्होंने वह रुपया हड़प लिया कि जो वहां काम करने के लिये था। वहां के अधिकारी इस बात को महसूस करते हैं कि यह बात सही है लेकिन उसकी जांच दो वर्ष से चल रही है और आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, कोई परवाह नहीं होती। एक दूसरे पंचायत इंस्पेक्टर का हाल यह है कि एक जगह पर जहां वह तैनात थे, एक पंचायत का चुनाव हुआ। इंस्पेक्टर साहब उस चुनाव में जिसकी जीत हुयी उसके खिलाफ थे और दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते थे। नतीजा यह हुआ कि पौने दो वर्ष तक उन्होंने उनको प्रधान का चार्ज नहीं मिलने दिया। अधिकारियों से कहा गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो जब तक हम इन बातों पर मुस्तैदी से अमल नहीं करेंगे तब तक, मैं समझता हूं, कुछ नहीं हो सकता। हमारी शिकायतें कई बार यहां तक आती हैं लेकिन जिले के अधिकारियों की वजह से यह भी मजबूर हो जाते हैं। छोटे-छोटे कर्मचारियों पर आरोप लगते हैं, उनका तबादला होता है लेकिन कुछ नहीं होता है। यह चीजें हमारे लिये बड़ी रोड़ा बन रही हैं। यह चीजें हमें आगे नहीं बढ़ने देंगी। जब तक हम इन चीजों की जिम्मेदारी के साथ परवाह नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे।

जहां तक यातायात की बात है, हमारी जरूरतें हैं कि हमारे देश की सड़कें अच्छी हों। किसी देश की प्रगति वहां के यातायात के साधनों पर मुनहसिर होती है। जब तक हमारे देश की सड़कें अच्छी न होंगी, हमें ऐसा विश्वास है कि हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आज जब हम देखते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो धन सड़कों के लिये दिया गया है वह बहुत ही नाकाफी है तो हमें दुःख होता है। मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग की सब-कमेटी का सदस्य होने के नाते कह सकता हूं कि हमें जितने धन की आवश्यकता है उसके देखते हुये जो धन मिला है वह बहुत नाकाफी है और किसी-किसी जिले में तो नाममात्र के लिये भी सड़कें पक्की नहीं बनायी जा रही हैं। मेरे इटावा जिले को ही लीजिये। वहां मुझे मालूम हुआ था कि १७ मील लम्बी सड़कें पक्की बनायी जा रही, हैं, लेकिन बाद को जब मैं चीफ इंजीनियर से मिला और उनसे बात हुयी तो उन्होंने कहा कि १३ मील की सड़क वहां खत्म करदी गयी है क्योंकि रुपये की कमी है। सिर्फ ४ मील का टुकड़ा नया बनेगा। तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि समझ में नहीं आता कि इस चार मील का टुकड़ा बनने से ही जिले का क्या उद्धार हो जायगा, वह भी न बनाया जाय। तो मैं समझ नहीं पाता कि ऐसा कर हम इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितनी तरक्की कर पायेंगे मैं अपनी सरकार से फिर यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस तरह की चीजों में प्रत्येक जिले के कोटे को ठीक हिसाब से तय करे और जो कुछ पैसा वह सड़कों में या दूसरे कामों में लगा सकती है उसको लगाये, खर्च करे। ऐसा न हो कि किसी जगह विशेष रूप से खर्च हो जाय और किसी जगह पर कुछ भी काम न हो। तो मैं सरकार से फिर अपील करूंगा कि वह इन बातों पर ध्यान दे।

जहां तक हम देखते हैं हम अपने सिंचाई मंत्री महोदय को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते क्योंकि उन्होंने इस बात की कोशिश की है कि सिंचाई के साधन ज्यादा से ज्यादा मुहैया किये जायं। हर जगह पर सिंचाई का काम हो रहा है। उससे हमारे राज्य की तरक्की हुयी है और हमारे यहां की अन्न की पैदावार बढ़ी है, लेकिन वहां भी छोटे-छोटे अधिकारियों की शिकायतें मिलती हैं। वहां पर भी ऐसा होता है कि मैं आपको बताऊं कि मेरे जिले में एक दफा काश्तकारों में बड़ा बावेला पैदा हुआ। उन्होंने आकर मुझसे कहा कि जिन धान के खेतों की सिंचाई नहीं हुयी है उनसे भी सिंचाई की कीमत लेने को लिखी गयी। इस तरह से पतरौल और अमीन कहते हैं कि उनको जिला अधिकारियों से ऐसे आदेश मिलें कि सबसे लिया जायेगा, मैं वहां के एक्जिक्यूटिव इंजीनियर से मिला उन्होंने मुझको बताया कि ऐसा आदेश इसलिये दिया गया है कि बहुत से पतरौल अमीन जिन जगहों पर पानी दिया जाता है उनको भी ले-देकर छोड़ देते हैं। मैंने उनसे कहा कि इस बात की कोशिश कीजिये और इस बात के लिये उनको सजा दी जाय अगर वह गलती करते हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिये। लेकिन यह किस प्रकार से आप पता लगायेंगे कि

[श्री मिहरबान सिंह]

कहां पर आबपाशी हुयी है। कहां पर पानी नहीं गया है वहां पर भी मुश्किल होगी। तो उन्होंने बतलाया कि जो लोग हमारे यहां अपील करते हैं, उनको जांच कराने के बाद माफ कर देते हैं। यह बड़ी दिक्कत है काश्तकारों के सामने आप इस बात की कोशिश कीजिये तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो छोटी-छोटी दिक्कतें हैं देहातों के अन्दर, जिनकी वजह से जिस तरह से हम आगे बढ़ना चाहते हैं उस तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन छोटी-छोटी दिक्कतों को कम करने की आवश्यकता है। हम आगे जरूर बढ़ रहे हैं और हमारे देश में समाजवाद कायम होगा। हमारा देश समाजवाद ढंग पर बनेगा इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम उसके लिये कोशिश कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ में अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात के लिये आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस मौके पर मुझे अपना विचार व्यक्त करने के लिये मौका दिया है। यह १९५६–५७ का जो बजट है और जो इसके मुताल्लिक हमारे माननीय वित्त मंत्री ने भाषण दिया है, और भाषण को पुस्तिका के रूप में प्रस्तुत की है मैंने उसको बहुत ध्यान से पढ़ा है। जो कुछ उन्होंने विवरण दिया है उस विवरण को देखकर सचमुच मुझे बड़ी खुशी हुयी। मैं उनसे सहमत हूं और उनका मैं समर्थन करता हूं लेकिन इसके साथ-साथ मुझे एक बात की तकलीफ भी जरूर हुयी कि जिस माध्यम से, जिस भाषा से और जिस शैली से उन्होंने विवरण प्रस्तुत किया है वह सचमुच ऐसा नहीं है जो कि हमारे संकल्प के अनुसार हो। हमने संकल्प किया है कि हम ६५ तक अपने देश में प्रचुर मात्रा में हिन्दी का प्रचार कर लेंगे और हर दफ्तर में हिन्दी का ही प्रयोग होगा। लेकिन जब मैंने इसको देखा तो सचमुच ताज्जुब हुआ। मैंने अन्दाजा लगाया और उसको पढ़कर शब्दों का लेखा-जोखा किया तो ऐसा मालूम हुआ कि अगर हिन्दी के शब्द दो हैं तो उर्दू के तीन। इस सम्बन्ध में मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अगर हम ही संकल्प करें और हम ही उसको तोड़ दें तो यह बड़े दुख की बात है। मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि हमारे ही द्वारा ऐसा कार्य नहीं होना चाहिये। मैं मानता हूं कि यह स्टेट और हमारी प्रदेशीय सरकार और भाषाओं के प्रोत्साहन में भी कोशिश कर रही है और उन्होंने छूट दी है कि जहां तक हो सके दूसरी भाषाओं को आगे बढ़ाने में सहायता की जाय। लेकिन साथ-साथ यह भी बात है कि जिस भाषा को हमने अपने देश की मातृभाषा बनाया है और एक पद पर आसीन किया है उसको ऐसे मौके पर जब कि एक प्रदेश का बजट पेश हो तो उसका प्रयोग न किया जाय बल्कि किसी और भाषा का प्रयोग किया जाय ठीक नहीं है। इसके पश्चात् मैंने कल से समाजवाद की काफी चर्चा सुनी और उस चर्चा में तरह-तरह की बातें कही गयीं। हमारे विरोधी पक्ष के नेता गेंदासिंह साहब ने कहा कि यहां सरकार ने जमींदारी अबालिशन ऐक्ट पास किया है, एवं जमींदारी उन्मूलन की है और इस बिना पर कहती है कि हमने समाजवाद की व्यवस्था इस देश और प्रदेश में कायम की है। मैं नहीं समझता कि कभी उत्तर प्रदेशीय सरकार ने ऐसी बात कही हो कि हमने समाजवाद की व्यवस्था को कायम कर लिया है। अगर कुछ कही भी है तो यह बात कही है कि हमारा ढांचा समाजवाद का ढांचा होगा और हमारी तमाम क्रियायें उसी भावना से प्रेरित होकर होंगी। जो कुछ हम करेंगे वह समाजवाद के ढांचे को दृढ़ करने के लिये, उसको मूर्तिवत् करने के लिये, उसको कार्यरूप में लाने के लिये उसको कार्यान्वित करने की चेष्टा से ही करते रहेंगे। लोगों का कुछ ऐसा ख्याल है कि समाजवाद कोई मूर्तरूप ऐसी वस्तु है लेकिन जो दार्शनिक लोग हैं, जो विचारशील लोग हैं वह समाजवाद को एक प्रक्रिया मानते हैं, एक प्रोसेस मानते हैं और वह प्रक्रिया अनन्त की ओर सदैव प्रवाहित होती रहती है और उस पर धीरे-धीरे चलकर हम उस वांछित अवस्था पर पहुंचने का प्रयास करते रहते हैं जो शिव हैं एवं कल्याणकारी हैं हमारा सदैव ही यह प्रयास रहता है कि मानव जाति के दुखों को दूर कर उसको सुख की चरम सीमा पर पहुंचा दें। इसी को प्राप्त करने के लिये इस देश में हम भगीरथ प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ऐसे समाज की रचना करने का है जिसमें दुख न होगा, हर एक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का पूरा अवसर प्रदान होगा। यही कारण है कि हमने जमींदारी उन्मूलन किया, पंचायतों की स्थापना की, सहकारिता

आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने का प्रयत्न किया, पूंजीपतियों के कैपिटल को कम करने के लिये हमने मृत्यु कर भी लगाया, हमने ऐग्रीकल्चरल टैक्स लगाया, हमने न्यूनतम और अधिकतम वेतन भी निर्धारित किया, इसके अतिरिक्त आपने इसी बजट में देखा होगा कि १ से लेकर ५वीं कक्षा के विद्यार्थियों की फीस आधी माफ की है, दो सौ से कम पाने वालों की मंहगायी भत्ता के आधे भाग को कर्मचारी के तनख्वाह में जोड़ दिया गया है ऐसी-ऐसी बहुत सी बातें हमने की हैं और यह तमाम चीजें उसी समाजवाद को अग्रमुख करने के लिये हमने की हैं। गत पंचवर्षीय योजना में हमने इतना गल्ला पैदा किया कि हम इस स्थिति में हो गये हैं कि गल्ले के मामले में हम किसी पर आश्रित नहीं हैं। उसके लिये हमने साधनों को जुटाया है। एक साथी ने इसके बारे में यह कहा कि मौसम अनुकूल होने के कारण यह गल्ला अधिक पैदा हो गया न कि सरकार के अनेक प्रयत्नों के कारण से। इससे ज्ञात होता है कि उन्होंने उस ओर बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया जो प्रयत्न कि सरकार ने इस बारे में किये हैं। क्या यह सही नहीं है कि सरकार ने नलकूपों की संख्या बढ़ाई, नहरें बढ़ाई, खाद दिया, अच्छा बीज दिया, अच्छे जानवरों की नस्लें बढ़ाई, इसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया बल्कि एक रौ में कह गये कि यह गल्ले की अधिक उपज केवल मौसमों की अनुकूलता से हुआ है, यह गलत बात है और सरासर गलत है। इसके साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति जिस के पास जरा सी भी बुद्धि है, जो समझना चाहता है और समझने की कोशिश करे वह जरूर समझेगा और कहेगा कि हमारी सरकार क्रमिक रूप से और एक सुदृढ़ता के साथ प्रगति की दिशा में बढ़ी है। उसने अपना उद्देश्य माना है और केवल समाजवादी व्यवस्था के रूप में माना है और उसी रूप की प्राप्ति के लिये धीरे-धीरे हमारे प्रदेश की सरकार बढ़ती जा रही है।

माननीय गेंदा सिंह जी ने अपने भाषण में एक बात और कही। उन्होंने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष बिरला महोदय बनाये गये हैं, और उन्होंने इस सिलसिले में यह भी कहा कि मुझे उम्मीद नहीं है कि माननीय गुप्ता साहब उनका हृदय परिवर्तन कर सकेंगे। उन्होंने ठीक कहा, यह सही बात है लेकिन अगर उनका गुप्ता जी हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते तो गेंदासिंह साहब भी नहीं कर सकते। अगर किसी का हृदय–परिवर्तन कोई करता है तो समय, वातावरण और विचार भाव करते हैं, यह तमाम चीजें हृदय-परिवर्तन करती हैं और ये ही अनुकूल परिस्थितियों को भी पैदा करती हैं। हमारे गेंदासिंह साहब समाजवादी हैं, समाजवाद के समर्थक हैं। मैं समझता हूं उनको ख्याल होगा कि एक जमाना था इंगलैन्ड में श्री बीवेन ने समाजवादी विचार से अभिभूत होकर एवं समाजवादी भाव में आकर अपने स्टेट का बटवारा कर दिया और इसी तरह का कार्य तिब्बत में भी हुआ और वह कार्य ३ बार हुआ। अगर यह कहा जाय कि उन्होंने अपने यहां समाजवादी व्यवस्था कायम कर दी तो ऐसा तो नहीं हुआ लेकिन यह सही है कि उनके मानस में समाजवादी प्रवृत्तियां अंकुरित हुयी, आज यहां भी इस सदन में बैठनेवाले माननीय सदस्य चाहे कांग्रेस पार्टी के हों या समाजवादी पार्टी के हों क्या यह सही नहीं है कि अधिकतर हम सबका पालनपोषण पूंजीवादी अंचल में हुआ है। हुआ है सही है। आज हमारे साथ ऐसे लोग हैं जिनका पहले से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं था लेकिन वह आज हमारे साथ हैं, आज हम देखते हैं और अपनी आंखों से हमने देखा है (और उनमें एक दो आदमी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि एक जमाना था कि कलेक्टर से मिलना आसान था लेकिन उनके पास पहुंचना मुश्किल था) लेकिन इस तरह के आदमी भी आज आप के साथ हैं जो आपसे किसी माने में, किसी अर्थ में किसी कार्य में कम या पीछे नहीं हैं। समय और समाज, वातावरण की गतिविधि नये हृदय और नये विचार को प्रतिपादित करने में सहायक होते हैं। फिर आप बिरला साहब के बारे में कैसे आपत्ति करते हैं जबकि सारे विश्व में समाजवाद का नारा किसी न किसी रूप में जोर से चल रहा है। आज एक फैशन हो गया है, कहने का तरीका और सोचने का ढंग हो गया है और हर एक अपने को समाजवादी कहता है चाहे वह किसी तरह का समाजवादी क्यों न हो। अगर बिरला साहब इस कमेटी के चेयरमैन हैं तो मुझे तो इसमें कोई हैरतअंगेज बात नहीं मालूम होती। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यह उन की मानस स्थिति की परीक्षा का समय है। और वह काम ऐसा है कि उनको बहुत सतर्क होकर सम्पादित करना है और उन

[श्री गंगा प्रसाद सिंह]

तथ्यों का निरूपण करना है जिन से हमारा समाज आगे बढ़े। उसके बाद में एक बात की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं वित्त मंत्री महोदय का, कि हमारे उत्तर प्रदेश में लाखों एकड़ जमीन ऐसी हैं जो कि छोटी-छोटी जोतों में हैं और उन छोटी-छोटी जोतों की संख्या जब से यह भूदान आंदोलन चला तब से और भी बढ़ गयी है। ये छोटी-छोटी जोतें अलाभकर हैं। जिन किसानों को ये छोटी-छोटी जमीनें दी गयी हैं या पहले से हैं उन पर परिश्रम जितना वे करते हैं, परिश्रम के बाद उसके एवज में उतना मुआविजा उनको मिलता नहीं जितना कि मिलना चाहिये। माननीय वित्त मंत्री से मैं आपके द्वारा यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसी अलाभकर जोतों के लिये उस वक्त तक मालगुजारी को मुलतवी कर दें जब तक कि वे लाभकर न हो जायं और उनको लाभकर करने के लिये हमारी सरकार जहां तक हो सके सहायता दे ताकि वे छोटे-छोटे लोग जो कि सुबह से शाम तक मेहनत इन खेतों पर करते हैं उसके बावजूद भी उनको पूरा पारिश्रमिक नहीं मिलता, मिलने लगे।

अंतिम बात यह कहना चाहता हूं कि मैं यह मानता हूं कि हमारे सामान्य प्रशासन का सामान्य रूप बड़ा ही सुन्दर रहा है और सुन्दर है भी लेकिन उसके साथ मुझे यह अर्ज करना है कि कुछ बातें जिले में ऐसी हो जाती हैं जिनको न कहना ही अच्छा है। लेकिन कभी-कभी जबान खुल ही जाती है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि बाढ़ का जमाना था और हमने अपने यहां से सहायता के लिये प्रार्थना की। यहां से एक उपमंत्री को भेजा गया और जो दुःख के बारे में अर्ज किया गया था उसको उपमंत्री ने सही पाया। उसके पश्चात् वहां के जिलाधीश महोदय के दिल में कांटा चुभा कि हमारी बेइज्जती के लिये यह काम किया गया है। और नाराज हो गये सही बात है कि समाज सेवा की भावना से प्रेरित होकर जब कोई उपाय न था तो यह किया गया। उसके बाद जितनी जितनी बातें हुयी हैं उनके बारे में क्या कहा जाय।

एक मिनट में मैं यह बात और अर्ज करना चाहता हूं। कुछ किसान ने जिलाधीश से पहसा में अर्ज किया कि हमारे पास कुछ रुपये जो तकावी के हैं बाकी हैं। हमें मद मालूम नहीं है जिसमें हम किस्तों को समय पर जमा कर दें। अगर हमें बता दी जाय तो हम जमा कर दें। लेकिन उन्हें बतलाया नहीं गया और कुल रुपये की वसूली के लिये कागज भेज दिया गया और बाद को कुर्की आदि जारी की गयी। क्या यह ठीक है? प्लानिंग कमेटी की मीटिंग हुयी और इस सभा के एक मेम्बर ने कहा कि हमको ऐसा काम करना चाहिये जिससे कि कम से कम किसानों को तकलीफ हो सुझाव भी पेश किया। उप मंत्री महोदय (नियोजन) वहां मौजूद थे जिलाधीश ने तैश में आकर ऐसी बातें कहीं जिनको मैं यहां नहीं कहना चाहता। अगर सरकार इस चीज को जानना चाहती है तो उप-मंत्री नियोजन से पूछ सकती हैं कि मैं जो बातें कह रहा हूं गलत हैं या सही। ऐसे सलूक से जिले का शासन क्या ठीक चलेगा। अन्ततः मैं वित्त मंत्री को इस पत्र के लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट की प्रशंसा करता हूं कि इस ढंग से बजट इस वर्ष प्रस्तुत किया गया है उसमें सचमुच नवीनता है। सांस्कृतिक दृष्टि से भी मैं इस बजट की प्रशंसा करता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम समाजवाद ढांचे की ओर बलपूर्वक चल पड़े हैं और इस अवसर के ऊपर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि समाजवादी ढांचे को लाने के लिये पहले हमें स्मरण रखना चाहिये कि कहीं व्यक्तिवाद ढांचा समाज के लिये धराशायी न हो जाय। हम इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि समाजवादी ढांचे को अच्छी तरह से प्रदेश में लाने के लिये मेरा खयाल है कि हम उसके अन्तर्गत समाजवादी ढांचे के अनुरूप एक कानून बनावें। गांव में से जो जमीन निकल जाती है सार्वजनिक कामों के लिये, चाहे वह ट्यूबवेल में हो, चाहे वह नहर में हो, चाहे पंचायतघर के लिये हो जिस तरह से भी हो उसे सारे गांव को सहन करना चाहिये। जिस व्यक्ति पर आपत्ति पड़ती है उस वक्त ढांचा सदा के लिये धराशायी हो जाता है।

समाजवाद का हमें कुछ ऐसा विधान बनाना होगा जिससे समाजवाद ठीक-ठीक तरीके पर लागू हो सके। तो मैं बहुत बलपूर्वक सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अविलम्ब इस सदन में ऐसा कोई विधान आना चाहिये जिससे गांव की जो जमीन ली जाती है उसकी पूर्ति सारे गांव वाले कर सकें। माननीय मुख्य मंत्री जी को शायद इस विषय में जानकारी हो लेकिन मुझे विवशतः आज इस सदन में अपनी आवाज उठानी पड़ती है। जहां चक-बन्दी हो जाती है वहां पर जिस गांव में यह जमीन ली जाती है वहां बड़ा विकट रोग हो जाता है। जिसके चक से जमीन निकलती है तो कोई विधान नहीं है कि किस तरह से उसकी पूर्ति की जाय।

इसके बाद मैं इस सदन का ध्यान अपने बस्ती जिले के उत्तरी भाग डुमरियागंज तहसील की तरफ ले जाना चाहता हूं। मेरे जिले में ६ तहसीलें हैं। पर मुझे यह बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जितना भी विकास हुआ है डुमरियागंज के उत्तरी भाग में, उस का एक अंश भी वहां नहीं हो पाया है, न नहर है, सिंचाई के साधन से बिलकुल ही विहीन है। यातायात का इतना अभाव है कि अब मेरी वाणी कोई काम नहीं कर सकती। डुमरियागंज का जो हिस्सा उत्तरी भाग में पड़ता है उस के अन्दर जो गल्ला पैदा होता है उसे किसान स्टेशन तक नहीं ले जा सकता है। बीच में एक छोटी-सी दरिया बूढ़ी राप्ती पड़ती है जिस पर कोई पुलिया भी नहीं है। बस्ती की तरफ इसलिये नहीं आ सकता कि बूढ़ी राप्ती पर कोई पुल नहीं बना हुआ है। किसी तरह से कोई साधन यातायात का नहीं है। ऊख की पैदावार का सर्वनाश हो रहा है। किसान अपनी ऊख को किसी हालत में स्टेशन नहीं लेजा सकता और न बस्ती ले जा सकता है। तो इतनी कठिनाई वहां यातायात की है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो रूप-रेखा हमारे सामने प्रस्तुत हुई और जिसको लेकर हम गांव-गांव गये वह भी धनाभाव के कारण धराशायी हो गयी। उसके अन्तर्गत एक २६ मील की सड़क बांसी से कुरसीपुर तक बनाने की योजना है जो इटवा से आगे चलकर समाप्त हो जाती है। उसमें पुलिया का कोई जिक्र नहीं है। मेरा ऐसा विचार है कि सरकार को चाहिये कि वह इस स्टेशन पर बनने वाली पुलिया को जो बूढ़ी राप्ती पर पड़ती है अविलम्ब बनावे। उसमें सरकार का कोई खर्चा नहीं पड़ेगा। एक २६ मील की जो सड़क है वह बांसी से इटवा तक ६ मील पड़ती है और ३६ हजार रुपया जो इस सड़क के लिये रक्खा गया है—पी० डब्ल्यू० डी० फी मील के हिसाब से जो जोड़ा करता है वह सारा रुपया बच जायगा और वह रुपया पुलिया पर खर्च किया जा सकता है। पहले इस पुलिया की आयोजना थी लेकिन उसे धनाभाव के कारण निकाल दिया गया है। लेकिन सरकार को यह कठिनाई समझना चाहिये और इसमें लाखों व्यक्तियों के जीवन का विकास रुका हुआ है। सच कहा जाय तो बस्ती जिले में ६ तहसीलें हैं और स्वशासन की दृष्टि से सरकार इस समय तैयार नहीं हो रही है, लेकिन मेरा ऐसा सुझाव है नौगढ़, डुमरियागंज, और बांसी तहसील को मिलाकर एक दूसरा अजला बना दिया जाय। इसी तरह से बढ़नी में जाने के लिये गोंडा होते हुये या गोरखपुर होते हुये जाना पड़ेगा और कोई साधन नहीं है। वहां पर भ्रष्टाचार की बात मैं कहूं तो किसी को दिखा नहीं सकता। जिलाधीश एक वर्ष में एक बार जाकर कृतकृत्य हो सकता है। सरकार इस दिशा में सोचे कि नौगढ़, बासी और डुमरियागंज का एक जिला बना दे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह एक सुन्दर जिला होगा और वहां शासन की दृष्टि से अच्छा काम चालू हो सकता है। नैपाली सीमा के निकट होने के कारण से यह भी एक बहुत रक्षा का स्थान होगा। तो सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिये।

अब मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं हमारे सीमावर्त्ती क्षेत्र में। हमारे बढ़नी स्थान के अन्तर्गत एक इंटर कालेज है जिसमें वहां पर तीन हिस्से पहाड़ियों के सड़के पड़ते हैं। वहां पर सरकार को दिखलाना चाहिये, सरकार के सुनाम की रक्षा के लिये विदेशों में इतना रुपया व्यय हो रहा है, तो उस स्कूल के ऊपर हमारे प्रदेश की सरकार की कुछ विशेष दृष्टि होनी चाहिये, क्योंकि वहां पर नेपाली छात्र भी आते हैं। उस कालेज के

[श्री रामलखन मिश्र]

ऊपर अब तक सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। वास्तव में मूल में यही कारण है। छः तहसीलें हैं। प्लानिंग कमेटी में बैठकर तो एक ऐसी रस्साकशी होती है कि मैं तो आश्चर्य-चकित रह जाता हूं। वहां पर क्षेत्रवाद इतना बड़ा भयंकररूप धारण कर लेता है कि वह हमें बिल्कुल दृष्टिविहीन कर देता है। हमारी दृष्टि पूरे जिले पर नहीं जाती और वहां पर प्लानिंग कमेटी में होने के पहले कई दलों में हमें विभाजित हो जाते हैं और सही रूप में कोई चीज हमारे सामने नहीं आ पाती। सरकारी अफसर तो हंसवार अपने चित्त को शान्त कर लेते हैं और यदि उनके अन्दर कोई बात आये भी, तो वह कुछ कर नहीं सकते। प्लानिंग कमेटी के अन्तर्गत मेरा यह सुझाव है कि हमारे माननीय मंत्री जी को चाहिये कि जिले को वह कोई ऐसा दृष्टिकोण दे कि जिससे वहां प्लानिंग कमेटी में सही ढंग से कुछ काम हो सके। कौन कितना बली है, किसका कितना बल है, किसका साधन किस मंत्री के पास कितना है, कौन किस मंत्री के पास तक अधिक दौड़ लगा सकता है, कौन मन्त्रिमंडल के साथ दौड़ने में कितना सिद्धहस्त है, इन सबका प्रभाव सरकारी यंत्रों पर पड़ता है। यही कारण है कि हमारे डुमरियागंज पर सरकार की दृष्टि नहीं पड़ी वहा पर, मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है, और न मैं ऐसा कह कर किसी के सम्मान के विरुद्ध ही कोई बात कह रहा हूं कि बाहर के जिले के सदस्य किसी जिले में जो भर दिये गये हैं, बहुत ईमानदारी से अपना सहयोग वहां नहीं दे पाते। आज तो जनता पिछले दिनों जैसी नहीं है। आज तो जनता इस बात को देखती है कि हमारा सदस्य ईमानदारी से कितना प्रयत्न हमारे लिये कर रहा है। जब कि जिले के अन्दर और भागों में कोई बात हो जाती है दो वहां की जनता मौन हो जाती है। यह रोग तो दूर किया जा सकता है यदि हम प्रदेश के मन्त्रिमंडल से कोई ऐसा आदेश पायें अपनी प्लानिंग कमेटी के वास्ते कि हमें वहां इस दृष्टि से पूर्ण रूप से विचार करना चाहिए तो यह रोग भी दूर किया जा सकता है। शिक्षा के स्थान में तो वहां पर सरकार की तरफ से सरकारी सहायता पर न कोई कालेज चलता है, न कोई स्कूल चलता है। रोगों के क्षेत्र में मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि कालाजार का वहां अड्डा था। लेकिन जब से कांग्रेस सरकार आयी है तब से कालाजार का डर गया और वह कालाजार वहां से सदा के लिये विनष्ट हो रहा है। मलेरिया की भी कमी हो रही है लेकिन वह एक डाक्टर जो पांच छः मास के लिये जाता है वह वहां पर उसके कुछ बीज छोड़कर ही चला जाता है। एक ही डाक्टर है। वह जब दूसरे स्थान पर जाता है तो वहां पर फिर वही भयावह समस्या आ खड़ी होती है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वहां पर कुछ दिनों के लिये कालाजार और मलेरिया के लिये एक डाक्टर नियुक्त कर दें और वहां पर अस्पतालों की व्यवस्था होनी चाहिये, क्योंकि उस क्षेत्र में मलेरिया और कालाजार और ऐसे और अनेक रोगों से जनता इतनी त्रस्त है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह ऐसे जिले का पुराने समय का, आज के समय का नहीं, आज तो हालत दूसरी है, पुराने समय का हरिजन क्षेत्र है। तो इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*राजावीरेन्द्र शाह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो वादविवाद १९५६-५ बजट पर कल से हो रहा है, उसे मैंने बहुत ध्यान पूर्वक सुना। मैंने नेता विरोधी दल के भाषण को और और भाषणों को बड़े ध्यान से सुना। श्रीमन्, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूं। मैं स्वतंत्र आया हूं। तो मैं उसमें नहीं पड़ना चाहता कि यह समाजवादी बजट है या क्या है। मैं बजट को देख कर इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि यह जनता के हित में है और कल्याणकारी बजट देखने में आता है। जितनी बात मेरी समझ में नहीं आती है वह मैं श्रीमन्, उसी तरह से सरकार को बतलाना चाहता हूं। सरकार ने विकास के लिये करीब ४४ करोड़ रुपये रखें हैं और उसके लिये यह कहा है कि ११ करोड़ के करीब उसमें करों से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आमदनी करनी है और उसके लिये मंत्री जी ने यह भी संकेत और निश्चय किया है कि आगे कोई टैक्स भी सरकार लगाने का विचार रखती है। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं इतना ही अदब से कहना चाहता हूं कि टैक्स से हमारे प्रान्त की जनता इतनी अधिक लदी हुई है कि उस पर और विचार करना किसी प्रकार से ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि कल यहां पर एक प्रदर्शन होने वाला है। एक पार्टी जो दो महीने पहले बनी उसने यह जुर्रत की है और उस का सिर्फ यही कारण है कि जनता इस वक्त करों से दबी हुई है। इसलिये उसको कोई भी सहारा मिल जाय और वह उसके साथ कहां तक आने को तैयार है सरकार को यह कल मालूम होगा कि जो हजारों आदमी यहां आ रहे हैं वे उस पार्टी के अन्दर न होते भी आ रहे हैं कि उनके ऊपर करों का बोझ लदा हुआ है जिसे सरकार को बतायें।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि विकास के साथ-साथ सरकार को यह भी देखना चाहिये कि हमारी जनता की क्षमता है कर देने की या नहीं। जहां सरकार विकास करे वहां उसको यह भी देखना चाहिये कि जो उस की फिजूलखर्चियां हैं उन पर कंट्रोल हो। सरकार ने एक एस्टीमेट्स कमेटी बनायी जो उसके खर्चों पर नियन्त्रण रख सकती है। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मैं उसका मेम्बर हमेशा से रहा हूं और अब भी हूं। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उसकी ९ रिपोर्टें सरकार के सामने गयीं लेकिन सरकार ने एक पर भी विचार नहीं किया और न कोई उस की बिना पर संशोधन ही किया। इधर तो आप खर्चा बढ़ाते जायं और विकास के नाम पर बड़ी-बड़ी रकम मांगें और टैक्स लगायें और उधर आप फिजूलखर्ची करें। एस्टीमेट्स कमेटी ने लिखा था कि ये जो आप तीन-तीन और चार-चार चीफ़ इंजीनियर्स रखे हुए हैं डिपार्टमेंट्स में वे कम होने चाहिये। और भी बहुत सी सुपरफ्लुअस पोस्ट्स उसने बताई थीं लेकिन कोई नतीजा नहीं दिखाई दिया। जब सरकार उसकी रिपोर्ट पर कोई विचार ही नहीं करती तो ऐसी कमेटी के होने से लाभ ही क्या? फिर मैं यह कहूंगा कि सरकार ने कमिश्नरों की जगहों के लिये कहा था कि ये सुपरफ्लुअस हैं। लेकिन हम देखते हैं इस बजट में कि पहले जितने कमिश्नर्स थे उतने ही अब हो गये। मुख्य मंत्री हैं, मंत्री हैं, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हैं, इतने दौरे ये करते हैं, तो क्या फिर भी जिलों की चेकिंग नहीं हो पाती? हमारे पूज्य मुख्य मंत्री साहब की भी यही इच्छा थी कि कमिश्नरों को कम किया जाय। लेकिन समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों अब १० कमिश्नर रखे जा रहे हैं। और यही नहीं, उनके साथ ९ एडिशनल कमिश्नर्स भी रखे जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने कमी करने के लिये जो एक कमेटी बनायी थी उसका भी कोई पता नहीं है। वह कमेटी कहां गयी, उसकी क्या रिपोर्ट है और कौन से महकमों में कमी की जाय। सेक्रेटेरियट में देखिये और ऐस्टीमेंट कमेटी में मसला चल रहा है आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी का। इसके पास कुछ काम नहीं है। एक ऐक्स्ट्रा आफिसर रखने के लिये ही यह जगह है। जब हमारी सरकार का यह कहना है कि कर्जा लेकर या और तरह से रुपया लेकर सरकार विकास का कार्य करे तो वहां सरकार का यह भी फर्ज है कि गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का एक पैसा भी फिजूल खर्च न हो और हर सदस्य का फ़र्ज है कि वह भी इस पर गौर करे।

अध्यक्ष महोदय, विकास के लिये जो रुपया रखा जाता है, उसके संबंध में माननीय विष्ट जी ने कहा था कि विकास तभी हो सकता है अगर जिले-जिले में बोर्ड बना दिये जायं और जोनल बोर्ड्स के जरिये काम कराया जाय तो अधिक काम कम पैसे में हो सकता है। मैं आपको अपने यहां का एक छोटा सा उदाहरण दे सकता हूं। होता यह है कि आपने सड़कों को लेने का निश्चय किया। हम कोई सड़क का नाम भेजते हैं लेकिन यहां दूसरी सड़क को ले लिया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सरकार सही काम को ले और जो लोग चाहते हैं उस काम को ले तो बहुत आसानी हो सकती है और रुपया भी काफी मिल सकता है। गल्ती यह होती है कि जनता कोई काम करवाना चाहती है लेकिन सरकार उसको न लेकर दूसरी योजना लेती है इसलिये उसका मन उचट जाता है। एक सड़क थी उसको जिलाधीश ने और हम लोगों ने लोगों को प्रोत्साहन दे कर बनवाया और केवल २० दिन में ६ मील लम्बी सड़क बन गयी। हमारे यहां के डिप्टी मिनिस्टर यहां बैठे हुये हैं वह जानते हैं।

[राजा वीरेन्द्रशाह]

७०,००० रुपया जमा कराया गया लेकिन क्या हुआ? श्रीमन्, पी० डब्ल्यू० डी० के मंत्री यहां नहीं हैं, उनका ऐसा हुक्म हुआ कि आज तक कोई कार्य नहीं हो सका। इसी सड़क पर कार्य तब शुरू हुआ जब हमने रुपया जमा कर दिया। जो सड़क जरूरी है उसको दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता नहीं दी गई और दो मील उसको नहीं बनाया गया। यह आठ मील का टुकड़ा है जिसमें ६ मील बन चुकी है, अगर यह बन जाती तो बंगरा से माधोगढ़ को मिला देती। यह जिला तहसील के बाद पांचवां गांव है फिर भी सरकार उसको लेना नहीं चाहती है। यहां बैठकर जो भी मर्जी होती है वह सड़क ले ली जाती है। इस तरह से काम नहीं चलेगा। प्रान्त को चार-पांच हिस्सों में बांट दिया जाय और उनमें डेवलपमेंट बोर्ड्स बना दिये जायं। हर मेम्बर, कार्यकर्त्ता और हाकिम लोग मिलकर निश्चय करें उसको फायइनल करके विकास का कार्य किया जाय। इस प्रकार से यदि आप काम करेंगे तो अधिक सफल होंगे वर्ना आप सफल नहीं हो सकते हैं।

श्रीमन्, मैं शिक्षा के लिये जो सरकार दिनों दिन बजट बढ़ाती जाती है, उसके लिये धन्यवाद देता हूं और इसके लिये भी कि प्राइमरी स्कूलों की फीस आधी कर दी है। चाहिये तो यह था कि प्राइमरी एजूकेशन निःशुल्क हो जाती, लेकिन खैर फिर भी अच्छा कदम है। मैं इतना और अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने १०० रुपया पाने वाले सरकारी कार्यकारियों के बच्चों के लिये ११, १२ क्लास के लिये आधी फीस कर दी है तो फौज के लोगों के बच्चों के लिये भी यह सुविधा दी जाय जो काश्मीर में या बाहर के मुल्कों में गये हैं। उनके बच्चों की फीस हाई स्कूल तक बिल्कुल माफ होनी चाहिये। हर मुल्क में जो लोग आगे काम करते हैं उनको रियायत होती है। हम चाहते हैं कि जो डिफेन्स फोर्सेज में काम करते हैं उनके बच्चों की फीस माफ होनी चाहिये।

दूसरी चीज यह अर्ज करना है कि जो डेवलपमेंट के कार्य किये जाते हैं और उनमें देर होती है इसका एक कारण यह भी है जो अभी बताया आपने कि यहां हेडक्वार्टर्स से आर्डर जाने में या उनके लिये रुपया मंजूर होने में देर हो जाती है। इसी तरह से और डिपार्टमेन्टों का मामला है कि वहां दिन प्रतिदिन भर्ती हो रही है। श्रीमन्, मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि प्लानिंग कमेटी में जो मेम्बर्स आपने बना रखे हैं क्या वे यह चाहते हैं कि सब से सहयोग लिया जाय। मंत्री जी ने अभी कुछ रूल्स बदले और उनके जरिये यह कोशिश की कि बाहर के लोग भी उस नियोजन कमेटी में आ जायं। मैं इसके लिये उनका आभारी हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिनको सरकार नामजद करती है उनको अगर देखा जाय तो वह लोग वही होते हैं कि जो वहां से होने चाहिये। वही लोग यहां आकर मिलते हैं और उनकी नामजदगी हो जाती है। यह नहीं देखा जाता कि कौन आदमी कितना सहयोग देता है और स्वतंत्र राय जिलाधीशों की क्या आती है। मैं यह कहता हूं कि नियोजन कमेटी के मंत्री जी अगर इसमें ध्यान देंगे तो सब लोगों का सहयोग मिल सकता है और उसके बाद उनका कार्य और अधिक सुगमता से चल सकेगा।

श्रीमन्, अन्त में यह कहना चाहता हूं कि आपने यह कहा कि हमने अन्न की समस्या इस देश में हल कर ली। मैं श्रीमन्, यहां यह कहना चाहता हूं कि अन्न की समस्या जैसे आप समझते हैं वैसे हल नहीं होती है। जो असुविधायें आज लोगों को हो रही हैं उनको आपको दूर करना चाहिये। आज हमारे जिले में गेरुआ लग जाने से जो फस्ल नष्ट होती है और उसके लिये किसान अगर जिलाधीश के पास जाते हैं तो आपके कानून में कुछ ऐसा है कि उसके नुक्सान को लिखा नहीं जाता है। ओले का नुक्सान लिखा जाता है, लेकिन गेरुआ से हुआ नुक्सान लिखा नहीं जाता है। तो आप देखें कि जब किसान को नुक्सान होता है तो उनके नुक्सान का ऐलान होना चाहिये और साथ ही रेवेन्यू माफ होना चाहिये, उनके इरिगेशन रेट्स में कमी होनी चाहिये, क्योंकि रेट्स इतने बढ़े हुए हैं कि जिसकी वजह से कोई आदमी जरा सी तकलीफ होने से परेशान हो जाता है। अभी यह कहा गया कि जमींदारी एबालिस कर दी गयी और उसके लिये कहा गया था कि जमींदारों को, जिनकी

जमींदारी ली गयी है, हम एक साल में बांड्स दे देंगे। मैं श्रीमन्, आपके जरिये से सरकार से कहना चाहता हूं कि वैसे ही आपने उनकी आमदनी १/५ कर दी है और अब बांड्स की हालत यह है कि उनकी क़ीमत बाजार में ४२ रुपये ३३ रुपये तक आ गई है। मैं चाहता हूं कि उनको बांड्स समय पर मिल जायं। इसके अलावा जो रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट मिलने वाली थी उसका तो कोई पता ही नहीं। तो आप जो छोटे-छोटे जमींदारों की मदद करना चाहते थे उस सम्बन्ध में आपने कुछ नहीं किया है। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब तो यहां नहीं हैं लेकिन डिप्टी मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं, मैं समझता हूं कि वह इस बात की ओर ध्यान देंगे और छोटे जमींदारों को जो तकलीफ है अगर वह दूर कर आप उन्हें कुछ सुविधा देंगे तो वह अति उत्तम होगा।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बोलने से पहले सदस्य महानुभावों ने जो मुझे उत्साहित किया है सबसे पहले मैं उसके लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं और फिर मैं माननीय फाइनेन्स मंत्री जी और इस विभाग के कर्मचारियों को बधाई देता हूं सिर्फ इसलिये नहीं कि बजट बहुत अच्छा है। बजट तो बहुत अच्छा है, यह मैंने कई बार कहा बहुत से मेम्बरों ने कहा, किन्तु कल विरोधियों ने भी बजट की तारीफ की। मेरे मित्र श्री गेन्दासिंह जी ने भी पहली बार धन्यवाद दिया बजट बनाने के लिये, उन कर्मचारियों को, मैं भी धन्यावाद देता हूं। यह बड़ी खुशी की बात है। "बात सच्ची है वह तो लब पै सदा आयेगी।" असल में मुखालिफ पार्टी में बैठने की वजह से कुछ लोग विरोध ऐसा करते हैं वर्ना दिल से वह भी पसंद करते हैं, और मानते हैं कि बजट अच्छा है।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट के सिलसिले में बहुत गहराई तक और डीप जाकर में हर पहलू पर अर्ज नहीं करूंगा। क्योंकि यह बहुत मोटा बजट है। बहुत से पहलू हैं अगर हरएक पर कुछ कहने लगूं तो किसी पर भी नहीं कह पाऊंगा। इसलिये मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं मगर जरा डरता भी हूं कि लोगों को कुछ मेरी बात खटक न जाय। लेकिन एक तरफ अगर खटकने की परवाह है तो दूसरी तरफ पब्लिक की भलाई है। इस कारण मैं इस बात की परवाह न करके कि किसी को यह बात खटकेगी या नहीं जनता की भलाई के लिये मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन का काम अच्छा होने के लिये सेशन नैनीताल में भी हुआ करे। उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी सेशन नैनीताल में हुआ करता था एक बार कांग्रेस सरकार के जमाने में सेशन नैनीताल में हुआ था। अब इधर जब से हाउस बड़ा हो गया तो वहां पर सेशन होना बन्द हो गया। मेरी प्रार्थना है कि इस पहलू पर अगर ध्यान दिया जाय और वहां पर काम किया जाय तो इस सदन का काम ज्यादा और अच्छा हो सकेगा। आप गौर फरमायें अक्सर जब कानून बनता है तो वह जल्दी में बनता है कहा जाता है कि जल्दी से इसको पास करो। कानून बना तो उसके बाद शीघ्र ही तरमीम आ जाती है और उसको चेन्ज तथा परिवर्तन करने के लिये संशोधन लाते हैं। वहां पर, नैनीताल में इतमिनान से बैठकर काम हो सकेगा कहा यह जाता है कि। वहां पर जाने से ज्यादा पैसा सर्फा होगा और जनता में गलतफहमी पैदा हो सकती है कि कल तक तो यह कांग्रेस वाले इसका विरोध करते थे और अंग्रेजों से कहा करते थे कि वहां न जाओं और आज खुद ही हजरत वहां पर मौज करने के लिये चले गये और वहां पर घूम रहे हैं। यह गलतफहमी पैदा करके नाजायज फायदा उठाया जा सकता है। इसके उत्तर में मेरा निवेदन यह है कि कमेटीज के सम्बन्ध में करीब-करीब सभी सदस्य माननीय मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहबान वहां जाते हैं। तो हजूरवाला जरा गौर फरमायें कि मेम्बर साहबान दूर दूर से वहां जाते हैं और दो दिन के लिये २००,१५० और १०० रुपया खर्च कर दिया जाता है। दो दिन के लिये इतना पैसा खर्च कर दिया जाय यह कौन सी अक्लमन्दी है। दूर से बुलायें ज्यादा खर्च करें और उसका फायदा भी न उठाया जाय यह

[श्री सीताराम शुक्ल]

कहां कि अक्ल की बात है ? जो गर्मी के दिन सदन में बैठ कर काम करने के होते हैं उनमें आप कहते हैं कि जाओ लेक्चर दे आओ और देहातों में घूमो । उन दिनों देहातों में घूमने में सिर्फ नेताओं को ही तकलीफ नहीं होती है बल्कि जो सुनने के लिये वहां पर आते हैं उनको भी तकलीफ होती है । ३,४ मील के फासले से लोग वहां पर सुनने के लिये आते हैं और फिर वापस जाते हैं तो गर्मी के मौसम में उनको बड़ी तकलीफ होती है और जब जाड़ा रहता है और घूमने का समय होता है तब कहा जाता है कि लखनऊ में बैठ कर काम करो, यह कहां की अक्लमन्दी है ? यह मुनासिब नहीं है। मेरी गुजारिश है कि इस उसूल पर गम्भीरता के साथ विचार किया जाय । आप जानते हैं कि इस सदन के माननीय मेम्बर बदायूं जिला के श्री तुलसीराम जी जान दे बैठे, वह लू के शिकार हो गये किसी को भी प्रकृति माफ नहीं कर सकती है । अगर आप हमसे ज्यादा गर्मी में बाहर घूमेंगे तो जरूर बीमार पड़ेंगे और जान जा सकती है इसलिये मेरी गुजारिश यह है कि इस पहलू पर और फरमाया जाय ।

दूसरा पहलू यह है कि वहां पर स्थान की कमी है। मेरी प्रार्थना है कि अगर वहां पर जगह कम है और रहने के लिये स्थान नहीं है तो क्या यह सरकार ५०० आदमियों के रहने के लिये इन्तजाम नहीं कर सकती है यह ताज्जुब की बात है। इससे यह मालूम हो सकता है कि सरकार को दिलचस्पी नहीं है। गवर्नमेन्ट चाहे तो वहां पर इन्तजाम हो सकता है। गवर्नमेन्ट चाहे तो वहां पर शहर बसाया जा सकता है, सरकार नया कैपीटल बना सकती है । कुछ बैरक्स बनाना कठिन नहीं है । मुझे आप आज्ञा दें ठेकेदारों में भी बहुत से देशभक्त हैं वे लोग बिना मुनाफा लिए वह मकान बना देंगे, मैं यह करा सकता हूं। उन लोगों ने मुझ से कहा है कि सरकार हमें नक्शा बना कर दे दे और हम काम करेंगे । वे सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि नैनीताल उजड़ने से बच जाय । मेरे पहाड़ी दोस्त यहां बैठे हैं वह इसमें हमारी सहायता करेंगे शामियाने, टेन्ट और झौपड़े भी बन सकते हैं। हमें १५ रुपया रोजाना न दीजिये जो पैसा यहां खर्च होता है वही वहां भी करिये । अब रही गलतफहमी की बात । कहा जाता है कि विरोधी दल इससे गलतफहमी जनता में पैदा करेंगे । तो विरोधी पक्ष तो प्रचार करेगा ही चाहे जितना अच्छा काम सरकार करे । क्या ये लोग लखनऊ के कूलर खस की टट्टी के लगने पर प्रचार नहीं करते हैं ? लेकिन हमें यह देखना है कि इनका प्रचार ठीक है या नहीं या हमारा कार्य ठीक है या नहीं । अगर उनका प्रचार गलत है और हमारा रास्ता सही है तो फिर प्रचार की परवाह कर के काम तो नहीं बिगाड़ा जायगा । एक ओर तो हमारे सामने पब्लिक का काम है और दूसरी तरफ गलतफहमी से बचना है तो कैसे काम चलेगा ? हमने पढ़ा था कि 'लोकापवादात भयम' अर्थात बदनामी से डरना चाहिये, पब्लिक ओपीनियन पर ध्यान देना चाहिये । एक शेर कहूं— "सुन तो जरा जहां में है तेरा फिसाना क्या, कहते हैं तुझे खल्के खुदा गायबाना क्या ।" मगर एक वक्त आता है कि सारा जमाना खिलाफ है फिर भी वह काम किया जायगा । राजनीति में अगर सबकी हम सुनते जावेंगे तब तो काम भी नहीं चलेगा । भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है—

"सशक्ताः कर्मणय विदवान्सो यथा कुर्वन्ति भारत । कुर्यात विद्वास्तथा शक्तश्चिकीर्षु लोक सगंग्रहम् ।"

भावार्थ कि जिस प्रकार दुनियां में फंसा हुआ आदमी अपने लिये काम करता है उसी प्रकार संसार के लिये तुम भी काम करो किन्तु संसार के कल्याण के लिये मैं एक उदाहरण दूं। डकैती और कत्ल से बढ़कर इस दुनिया में क्या अपराध बड़ा है ? लेकिन भगतसिंह ये दोनों करते थे और आज उनकी तस्वीर हर जगह टंगी हुई है। क्यों लोग उनका इतना आदर करते हैं ? क्योंकि उनकी नियत अच्छी थी । वह ऐसा करके देश सेवा ही करते थे।

श्री शिवनारायण—मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है कि माननीयसदस्य ने हमारे उस शहीद के लिये डकैत और कातिल कहा है। वे इन शब्दों को वापस लें।

श्री सीताराम शुक्ल—मैं दलील दे सकता हूं लेकिन समझने की अक्ल नहीं दे सकता। मैं कहता हूं कि वह तपस्वी थे और त्यागी थे, परन्तु आप क्या समझ रहे हैं? अगर पहाड़ पर जाना ऐश कहा जा सकता है तो लखनऊ में खस की टट्टी लगा कर, कूलर लगा कर रहना भी ऐश है। आप किसान को इतना बुद्धू क्यों समझते हैं कि वह विरोधी पक्षवालों के गलत प्रचार में फंस जायगा। वह जानता है कि हम लोग उसकी भलाई के लिये ही काम करते हैं। अन्त में मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूं—

"निन्दन्तु नीति निपुणः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्
अद्यैववा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदन्न धीराः।"

अर्थात् नीति जानने वाले लोग प्रसंशा करें या निन्दा, धन हमेशा रहे या फौरन चला जाय, लाखों वर्ष जिन्दा रहें या अभी मर जायं किन्तु धीर लोग न्याय के रास्ते को नहीं छोड़ते। यह श्लोक पढ कर दिल खुश करने के लिये नहीं है बल्कि उस पर चलने के लिये भी है। देखना यह है कि नैनीताल जाने से किसानों की भलाई होगी या बुराई, बुराई हो तो हरगिज मत जाइये। इसी सिलसिले में यह भी अर्ज कर दूं कि नैनीताल वह स्थान है कि जिसने माननीय पंडित पन्त जी ऐसा नेता दिया है, जो दिल्ली में हमारे गृह मंत्री हैं और संसार में हिन्दुस्तान का नाम उज्जवल कर रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति होने के बाद मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप नैनीताल के लोगों की दशा अंग्रेजी राज्य से भी खराब बनावेंगे? यदि नहीं, तो गर्मी में वहीं सेशन कीजिए ताकि वहां के मजदूरों को चार पैसे मिलें और व्यापारियों की हालत भी खराब न हो तथा कानून भी अच्छे बनें।

*श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, मैं सदन के माननीय सदस्यों से क्षमा चाहूंगा यदि मैं यह कहूं कि इस अवसर पर बजट पर विचार करते हुये मेरा दृष्टिकोण बजट की आमदनी और खर्च पर नहीं है या मैं इस बजट को खर्च और आमदनी के खाते की दृष्टि से नहीं देख रहा हूं। बजट किसी सरकार की पालिसी का प्रतीक होता है। हमें देखना यह है कि सरकार किस आधार पर चल रही है तथा उसके प्रयास सोसाइटी को किस ओर ले जा रहे हैं? सरकार का ध्येय क्या है? जहां तक सोसाइटी को किसी मंजिले मकसूद पर ले जाने का उद्देश्य है, मैंने इस सदन में और बाहर भी अपने मित्रों के बड़े-बड़े व्याख्यान सुने हैं। मैंने सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का जिक्र सुना, मैंने करांची के कांग्रेस के रिजोल्यूशन का जिक्र सुना, मैंने बम्बई के प्रस्ताव का जिक्र सुना, मैंने कांग्रेस के मैनीफैस्टो और कम्यूनिस्ट या कम्यूनिस्ट कानसैन्शस आफ सोसाइटी का भी और सोशलिस्ट का भी जिक्र सुना। मैंने इन सब बातों को पढ़ना और समझना चाहा। जितना भी मैंने गौर से सुना और समझना चाहा तो मैं इसमें से केवल एक ही नतीजा निकाल सका और वह यह कि आजकल के जमाने में कोई भी प्रगतिशील प्रदेश अथवा देश वही हो सकता है, चाहे वह सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी के नाम पर हो, चाहे वेलफेयर स्टेट के नाम पर हो, चाहे कम्युनिस्ट अथवा सोशलिस्ट विचाराधारा के ऊपर हो, लेकिन उसको देखने के लिये हमारा मापदंड यह होना चाहिये कि कामन मैन को उसमें उठने की गुंजाइश है या नहीं, गिरे हुये व्यक्ति को फिर से उठने के लिये सहारा है या नहीं और मानवता का इस बजट में कहीं तिरस्कार तो नहीं हुआ है। जब मैं इस मापदंड से इस बजट को देखता हूं तो श्रीमन्, और चाहे जो कुछ कहा जाय लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि बजट अवश्य ही इसका प्रतीक है, हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं, देर हो सकती है, हमारी चाल धीमी ही क्यों न हो लेकिन कभी न कभी हम अवश्य ही मंजिले मकसूद पर पहुंचेंगे।

श्रीमन् चाहे सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी हो, या सोशलिज्म ही क्यों न हो लेकिन मुझे यह देखना है कि प्रत्येक सरकार का ध्येय क्या होना चाहिये, जिससे कि हर एक व्यक्ति को यह पता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

चल सके कि इस बजट में यह झलक है कि सरकार सोशलिस्ट पैटर्न की ओर अथवा सोशलिज्म की ओर जा रही है, उसका सबसे पहला प्रयत्न यह होना चाहिये कि वह एम्प्लायमेंट की तरफ कदम बढ़ाये। यह हो सकता है कि उसमें कुछ देर लगे, लेकिन किसी न किसी समय उस गोल (ध्येय) पर पहुंच जाना चाहिये। इसका दूसरा मापदंड यह है कि उसमें सोशल इक्वेलिटी अथवा फ्रीडम की ओर कदम बढ़ाया गया है अथवा नहीं ? तीसरा मापदंड यह है कि प्रोडक्शन और वितरण में कोई संतुलन है या नहीं और चौथा यह है कि पब्लिक सेक्टर का विकास हो रहा है अथवा नहीं। जब मैंने इन चार मापदंडों से इस बजट को देखा तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं और विरोधीदल के लोग भी इस बात को मानेंगे कि इसमें सरकार की नीयत पर आक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं है चाहे उसके मैथड पर कितना ही आक्षेप क्यों न किया जा सकता हो। जब लोग कहते हैं कि सरकार का यह कहना गलत है कि उन्होंने सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी को कायम करने की ओर कदम बढ़ाया है, जबकि रिक्शा वाले बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लाइमेंट बढ़ रहा है, वे हमेशा तस्वीर का एक ही रुख देखते हैं। वे यह नहीं देखते कि सरकार ने ऐपीडेमिक्स को रोका है, पब्लिक की हैल्थ को ठीक करने का प्रयत्न किया है, लोगों की जानों की फिक्र की है, लड़ाई दंगों को रोका है, चार को रोका है। तो क्या इसके विरुद्ध विरोधीदल के लोग यह कहना पसन्द करेंगे कि जब तक फुल एम्प्लायमेंट का इन्तजाम न कर लो, गरीब जनता को भूखों मरने दो, जब तक हर आदमी एम्प्लाइड न हो जाय, तब तक इस बात की भी कोशिश न करो कि जनता जिन्दा भी रहे या न रहे। लेकिन श्रीमन्, मानवता की सरकार ऐसा नहीं कर सकती। उसको पहले अपनी जनता के जीवन का ख्याल रखना होगा, जनता के स्वास्थ्य को बनाना होगा और उसके साथ ही साथ धीरे-धीरे वह एम्प्लायमेंट को भी बढ़ाने का प्रयत्न करेगी। सोशल इक्वेलिटी और सोशल फ्रीडम को पूरी तरह से प्राप्त करने में श्रीमन्, यह हो सकता है कि ७–८ साल लग जायं लेकिन सब लोगों को यह भी मालूम है कि उसके रास्ते में क्या-क्या दुश्वारियां हैं, यह भी किसी से छिपी हुयी बात नहीं है। रही पब्लिक सेक्टर की बात। क्या हम उद्योग में या इंडस्ट्री में ऐसा प्रयास तथा प्रयत्न नहीं कर रहे हैं कि हम पब्लिक सेक्टर का विकास करें।

श्रीमन्, मैंने अपने नेता विरोधी दल का भाषण सुना और जिस समय उनका भाषण आरम्भ हुआ मुझे उनकी तरफ से यह बड़ी आशा सी हुयी थी कि जिस तरह की सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी बनाना चाहते हैं वह हमें बतायेंगे और हमें उससे लाभ होगा और उसकी रूपरेखा उनसे सुनने को मिलेगी कि कौन-कौन सी बातें बजट में भुलायी गयी हैं और कहां कौन सी चीज और रख दी जाय जिससे हमारी सोशलिस्टक पैटर्न आफ सोसाइटी की तस्वीर पूरी हो जाय। लेकिन मुझे खेद है कि जैसे-जैसे उनका भाषण आगे बढ़ता गया हमारी निराशा बढ़ती गयी। अन्त में हमने देखा कि वह अनुदानों में उलझ गये और उन्होंने कोआपरेटिव से गन्ने तक हर चीज कह डाली लेकिन खेद है कि उन्होंने यह बताने की कृपा नहीं की कि तुम्हारी सोशिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की तस्वीर में उसके ढांचे में कहां गलती है, कहां किस चीज को हटाकर क्या चीज रखने से सोशलिस्टिक पैटर्न पूरा हो जायगा। मेरा कहना यह है कि आज का जो हमारा प्रयास या प्रयत्न है, हमने जिस प्रकार से हुकूमत के ढांचे को बनाया है, उसमें रफ्तार जरूर धीमी रहेगी, प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी में यह नहीं हो सकता कि हम तेज रफ्तार से कोई काम कर डालें। मैं तो प्रजातंत्र की प्रगति की रफ्तार का हाथी की चाल से मुकाबिला करूं तो ठीक होगा, जिस तरह से हाथी अपनी अद्भुत मस्तानी चाल से चलता है, रास्ते में मिट्टी हो या पत्थर सब को रौंदता हुआ, बच्चे चिल्लाते हों या कुत्ते भूंकते हों लेकिन वह धीरे धीरे चलता रहता है और देर में पहुंचता है लेकिन अपनी मंजिले मकसूद पर पहुंचता जरूर है। जहां तक सोशलिस्टक पैटर्न आफ सोसाइटी की बात है मैं निवेदन करूंगा कि सरकार की नियत पर जरा सा भी हमला करने की गुंजाइश नहीं है लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि केवल किसी उद्योग का सरकार का ले लेना और स्टेट की तरफ से चलाना ही काफी नहीं है और उसी

को कहना कि सोशलिस्टिक पैटर्न हो रहा है यह काफी नहीं है। यह ठीक है कि स्टेट कैपिटल वहां लगाया गया है और स्टेट कोआपरेटिव में हम आगे बढ़ें लेकिन एक बैलेंस होना आवश्यक है जैसे रोडवेज स्टेट कोआपरेटिव का है और उस में आज सरकारी कर्मचारी लगे हुये हैं, लेकिन जब तक वहां का हर एक कर्मचारी यह न समझने लगे कि यह सरकारी नहीं बल्कि हमारी अपनी इंडस्ट्री है तब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। हमारा प्रयास यह होना चाहिये कि इस देश का हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा सरकारी सम्पत्ति को अपनी सम्पत्ति समझे, हमारे पब्लिक सेक्टर में हर एक वर्कर उस इंडस्ट्री को अपनी इंडस्ट्री समझे तब हम कह सकते हैं कि हम सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की ओर कामयाबी के साथ और सफलता के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उसमें कमी है और उसमें अभी कुछ देर है।

कहा जाता है कि इतने साल की स्वतंत्रता के बाद, इतना ढोल पीटने के बाद सरकार ने क्या किया ? बार-बार सरकार यह कहती है कि हमने जमींदारी खत्म कर दी और कहा जाता है कि जमींदारी खत्म हुयी इसको तो कई साल हुये लेकिन अभी तक उसका ढोल पीटा जाता है कि वह खत्म हो गयी। क्यों जमींदारी खत्म हुयी, उससे किसका भला हुआ और किसका नुकसान हुआ इस प्रश्न में न जाकर मैं कहूंगा कि उसका जो एक एफेक्ट पड़ा है उस असर से काफी मदद मिल रही है। हम सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी जिसका नाम बराबर लिया जाता है उसकी ओर चल सकें और श्रीमन्, मैं यहां तक कहूंगा कि अगर सरकार के पास जमींदारी खत्म करने के अलावा और कुछ कहने को नहीं है जैसा आक्षेप किया जाता है तो मैं श्रीमन्, अपने दाहिने ओर बैठे हुये भाइयों से क्षमा चाहूंगा कि यह कहने के लिये कि उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन आफ लैन्ड के सिवा और कुछ कहने को नहीं है। जब देखिये उनके पास एक ही आर्गूमेंट है और वह समझते हैं कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन आफ लैन्ड हो गया तो सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी कायम हो गया। मैं यह जानना चाहूंगा कि जब इस ओर से कहा जाता है और जब माननीय रेवेन्यू मंत्री जी उनसे पूछते हैं कि हमें बतलाया जाय कि आखिर वह कितनी जमीन है जो हम बांट सकेंगे और वे कितने लोग हैं जिनमें हमको बांटना चाहिये, तब मैं देखता हूं उनके पास कोई जवाब नहीं है। यदि डिस्ट्रीब्यूशन आफ लैन्ड एक नारा है तो वे लगावें लेकिन अगर वे समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन आफ लैन्ड किसी अच्छे स्थान पर, किसी मंजिल पर पहुंचने की एक सीढ़ी है तो उससे काम नहीं चलेगा।

अन्त में श्रीमन्, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा है कि कहीं बचत करके काम नहीं चल रहा है लेकिन अगर इतने बड़े बजट में फिजूलखर्ची है तो रोका जाय लेकिन उससे डेफीसिट तो कम्प्लीटली दूर नहीं होगा उसमें डेफिसिट रहेगा लेकिन श्रीमन्, मैं अदब के साथ यह निवेदन करूंगा कि बचत एक आना भी अगर हो या बचत इतनी कम हो कि उससे बजट पर कोई असर न पड़ता हो लेकिन वे कृपया इसके साइकालोजिकल असर को न भूलें। जैसे कि हममें से हर एक आदमी छोटे-छोटे बचत की संख्या में उसमें १० प्रतिशत और २० प्रतिशत भाग देने लग जायं। मान लीजिये हममें से हर एक यह तय कर लें कि जब तक पंचवर्षीय योजना खत्म नहीं हो जायगी तब तक हम नैनीताल नहीं जायेंगे या हम समितियां नैनीताल में नहीं करेंगे। मुझे नहीं मालूम कि दो महीने का नैनीताल का सीजन होता है, क्या आवश्यकता है कि हम नैनीताल में समितियां करें ही ? वहां जाने के बाद सेलेक्ट कमेटी करें जुलाई में, बरसात में क्यों सेलेक्ट नहीं कर लें। मैं मानता हूं कि इससे ज्यादा बचत नहीं होगी लेकिन जो साइकालोजिकल असर हम लाना चाहते हैं तो वह साइकोलोजिकल असर पड़ेगा और जनता यह समझेगी कि हम लोगों ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये नैनीताल की ठंडी हवा खाने का भी अंत कर दिया कहा जाता है कि सेशन भी नैनीताल में होने लग जाय ? मैं तो कहूंगा कि सेशन जरूर हो, जरूर बैठा जाय लेकिन अगर हम यहां गर्मी में बैठ सकते हैं और जो हमारे मित्र कहते हैं कि नैनीताल में सेशन बैठ जाय तो काम अच्छा होगा तो मैं अनुरोध करूंगा कि जाड़े में तब तो यहां की अटेंडेंस पूरी होनी चाहिये तब तो लोग बैठें। यह बजट सेशन चल रहा है इसमें अटेंडेंस पूरी होनी चाहिये तो इस तरह से तो काम नहीं चल सकता है। मैं मानता हूं कि हम बचत कितनी कर सकते हैं, लेकिन इसका साइकलोजिकल असर होगा।

[श्री सुरेशप्रकाश सिंह]

मैं श्रीमन्, एक लफ्ज और कहूंगा और अन्त करूंगा। मैं उदाहरण के लिये शिक्षा विभाग को लेता हूं। श्रीमन् करीब १३ करोड़ रुपये हम खर्च करने जा रहे हैं और हमारे राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर हर एक एजूकेशनिस्ट और हर एक मिनिस्टर कहता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली गलत है और उसको बदलने की आवश्यकता है और बगैर उसको बदले अगर हम १३ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च कर रहे हैं तो वह रुपया फिजूल खर्च हुआ या नहीं और इस १३ करोड़ रुपये को खर्च करके हम बी० ए० निकालते हैं। जो नहीं जानते कि मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन हैं और डाक्टर राधाकृष्णन कौन हैं? इसमें प्राइमरी क्लासेज के लिये आधी फीस माफ की गयी है और उन सरकारी कर्मचारियों को जिनको सौ रुपये से कम मिलता है उनके लिये आधी माफ की गयी है लेकिन अगर १३ करोड़ रुपये और लग जायं और इन दोनों की पूरी फीस माफ कर दी जाय तो इसमें कुछ कल्याण हो सकता है।

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा सुन्दर बजट हमारे सामने पेश किया है। वैसे तो यह बजट देखने में ऐसा मालूम होता है कि चारों तरफ से इसमें प्रगतिवाद की झलक दिखायी पड़ती है। इसमें जो भाषण माननीय मंत्री महोदय ने दिया यद्यपि वह बहुत लम्बा था लेकिन वास्तव में उसकी आवश्यकता थी। बहुत सी नयी बातों का उसमें समावेश किया गया है इसके लिये हम वित्त मंत्री महोदय के आभारी हैं। मैं साथ ही माननीय नेता विरोधी दल को भी बधाई देता हूं इसलिये कि हमारे गोसाईं जी ने कहा है "अमिय सराहिय मधुरता, गरल सराहिय मीच"। माननीय नेता विरोधी दल को इसलिये बधाई देता हूं कि उनके भाषण में गहरा कटाक्ष था, ह्यूमर से मिले हुये चोट थे, लेकिन वास्तविकता से बहुत दूर भागने में बे जोड़ जिसमें अपढ़ और बजट को न पढ़ने का कोई मुकाबिला नहीं था, इन बातों में मैं उनको बधाई देता हूं। माननीय नेता महोदय ने यह कहा कि शायद हमारे मंत्री महोदय ने टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ने का कष्ट नहीं किया। सम्भव है ऐसा हो लेकिन स्पीच सुनने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है और इसमें मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि उन्होंने न तो बजट की स्पीच को पढ़ा है और न बजट को ही पढ़ने का कष्ट उठाया है। उनका यह कहना है कि बजट के अन्दर तमाम ढूंढने पर भी उन्हें समाजवादी ढांचा या इस तरह की कोई चीज नहीं दीख पड़ी। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर समाजवादी ढांचा है क्या चीज? माननीय नेता की मांग है कि शुगर मिल्स को नेशनलाइज कर दिया जाय। अगर ऐसा कोई कदम हमारी सरकार उठावे तो क्या उसको नेशनलाइजेशन या सोशलाइजेशन कहा जायगा? और अगर सरकार यह कह भी दे तब भी वह यह नहीं कहेंगे कि यह समाजवादी कदम है। अगर वे पृष्ठ ३१ देखें तो वहां पर काफी मिसालें इस बात की दी हुयी हैं कि हम धीरे-धीरे समाजवादी समाज की ओर कदम उठा रहे हैं। हमारी सरकार या माननीय मंत्री महोदय का यह हरगिज दावा नहीं है कि आज हमने समाजवादी समाज कायम कर दिया है। हम लोग तो केवल यह निवेदन कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे उस ओर कदम उठा रहे हैं। अगर हम कहें कि हम बनारस जा रहे हैं और तुम यह जवाब दो कि तुम तो यहां खड़े हो, तो आप खड़े होकर यह कैसे कह सकते हैं कि आपको हम लखनऊ में देख रहे हैं? अगर आप हमारी बातों को सुनने और समझने की कृपा करते तो आपको दिखायी पड़ता कि इसमें काफी संकेत इस बात के किये गये हैं कि हमारा जो बजट है वह किसी कदर पिछले बजट से आगे बढ़ा हुआ है।

हमने जमींदारी का उन्मूलन किया यह तो दूर की बात है। आजकल हमारे यहां सीमेंट के उत्पादन की एक फैक्टरी है वह स्टेट की है। दो और फैक्टरियां हमने कायम कीं हैं वे भी स्टेट की हैं। यातायात के लिये बसें सरकारी योजनाओं में जारी की गई हैं। साथ ही इसमें यह बतलाया गया है कि सौ रुपये से कम तनख्वाह पाने वालों का डियरनेस एलाउन्स पारसाल आधा मिला दिया गया था और इस बजट के अन्दर अब दो सौ रुपये से कम तनख्वाह पाने वाले जो आदमी हैं उनके आधे डियरनेस एलाउन्स को हमने मिला दिया

है। क्या यह कदम गरीबों की खुशहाली की तरफ नहीं ले जाता ? दो तरीके होते हैं। आज हमारे मुल्क में हजारों तरह के कारखाने कायम हैं और अभी लाखों कायम करने हैं। या तो हम इन हजारों को जो कुछ रुपया हमारे पास है उससे मुवाविजा देकर उन्हीं हजारों को नेशनलाइज कर दें या जो लाखों नये कारखाने कायम करने हैं उनको उस रुपये से इस स्टेट के अन्दर कायम करें। बदकिस्मती से हमने यह फैसला किया कि बजाय इसके कि हम अपना रुपया मौजूदा कारखानों को नेशनलाइज करने में लगावें, यह चीज हम बेहतर समझते हैं कि नये कारखाने कायम करें। इस स्टेट में कुछ दिनों में यह देखने में आयेगा कि वह जो उत्पादन है वह सोसाइटी के हाथ में आया। यह क्या सोशलिस्टिक पैटर्न नहीं है ? इसमें १३ आइटम वित्त मंत्री जी ने बतलाये हैं और उससे साफ जाहिर होता है कि हम इस ओर जोरों से बढ़ते जा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि कांग्रेस अपना ध्येय बदला करती है। एक माननीय मित्र ने कहा कि कभी कोआपरेटिव कामनवेल्थ है, कभी सोशलिस्ट स्टेट है, कभी वेलफेयर स्टेट है। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरी समझ की गलती है या कहने वालों की गलती है। एक ही चीज को अगर हम तरह-तरह के दृष्टिकोण से देखें तो वही चीज भिन्न-भिन्न दिखायी पड़ती है। कोई कहता है, अपने घर में बच्चे की मां, कोई कहता है कि बच्चों की मां, कोई कहता है कि घर की मालकिन, लेकिन चीज एक ही है। हम पर आक्षेप लगाया जाता है कि आप की स्टेट पुलिस स्टेट है। इसके मुकाबिले में हम कहते हैं कि हमारा कल्याणकारी राज्य है। कोआपरेटिव कामनवेल्थ स्टेट जो होगी वह कल्याणकारी नहीं हो सकती। वह भी कल्याणकारी है, जब हम अपने समाज के ढांचे को बयान करते हैं तो हम यह स्पष्टीकरण करते हैं कि हम सोशलिस्टिक पैटर्न की सोसाइटी कायम करने जा रहे हैं। जिस समाज को हम कायम करने जा रहे हैं, जिस तरह से हम राष्ट्र को आगे बढ़ाये जा रहे हैं, उसके आकार और कंटेंट को अगर देखें तो कोई बुनियादी अन्तर नहीं है। अपनी जनता को समझाने के लिये स्पष्टता लाने की कोशिश की है और कोई मूलतः भेद इसमें नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस बात का दुःख है कि जो कुछ भाई भाषण कर गये हैं, उन्होंने बजट पढ़ना गवारा नहीं किया। बजट में एक बड़ी खूबी की बात यह रही है कि चालू साल में यह तखमीना लगाया गया था कि ५५० लाख रुपया हमको घाटा होगा। लेकिन यह बड़ी प्रसन्नता और प्रशंसा की बात है कि हमारे वित्त मंत्री महोदय जी के परिश्रम द्वारा उस घाटे को पूरा कर लिया गया और कोई नया टैक्स नहीं लगाना पड़ा। आमदनी बढ़ायी गयी। यह भी आप खयाल करें कि इस साल में जब कि हमने बाढ़ पर ढाई करोड़ रुपया खर्च किया और २६० लाख रुपया हमने रिबेट में दिया। १२० लाख मालगुजारी माफ की। इतना होते हुये हमने पचास लाख का घाटा पूरा किया। इसके लिए माननीय वित्त मंत्री विशेष बधाई के पात्र हैं। आगे साल में यह अनुमान किया जाता है कि ९५० लाख का घाटा होगा। हमने बड़ी बड़ी योजनायें रखी हैं उनका ध्यान रखते हुये यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं दो एक बातें निवेदन करना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में अगर टैक्स लगाने की आवश्यकता हो तो मैं उसका समर्थन करूंगा। लेकिन हमारे यहां की जो अर्थव्यवस्था है उसको देख कर अभी मैं समझता हूं कि टैक्स की जरूरत नहीं है। कहा यह जाता है कि इस प्रदेश में टैक्स का इंसीडेंट और राज्यों के मुकाबले में कम है। मैं इसको नहीं मानता हूं। हमारी इस राज्य की इकानोमी जो है कृषि पर आधारित है। जहां पर पश्चिमी बंगाल, बम्बई और मद्रास में औद्योगीकरण काफी आगे बढ़ चुका है, वहां पर जो कुछ टैक्स का रुपया आता है वह बड़े आदमियों के द्वारा हासिल होता है और तमाम जनता में बांटा जाता है। नतीजा यह होता है कि उसका औसत कम दिखायी पड़ता है। हमारे यहां जो कुछ भी टैक्स की आमदनी है वह गरीब किसानों के घर से आती है।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

एक किसान जो महज तीन बीघे खेत रखता है मुश्किल से गुजर कर पाता है, पर वह यह लगान, सिंचाई–कर इत्यादि के रूप में कर देता है, यह सब जानते हैं कि

[श्री राधा मोहन सिंह]

हमारे यहां औद्योगीकरण नहीं हुआ है। बड़े-बड़े लोग नहीं हैं, जिन पर टैक्स लगा कर हम अपनी आमदनी बढ़ा सकें। हमारे यहां ऐग्रीकल्चरल इकानोमी होने के कारण ही और राज्यों के मुकाबले में देखने में हमारे यहां मालूम होता है कि हमारे टैक्स का इंसीडेंस प्रति जन कम है। आज हमारे यहां भी अगर उद्योग बढ़े होते तो ऐसा दिखायी नहीं पड़ता। लेकिन कृषि पर आधारित होने के कारण हमारे यहां टैक्स का बोझ ज्यादा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हमारे वित्त मंत्री महोदय, तथा फाइनेंस एक्सपर्ट अगर इस तरह की हमारे राज्य की एकोनामी का अध्ययन करेंगे तो मालूम होगा कि हमारे ऊपर बोझ बहुत ज्यादा है। अभी टैक्स बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हम इस बात को मानते हैं कि पंचवर्षीय योजना खत्म होने के बाद हमारे यहां की माली हालत में सुधार हुआ है। लेकिन इतना काफी नहीं है कि हम टैक्स को बढ़ाएं। हमारे वित्त मंत्री ने १९५२ में कहा था कि हम उन तमाम सुधारों को ला रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम टैक्स नहीं लगायेंगे और तभी लगायेंगे जब हमारे लोग इस काबिल हो जायं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी समझ में अभी वक्त नहीं आया है कि हम टैक्स लगाएं। कुछ इंतजार करने के बाद, हमको चाहिए कि पांच वर्ष के बाद जब हम उद्योग-धंधों में आगे बढ़ जायं, तो वह वक्त आगे आयेगा जब हम सोचेंगे कि हम अपने यहां टैक्स लगाएं। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में हमारे माननीय वित्त मंत्री और सदस्यगण जो इसमें दिलचस्पी रखते हों, इस बात को देखेंगे।

मैं दो तीन बातें और आप के ध्यान में लाना चाहता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि आप ने इस बजट के अन्दर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने की योजना रखी है। इस बात की बड़ी आवश्यकता है। हमारी सरकार जितना काम करती है उसकी जानकारी जनता को नहीं हो पाती है। अगर ठीक तरीके से काम किया जाय और अगर जनता का हम सहयोग चाहते हैं, जिसके बिना हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो मैं यह समझता हूं कि पब्लिसिटी की तरफ अपना ध्यान दें और जो भी इस सम्बन्ध में योजना बनायी गयी है मैं उसका स्वागत करता हूं।

बेकारी की समस्या के सम्बन्ध में मुझे प्रसन्नता है कि सरकार का ध्यान उस तरफ गया है। गोकि अभी एक हफ्ता पहले मैंने यहां निवेदन करते हुये कहा था कि इतनी बड़ी-बड़ी योजनाओं में लोगों को काम मिल सकेगा। परन्तु हम तो यह चाहते हैं कि हमारे पास स्वयं बेकारी की समस्या को हल करने के लिये एक योजना होनी चाहिये, जिसके आधार पर हम यह कह सकतें हैं कि पांच वर्ष के बाद कोई भी शिक्षित बेकार नहीं रहेगा। हमें बड़ा दुःख होता है कि शिक्षित ही नहीं बहुत से टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो बाहर मुल्कों से पढ़ कर आये हैं वह भी बेकार पड़े हुये हैं। इसके लिये कोई योजना नहीं है, ऐसी कोई संस्था नहीं है। मैं यह चाहूंगा कि राष्ट्रीय पैमाने पर ऐसी स्कीम होनी चाहिये कि कोई भी आदमी यह कहे कि हम काम करने के योग्य हैं, हमें काम नहीं मिलता है, यह उसे कहने का मौका न मिले। मुझे खुशी है कि इस तरफ सरकार का ध्यान गया है और आशा है कि यह मसला भी हल हो जायगा। माननीय नेता विरोधी दल ने कहा था कि हमारे यहां, यह बड़े आश्चर्य की बात है, एक ही मिनिस्टर के हाथ में सब कुछ एकत्र कर दिया गया। मुझे आश्चर्य मालूम होता है कि अगर वह इससे पहले देखें, तो जितना काम आज योजना मंत्री को दिया गया है, उससे कहीं अधिक काम हमारे मुख्य मंत्री को दिया गया था और अभी कोई शिकायत नहीं आयी। यह तो बंटवारे का मामला है। अगर काम में खराबी हो, तो सदन को पूरा अधिकार है कि वह कहे कि इसलिये काम खराब हो रहा है कि एक ही आदमी को बिठा कर इतना काम दे दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है--मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो भी योजना मंत्री ने काम हाथ में लिया है बड़ी योग्यता के साथ सम्पन्न किया है और वह सफल हुआ है।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले उन तमाम समाजवादी भाइयों को जो इस विधान सभा के अन्दर हैं और विधान सभा के बाहर भी, धन्यवाद देना चाहता हूं इसलिये कि उनकी तपस्या और त्याग का यह परिणाम है। उन्होंने राजगद्दी प्राप्त करने के बाद भी जो त्यागमय जीवन बिता कर यह परिस्थिति पैदा कर दी कि आज इस सदन में उधर भी बैठने वाले लोग जिन्होंने कभी समाजवादी के अवगुणों की चर्चा की थी, आज समाजवाद की बात करने लगे हैं। इसलिये उन तमाम समाजवादी भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके बाद, श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस समाजवाद की बड़ी चर्चा इस सदन में हुई है और जिस समाजवाद की चर्चा माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में की है उस समाजवाद की रूपरेखा की तरफ भी आप का ध्यान आकर्षित करूं। आप देखेंगे कि अपने भाषण में छठे पेज पर माननीय वित्त मन्त्री जी ने यह घोषणा की है कि यह समाजवादी योजना है और इस योजना के मातहत यह बजट हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिये यह समाजवादी है, इसे आबडी के सेशन में हमने स्वीकार किया है। श्रीमन्, आबडी के सेशन में जो स्वीकार किया जाय वह जनता की योजना है, वह समाजवादी योजना है, यह हो सकता है उधर के बैठने वाले इसे स्वीकार कर लें लेकिन आज देश पूंछ सकता है कि जिस योजना की धूम समाजवादी कह कर सारे देश और प्रदेश में आप मचाना चाहते हैं क्या उस योजना को कार्यान्वित करने के पहले आपने अपने उन योजनाकार से, उनके वैज्ञानिकों से, उनके जानने वाले शास्त्रियों से इसके सम्बन्ध में किसी भी तरह की राय ली थी, यदि इसका उत्तर मैं पूंछूं तो उत्तर यही होगा कि माननीय वित्त मंत्री जी का और उनकी सरकार का कि कोई भी राय लेने की चेष्टा नहीं की गई।

मैं एक और बात प्रस्तुत करना चाहता हूं। आबड़ी सेशन में जो प्रस्ताव समाजवादी योजना का पास हुआ और जिसके आधार पर आप फूले नहीं समा रहे हैं, क्या मैं यह पूंछ सकता हूं कि जो विधान निर्मातृ समिति, कांस्टीटयूएंट असेम्बली बैठी और उसने सबसे पहली बात जो सारे देश में लागू करने के लिये की राज्य सरकारों के संविधान में है कि अपर प्राइमरी तक निःशुल्क होनी चाहिये, क्या इस बजट में जिसे आप समाजवादी कहने का दावा करते हैं और हमारे माननीय सदस्य इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा के स्रोतों का एक वाग्जाल बिछाये हुये हैं, क्या मैं यह पूंछ सकता हूं कि आप भारत के संविधान की जो मंशा है उसके अनुकूल अपर प्राइमरी तक की शिक्षा निःशुल्क करने जा रहे हैं। आप कह सकते हैं और हमारे माननीय सदस्य डींग हांक सकते हैं कि हम अपर प्राइमरी की शिक्षा में जो आधा शुल्क है वह देने जा रहे हैं इस साल के बजट में लेकिन क्या मैं आपको याद दिलाऊं कि जो, आधा शुल्क सरकार देने जा रही है वह सरकार किसानों से सेल्स टैक्स के द्वारा उससे अधिक अप्रत्यक्ष रूप से लेने जा रही है। यदि इसी को समाजवादी कह लें तो आप इसकी डुग्गी पीटा करें, लेकिन श्रीमन,मैं यह कह सकता हूं कि यह समाजवादी नहीं है। आज का बजट समाजवादी बजट नहीं है। दुनियां आज दो विभागों में विभक्त है, समाजवादी और साम्राज्यवादी। मैं हिम्मत तो नहीं करता कि यह कहूं कि यह साम्राज्यवादी बजट है, लेकिन जब इसमें यह देखने को मिलता है कि व्यक्तिगत पूंजी को पनपने का पूरा अधिकार इस बजट में दिया गया है, जब हम देखते हैं कि बी० जी० बिड़ला के नेतृत्व में खोज होने जा रही है कि किस तरह के उद्योग इस प्रान्त में पनप सकते हैं, जब हम यह भी देखते हैं कि जो कुछ भी किया जा रहा है उसमें ज्यादा सुविधायें सरकारी कर्मचारियों के लिये उनके बच्चों और उनकी दवाओं के लिये संचित निधि उनके लिये सुरक्षित रखी जा रही है, तो श्रीमन्, यह कहा जा सकता है कि साम्राज्यवादी जो अब शेष रह गये हैं उनके पद चिह्नों पर चल कर यह बजट बनाया गया है। अगर कहा जाय तो इसे अर्बन एरिया का बजट कहा जा सकता है, इसे कर्मचारियों का बजट कहा जा सकता है, इसे सरकारियों का बजट कहा जा सकता है और यह कहा जा सकता है कि सरकारपरस्तों का यह बजट है। आप देखेंगे कि आई० जी० बढ़ रहे हैं, आप देखेंगे रोडवेज में मेम्बरों की संख्या बढ़ रही है, कमिश्नर बढ़ेंगे, पुलिस के आई० जी० बढ़ेंगे, ये सारे कर्मचारी बढ़ेंगे।

[श्री रामेश्वर लाल]

उनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी, उनके बच्चों की फीस माफ होगी, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिये प्रबन्ध होगा और नैनीताल में उनके बच्चों का प्रबन्ध होगा। तो श्रीमन्, मैं यह कहूंगा कि यह समाजवादी बजट नहीं है। समाजवादी के रूप रेखा की चर्चा के सम्बन्ध में माननीय सदस्य सुरेश प्रकाश सिंह जी ने प्रश्न पूछे और जमीन के बंटवारे की आवाज़ उठा कर श्रीमन्, उसमें उलझने के बाद अन्त में कहा कि उचित भी हमारे लिये नहीं होगा यह। एक और माननीय सदस्य ने उधर से कुछ व्याख्यान दिया और उन्होंने अपने व्याख्यान में एक्सपेंडीचर मिनिस्ट्री एक अलग विभाग कायम करने की बात कही। श्रीमन्, मैं इसका समर्थन करता हूं और मैं यह चाहता हूं कि सरकार एक ऐसा विभाग अवश्य खोले कि जो व्यय होता है उसके सम्बन्ध में वह जानकारी रखे। कम से कम उनको सुचारु रूप से प्रचलित करने के तरीकों पर अमल कराये। हमारे साथी यह आवाज़ लगा रहे हैं कि मिनिस्टर कौन होगा? इसमें आपको शुबहा नहीं होना चाहिये कि हम आपोजीशन में हैं और हम यह सुझाव नहीं दे सकते कि मिनिस्टर कौन हो। लेकिन हम यह कहते हैं कि ऐसा विभाग होना चाहिये और यह क्यों कहते हैं यह मैं अर्ज़ करना चाहता हूं। आज सरकार ने प्लानिंग के लिये, दुर्भिक्ष के लिये और अन्य विभागों के लिये रुपया दिया है। सारे प्रान्त की जानकारी तो हमको नहीं है लेकिन मैं अपने जिले की बात बतलाना चाहता हूं कि हमारे जिले में हाटा-पडरौना दो सब-डिवीजन हैं। वहां ३५ हजार रुपये गरीबों के कुओं के लिये, हैंड पम्प्स के लिये जो बांटे गये उसका जिम्मा वहां के हाकिम परगनाओं को दिया गया। सरकार से अगर पूंछा जाय कि वह रुपया व्यय हुआ तो वह कहेगी कि हां, वह व्यय हो गया क्योंकि उसके पास रिपोर्ट भेज दी गयी है कि वह व्यय हो गया। लेकिन सरकार को नहीं मालूम कि वह रुपया हाटा और पड़रौना तहसील के स्याहा खारजा में दर्ज कर दिया गया है। मैं आज भी माननीय वित्त मंत्री जी और अन्य मंत्रियों को कहना चाहता हूं कि हाटा और पडरौना के स्याहा खारजा को देखें कि गरीबों को दिया गया ३५ हजार रुपया उसमें दर्ज पड़ा हुआ है या नहीं। तो श्रीमन्, जहां तक समाजवादी बजट का सम्बन्ध है वह समाजवादी बजट नहीं है।

माननीय सुरेश प्रकाश जी ने कहा कि क्या यह सही है कि हम बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, लोगों के लिये रोटी की व्यवस्था की बातों को छोड़ दें और जो बातें समाजवादी लोग कहते हैं वही हम करें। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सुरेश प्रकाश जी यह समझ लें कि समाजवादी जहां एक तरफ यह कहते हैं कि यह समाजवादी बजट नहीं है वहां दूसरी तरफ उसका एक नक्शा भी रखते हैं और मैं कहना चाहता हूं कि जो यह साढ़े ९ करोड़ रुपया सरकार टैक्स लगाने जा रही है इसके बदले अगर वह जमींदारों को दिये जाने वाले प्रतिकर को और १५ वर्ष के लिये रोक दे तो साढ़े ९ करोड़ क्या उससे अधिक रुपया सरकार को यों ही प्राप्त हो जाय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मातहत जब बहुत से विकास के कामों की घोषणा सरकार कर चुकी है तो क्या वजह है कि गरीबों पर जो एक-एक रुपया, दो-दो रुपया, चार-चार रुपया मजदूरी करने वाले आदमी हैं उन पर तो हम टैक्स लगा दें और जो सुरेश प्रकाश जी जैसे लोग यहां बैठे हुये हैं उन पर टैक्स न लगायें और उनकी पूंजियों को बैंकों में यों ही छोड़ दें? अगर हमारे समाजवादी ढांचे को स्वीकार किया जाय तो हम यह कहना चाहते हैं कि सरकार को उन तमाम पूंजियों को जब्त करना चाहिये और उन लोगों को जिन्हें प्रतिकर के रूप में पैसा सरकार देने जा रही है वह १०–१५ वर्ष के लिये रोक दें। सरकार ऐसा करने से अधिक रुपया पा सकेगी। हमारे पास इसके नक्शे हैं लेकिन हमारे सामने मजबूरियां भी हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा श्रीमन्, कि वह जो समाजवादी ढांचे का राज्य बनाने के लिये यह कदम उठाने जा रही है उसे कम से कम समाप्त करे और उसके बाद उस रुपये की पूर्ति जमींदार लोगों को देने वाले प्रतिकर से करे। मैं

यह नहीं कहता कि उनको दिया न जाय, लेकिन १० वर्ष रोक दिया जाय और उसके बाद दिया जाय।

दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में यह जो काम हुआ है यह ठीक है कि सरकार ने समय पर कुछ काम किया है, लेकिन सरकारी अधिकारी जो जिलों में काम करने वाले हैं—मैं सबकी निन्दा नहीं करना चाहता, सब निन्दा के पात्र भी नहीं है, लेकिन मैं फिर एक घटना का जिक्र करूंगा कि जो कम्बल बांटने के लिये दिये गये थे वे आज भी देवरिया के तहसील के खजाने में सड़ रहे हैं, अभी तक बांटे नहीं गये हैं। मैं जानता हूं कि १२ से लेकर १८ तक गांव पंचायतों के चुनाव होने जा रहे हैं उस समय वह सब कम्बल बंट जायेंगे। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी कह देना चाहता हूं कि श्रीमन्, समाजवादी ढांचे में इस तरह का पक्षपात अमल में क्यों लाया जा रहा है ? जो बाढ़ आयी हमारे जिले में बहुत से गांव बह गये, भिखनापुर बह गया और वहां के लोग तबाह हुये। हमने लिखा भी था लेकिन कौन सुनता है उन पर आरोप लगाया गया कि यह समाजवादी गांव हैं, इसलिये वहां काम नहीं हो सका ? जो गांव बह गये हैं वहां लोगों को क्या मिला है ? कुल १०–२० रुपये लोगों को घर बनाने के लिये सहायता दी गई है। इस तरह का पक्षपात श्रीमन्, सरकार को नहीं करना चाहिये।

श्रीमन्, जहां तक चिकित्सा का सवाल है कि हर ५ मील के दायरे में औषधालय या अस्पताल होना चाहिये। यह जो हमारी सरकार की रूप रेखा है उस पर मुझे संतोष है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा जैसा कि आपकी मौजूदगी में मदनमोहन जी उपाध्याय ने यह बतलाया कि उनके क्षेत्र में कोई काम ऐसा नहीं हुआ है और वहां एक भी नया अस्पताल नहीं खोला गया है, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इसको कार्यरूप में लाते समय यह न सोचा जाय कि किसी पार्टी विशेष या पार्टी विशेष के नेता को ध्यान में रख कर यह काम नहीं होना चाहिये।

श्रीमन्, जहां तक रोडवेज में कर्मचारियों का सवाल है वहां हैमरमैनों में बढ़ोत्तरी की गई है। जनरल मैनेजर्स की भी बढ़ोत्तरी हो रही है इस तरह के जो जनरल मैनेजर्स हैं उनको हटाना चाहिये जैसे कि रेलवे में हैं उस तरह की व्यवस्था करना चाहिये। कंडक्टर्स और ड्राइवर्स के संबंध में २० प्रतिशत को स्थायी करने की बात की गयी है। जो आरोप लगाकर निकाले जाते हैं उस तरह की बात नहीं होनी चाहिये। रेलवे को भी देखिये वह भी तो सेंट्रलाइज्ड है और वहां पर भी काफी काम होता है वहां क्यों नहीं यह बात होती है। वहां इसलिये नहीं होता है कि वहां के लोग मुस्तकिल हैं, इसलिये यहां के लोग भी मुस्तकिल किये जायं। वह आरोप लगाये जाते हैं और उनको निकाला जाता है इसलिये कि वह मुस्तकिल नहीं होते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को इधर ध्यान देना चाहिए।

श्रीमन्, अंत में मैं सरकार से कहूंगा कि यह सही है कि आपने लखनऊ में भातखंडे विद्यालय खोल रखा है और जो हमारे साथी शहीद हुये हैं उनके स्मारक बनाने के लिये जो रकम रखी गई है उसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं। मैं यह चाहूंगा कि जिलों में जो शहीद हुये हैं उनके लिये जिले के लोग अगर स्मारक बनवाना चाहें तो उन्हें कुछ रुपया रखा जाय जो इस अनुदान में दिया जा सके जिससे वह इच्छानुकूल स्मारक बनवा सकें।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, हमारे उस तरफ के मित्र को ३० मिनट का समय मिला था क्या मुझे भी उतना ही समय मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष—मेरे पास दोनों तरफ के एक दो आदमियों की सूची आयी है कि एक दो को इधर से और एक दो को उधर से २० मिनट का समय दे दिया जाय। इस प्रकार अधिक समय देने की छूट मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिये। मैं आपके भाषणों को देखकर और सुन कर बीच में समय दे दूंगा।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—तब तो मुझे आशा है कि अधिक मिल जायगा। मान्यवर मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी को उनके बजट पर बधाई देता हूं। मैं केवल परम्परागत बधाई नहीं देना चाहता हूं किन्तु श्रीमन्, थोड़ी बहुत जो कुछ मुझे जानकारी है उसके आधार पर मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि यह बजट कई दृष्टियों में बहुत मौलिक है। पहली बात तो यह कि जो चीज उसमें है वह बहुत ही साफ शब्दों में है और हर एक परिस्थिति को रख दिया गया है। यह बहुत साहस की बात थी कि उन्होंने ४८-४९ से लेकर तुलनात्मक आंकड़े १९५४-५५ तक के दे दिये हैं। यह भी बड़े साहस की बात थी कि उन्होंने अपने भाषण में प्रदेश की समूची परिस्थिति पर वास्तविक प्रकाश भी डाल दिया। मुझे खेद है श्रीमान् कि इस बजट के विषय में जो वादाविवाद हुआ उससे कुछ मेरी जानकारी विशेष नहीं बढी। मैं बधाई देना चाहता हूं आपके द्वारा एक सदस्य को, नारायणदत्त तिवारी को, जिन्होंने वास्तव में एसा कुछ कहा जिससे हमको कुछ सोचने और समझने का मौका मिला। मुझे बड़ा खद हुआ माननीय गेंदा सिंह जी के भाषण को सुन कर। आज के जमाने में, प्रजातंत्र में कोई भारत की परिस्थिति से यूगोस्लाविया जैसे छोटे से ४० लाख आबादी वाले देश की तुलना करे, मैं समझता हूं कि यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। आज के जमाने में जब कि हम भारत में हर एक पहलू पर भ्रष्टाचार के देखने की बात सोचते हैं, जब हम देश को बना रहे है, ऐसे समय रूस और चीन से इसकी अनायास तुलना करना वांछनीय नहीं मालूम होता। श्रीमन्, बड़े हर्ष और संतोष की बात है कि अपने महान् और थोड़े से शासनकाल में हमने जो कुछ भी भ्रष्टाचार देखा है वह उन देशों के मुकाबिले में जो ३०-३० वर्षों से प्रजातंत्रीय शासन चला रहे है, बहुत कम है और कम से कम हमें अपने से असंतोष नहीं होना चाहिये। अभी जब बुल्गानिन महोदय यहां आये थे तो उन्हीं दिनों भ्रष्टाचार के कारण ६ आदमी रूस में गोली से मार दिये गये। तो इसमें इन देशों की तुलना करना अनावश्यक है। आवश्कता इस बात की है कि हम ठंढे दिल से इस बात को सोचें और देखें कि वास्तव में प्रदेश की क्या-क्या आवश्यकतायें हैं।

माननीय नारायणदत्त जी ने तीन, चार बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया। मैं समझता हूं कि कुछ उनको भ्रम हो गया। पहली बात तो यह कही गई कि हमारे बजट के १४७ करोड़ के पूरे आंकड़े गलत हैं, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। १४७ करोड़, जिसको कि उन्होंने १३७ करोड़ सिद्ध करने का प्रयास किया, वास्तव में १४७ करोड़ ही है। ४२ करोड़ ९८ लाख कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ९४ करोड़ ९१ लाख रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और ९ करोड़ ५० लाख लोन्स और एडवांसेज हैं, जो गवर्नमेन्ट देगी। इन तीनों का जोड़ १४७ करोड़ के अलावा एक पाई भी कम नहीं होता।

दूसरी चीज जिसके बारे में उनको भ्रम हुआ वह थी इरिगेशन डिप्रिशियेशन फंड की बात। उन्होंने कहा कि वह १ करोड़ ५० लाख से घट कर ३० लाख रुपया हो गया है। मैं उन्हें बता दूं कि १ करोड़ ५० लाख की जो रकम १९५०-५१ में उन्होंने पढ़ी उसमें हाइडिल की रकम भी शामिल थी। उस समय नियम यही था कि हाईडिल और इरिगेशन, दोनों का फंड एक में रहा करता था। अब दोनों अलग अलग हैं, चुनांचे ३० लाख इरिगेशन का और १ करोड़ ५४ लाख हाईडिल का है। असल में घटने के बजाय यह रकम काफी बढ़ गई है।

तीसरी एक और शंका माननीय नारायण दत्त जी की थी और उन्होंने कहा कि कंसालिडेटेड फंड में ऐसा क्यों नहीं कर दिया गया कि ओपनिंग बैलेन्स दे दिया जाय। कुछ उन्होंने यह भी सलाह दी कि हमको अपने बजट को नये ढंग से बनाना चाहिये। मैं नहीं जानता कि किस प्रदेश का बजट नये ढंग से बनता है। देश और विदेशों के बजट की थोड़ी बहुत जानकारी मुझको भी है और उसी के आधार पर श्रीमान्, मैं निवेदन

कर सकता हूं कि परपरागत जो प्रणाली है उसमें भारत का बजट और देशों की तुलना में बहुत स्पष्ट है और इसके अलावा एक बात और । हम बजट बनाने के तरीके स्वयं नहीं निर्धारित कर सकते इसका तरीका आडीटर जनरल निर्धारित करता है। वह मदें देता है, वह नियम बनाता है और उन्हीं नियमों के अनुसार हमारी सरकार को चलना पड़ता है । इसलिये इस प्रकार का जो भ्रम है वह भी गलत है ।

एक बात जो बहुत कुछ अखबारों में भी मैंने पढ़ी, इस सदन में भी कही गई, सुन कर मुझे खेद हुआ । नारायण दत्त जी ने भी उसका जिक्र किया । वह यह है कि हमारे प्रदेश का ऋण भार १३२ करोड़ बढ़ गया है। मैंने भी चेष्टा की कि १३२ करोड़ रुपया खोजूं कि कहां से निकल आया ? सन् १९५०–५१ में उत्तर प्रदेश का ऋण भार छपे बजट के अनुसार ६१ करोड़ था और सन् १९५५ में १३ करोड़ कहा जाता है उसको गौर से पढ़ना पड़ेगा । पढने से मालूम होगा कि १३ करोड़ ७१ लाख की जो रकम उस ऋण भार में है वह वही रकम है जो कि प्राविडेंट फंड की डिपाजिट है । लोकल बाडीज ने गवर्नमेन्ट के पास जमा कर रखा है, सिविल डिपाजिट है इन तीनों रकमों को जोड़ें तो १३ करोड़ ७१ लाख होता है। इसको बाद कर दिया जाय तो ३२ करोड़ ३२ लाख रुपया इस समय का ऋण भार होता है और यही चीजें निकालने के बाद १९३ करोड़ जो आप समझे हैं उतना ऋण भार नहीं रह जाता है और वह इसलिये नहीं है कि उन्हीं तीन मदों को उसमें फिर बाद कर देना पड़ेगा और इसके साथ ३६ करोड़ रुपया कम्पन्सेशन बान्ड का है । कम्पन्सेशन बांड की रकम सबको मालूम है कि रेवेन्यू से पेमेन्ट होती है। इन दोनों रकमों को निकालने के बाद १९३ करोड़ ऋण का भार न होकर केवल ७१ करोड़ ऋण रह जाता है । तो गलत सोचने से क्या लाभ है ? उत्तर प्रदेश का ऋण भार ७१ करोड़ रुपये से अधिक नहीं है । उसमें एक चीज और सोचने की होगी कि इसमें ३० करोड़ १ लाख रुपया १९५५–५६ में केन्द्रीय सरकार का भी गिना गया था जो कि प्रोडेक्टिव एक्टीविटी के लिये दिया गया था, ऐसे कामों के लिये जिनके करने से आमदनी हो। फिर वह रकम बढकर ३० करोड़ ७६ लाख हो गयी । तो फिर वह प्रोडेक्टिव एक्टीविटीज का ऋण है तो कौन कहेगा कि यह अवाञ्छनीय ऋण है ? इन तीन चार चीजों को समझ लेने के बाद मैं समझता हूं कि शायद बजट को समझने में आसानी होगी । इसके बाद मैं २–३ बातें और निवेदन करना चाहता हूं ।

बहुत कुछ हमारे यहां कहा गया कि १९४८–४९ के आंकड़ों की तुलना क्यों की जाती है ? पर कैपिटा इनकम उनके द्वारा क्यों निकाली जाती है ? मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा देश है जिससे इन ६, ७ वर्षों को तुलना के अलावा और जल्दी के वर्षों से तुलना की जाती हो और जिसने तुलनात्मक आंकड़े प्रकाशित किये हों और उसमें उसने १९५२–५३ के आंकड़ों को आधार माना हो ? चीन की एक रिपोर्ट मुझको पढ़ने को मिली। उसने ४६–४७ से तुलना की है । उनकी बात को जाने दीजिये । उसमें केवल प्रतिशत की तुलना उन्होंने की है, वास्तविक प्रोडक्शन की तुलना नहीं की है, उसको आप जाने दें । इसके अलावा इंग्लैन्ड ने और दूसरे देशों ने ४८–४९ को आधार माना है। कुछ ने १९५० को भी आधार माना है। केवल एक वर्ष का अन्तर कोई विशेष अन्तर नहीं डालता है। हमने ४८–४९ को आधार माना है । हमारी आजादी के बाद वह पहला पूरा साल था जिसको हमने आधार भी माना और उसको आधार मानने की जरूरत इसलिये भी हुई कि प्रत्येक सरकार ने और हमारी भारत सरकार ने सबने उसको ही आधार माना है। इसके अलावा कौन-कौन उसके लिये आधार माना जाय ? इसके हिसाब की गणना करने से दो चीजों का मतलब है। किसानों की ओर शहरों के लोगों की आमदनी का अनुपात लगाने के लिये एक खास तरीका होता है। शहर वालों

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

की आमदनी ज्यादा होती है। शहर वाला केवल खरीदार है, कंज्यूमर है, सामान खरीदता है। किसान सामान पैदा करता है, उसको बेचता है और उसको बेचकर फिर खरीदता है। इन तीनों जरूरतों का अन्तर निकालना पड़ता है। ऐसा मान लीजिये कि सन् १९४८-४९ में किसान ने जो कुछ पैदा किया उसका मूल्य १०० था उसको उसने बेचा ९० रु० में और फिर उसको खरीदा ६० रुपये में तो वह ऐसा करता है। आप मान लीजिये कि जो उसने खरीदा उसका मूल्य ६० था और बेचा उसने ८० में। अन्तर्राष्ट्रीय तरीका यह है कि इन दोनों की जरूरतों में तीन चीजें है। खरीदना, बेंचना और फिर खरीदना। इसका अनुमान निकालने के लिये ८० में १० जोड़ दीजिये और ६० में १० जोड़ दीजिये तो इस हिसाब से ९०/७०×१०० =१२८ यानी २८ ज्यादा हो गया यह १२८ हो गया। तो इस हिसाब से १९४८-४९ में अगर एक किसान की आमदनी १०० रुपया थी तो ५५ में आकर वह १२ हो गयी। इसके हिसाब से अगर आंकड़े निकाले जायं तो फिर असली बात आपको मालूम पड़ेगी। क्वान्टुम आफ प्रोडेक्शन से आप तुलना कीजिये। ५२-५३ को आधार मान लेने में आप इस बात को समझ लें तो फिर आपकी समझ में यह बात आ जायगी। ४८-४९ में किसान की आमदनी २०० रुपया थी इससे ज्यादा नहीं थी लेकिन वह ५५ में आकर १५० रह गयी। इसी आधार को मान लेने से शहरों में जिनकी आमदनी ५००.१ रुपये थी उनकी ५५ में ६०४.४ हो गयी और इसी आधार पर जिस किसान की आमदनी २०० रुपये थी वह १५० रुपये ५५ में रह गयी। पर मूल्य के आधार पर आंकड़े निकालना अनुचित है क्योंकि उनसे किसी प्रकार कुछ सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो इन्डेक्स है उसमें सेल, परचेज और रिपर्चेज इन तीनों का क्वान्टुम निकालने की जरूरत है। आज हमारे किसान की परकैपिटा इन्कम १९२ से २२० हो गयी है। दूसरी बात इस सम्बन्ध में यह है कि एक साहेब ने ही सुबह कहा था कि कुछ आंकड़े तो मालूम नहीं होते। तो फिर ठीक प्रकार से स्थिति कैसे मालूम हो? मैं उन मित्रों से निवेदन करूंगा कि उन्हें यहां जो साहित्य बंटता है वह तो समझ लेना चाहिये, पढ़ लेना चाहिये। खाद्य के बारे में किसी ने कहा कि जो आंकड़े दिये जाते हैं या प्रकाशित किये जाते हैं, वे गलत हैं। हमको बताया गया है कि ७८ लाख टन से १२० लाख टन हमारे खाद्यान्न की उत्पत्ति हो गई। अगर इसे मन में लावें तो ३२ करोड़ मन गल्ला हम पैदा करते हैं उत्तर प्रदेश में। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमारी आबादी में ३८.३ फी सदी आदमी ऐसे हैं जिनकी उम्र १६ बरस से कम है और ८.३ फी सदी की उम्र ५५ वर्ष से ज्यादा है। यदि हम सबको बराबर मानकर ८ छटांक गल्ला हर एक को देवें तो हमें २९ करोड़ ६६ लाख मन गल्ला चाहिये। तो इस हिसाब से क्या हम ३ करोड़ मन गल्ला अधिक नहीं पैदा कर पाये हैं? पर एक बड़ी गम्भीर समस्या है यद्यपि कह देना आसान है हमारे प्रदेश में इस समय साढ़े ६ करोड़ की आबादी में करीब १ करोड़ ९० लाख आदमी ऐसे हैं जो कमाते हैं और केवल २१ लाख स्त्रियां कमाती हैं। २ करोड़ मर्द और ३ करोड़ स्त्रियां उन्हीं के बल पर बिना कमाये खाती हैं। तो फिर कैसे इस प्रदेश की आबादी का सन्तुलन हो सकेगा जब कि अन्तर इतना बड़ा है? समूचे भारतवर्ष के देश प्रदेशों का बजट करीब १,००० करोड़ रुपये का है और अगर बराबर बांट दिया जाय तो २.७ करोड़ रुपया रोज सरकार खर्च करती है, कैपिटल एक्सपैन्डीचर को छोड़कर। एक दिन के लिये आफिस बन्द कर दीजिये, शोक के लिये, त्यौहार के लिये, तो हम २.७ करोड़ रुपये का नुकसान करते हैं। इसका कितना बड़ा मूल्य है? हमारे प्रदेश में २६ लाख रुपया रोज सरकार खर्च करती है। एक दिन के लिये काम बन्द कर देने से कितनी बड़ी हानि होती है। समूचे प्रदेश के खर्चे को हम बराबर बांट दें तो २७ रुपया केन्द्रीय सरकार का फी व्यक्ति

का औसत पड़ता है। हमारे प्रदेश का औसत करीब १३।।) साढ़े तेरह रुपया पड़ता है। बम्बई की सरकार फी आदमी पीछे ४० रुपया, मद्रास की ३३ रुपये, पश्चिमी बंगाल की ३४ रुपये खर्च करती है। हम तो चेष्टा करने पर भी फी आदमी पीछे १४ रुपये से अधिक नहीं खर्च कर पा रहे हैं। इसका कारण हमारी बहुत बड़ी आबादी है। प्लान्ड इकानामी की बात हम कैसे दिखलावें जब कि छोटे प्रदेशों में काफी अधिक काम हो गया है? पंजाब की बात मैं बताऊं, श्रीमन्, भारतीय पंजाब की। पंजाब में केवल फी आदमी पीछे प्लानिंग के सिलसिले में आज पचास साल में करीब १०८ रुपये का खर्चा है और हमारे उत्तर प्रदेश में उनसे अधिक खर्च करने पर भी किसी प्रकार से भी हिसाब लगा लीजिये, फी आदमी पीछे २८ रुपये से ज्यादा का औसत नहीं पड़ता है। हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है, हम जानते हैं कि हमारी सीमा बहुत लम्बी है और हम बहुत लम्बे चौड़े हैं, तो हमें गम्भीरता से विचार अपनी समस्याओं का करना होगा। क्या किया जाय और लोगों को क्या करना चाहिये कि उनका कल्याण हो, क्या किया जाय कि हमारी प्रगति हो, और हमारे साथ ही साथ प्रदेश की प्रगति हो। यह सबके सोचने की बात है। श्रीमन् मैं ज्यादा समय तो लेना नहीं चाहता केवल इन तीन-चार बातों की तरफ ध्यान दिलाकर पुनः यह निवेदन करूंगा कि हम सब ठंडे दिल से यह सोचें कि आखिर देश की गाड़ी और प्रदेश की नौका कैसे चलेगी?

श्री आर्थर ग्राइस (नाम निर्देशित आङ्ग्ल भारतीय)—अध्यक्ष महोदय, मैं खड़ा हूं आपके द्वारा फाइनेंस मिनिस्टर साहब से निवेदन करने के लिये जो अपने बजट को बहुत बड़ा और फर्स्ट क्लास बताते हैं। उनकी निगाह में नेक्स्ट पांच साल में हमारा यू० पी० बिलकुल बगीचा के माफिक हो जायगा। सब आदमी के पेट में खाना रहेगा और पीठ पर कपड़ा रहेगा। यह ख्याल में ठीक है और उसके लिये बजट में फिगर्स मौजूद है। लास्ट फाइव ईयर में जो बातें हो चुकी हैं उनको देखते हुये तो हमें उम्मीद नहीं है कि जो उनका अन्दाजा है वह हो जायगा हमारा दिमाग तो इतना नहीं है कि श्री परिपूर्णानन्द की माफिक आंकड़ों से ब्याकुल कर दूं। सब के आंकड़े ही आंकड़े दे दूं, हमारा दिमाग ऐसा नहीं है। लेकिन मोटे तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि जो स्लोगन्स है उनको हम लोग भूल जायं और हम लोग काम करना शुरू करें। आज यहां फरमाया गया कि जब तक वे लोग न सोचें जो वर्कशाप में काम करते हैं, तब तक वर्कशाप की तरक्की नहीं हो सकती। लेकिन हम उस पर यह कहना चाहते हैं कि जब तक हम सारा हिन्दोस्तान अपना न समझ लें तब तक हिन्दोस्तान की बढ़ाई नहीं हो सकती। मैं आज अफसोस करता हूं कि मि० हरगोविन्द सिंह शिक्षा मंत्री आज नहीं है। मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह सोचकर काम चलायें। आपकी मेहरबानी से हम दो कमेटियों के ऊपर हैं। एक ऐजूकेशन कमेटी में है। मैं हाईस्कूल के बोर्ड के ऊपर ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जहां तक हम दूसरे लोगों से मिल पाये और बातचीत हुई हमें मालूम हुआ कि हमारे यहां की एजूकेशन पालिसी बिलकुल बेन्करप्ट है, बिल्कुल, कतई, शुरू से नीचे तक बाबू हो, इंस्पेक्टर हो, चाहे कोई भी हो, जो चीज है पुरानी और अनएस्टेबलिश्ड उसकी ठीक रखने की फिक्र नहीं है, वह हमेशा नई चीज के बारे में सोचते हैं और उसी को बड़ी बहादुरी समझते हैं और वाहवाही लूटना चाहते हैं, जो पुरानी चीज है उसको कुल्हाड़ी मारते हैं, मेरा कहना यह है कि जो पुराना पेड़ है पहले से लगा है उसको फल लाने के वास्ते पानी दो, मेन्योर दो ताकि वह खराब न हो अलबत्ता आप नया पेड़ भी लगाओ लेकिन जो एसटेबलिश्ड है उसको कुल्हाड़ी से काटो नहीं।

हम आजतक हाउस में एंग्लोइंडियन्स के लिये कुछ नहीं लाये और हमें सरकार से बहुत उम्मीद थी लेकिन मुझे अफसोस है कि उसने अपना पौंड आफ फ्लेश ले लिया है। हमारे कुल ३४ स्कूल हैं और उनमें ८ लाख खर्च होता है उनमें सन्, १९३८ में ३,००० लड़के पढ़ते थे और अब सन् १९५४ में वहां १३,००० लड़के हैं। इस तरह से पहले से दस हजार लड़के ज्यादा हो गये हैं। जनमें गैर एग्लोइंडियन की तादाद दूनी से भी ज्यादा है अब बजट को

[श्री आर्थर ग्राइस]

देखो तो हमारा दस परसेंट ५२ में काट डाला और १० परसेंट ५६–५७ में काटा गया है, जो चीज एस्टेबिशिश्ड है उसको गिराना ठीक नहीं है; जो एक चीज बृटिश राज्य की बनाई हुई थी उसको डेस्ट्राय किया जा रहा है। जो चीज अच्छी है वह चाहे ब्रिटिश की हो, फ्रेंच की हो या जर्मनी की हो अच्छी चीज को रखना सीखना है, डेस्ट्राय करना नहीं, उससे ठीक नहीं होगा। मैं सुझाव करता हूं कि एक कमेटी एजूकेशनिस्ट्स की देखे कि हमारे यह स्कूल्स किस तरह के हैं, और वहां किस तरह से क्या सिखाया जाता है, तब पता लगेगा कि वहां क्या हो रहा है? हमारा एजूकेशन विभाग जानता ही नहीं है कि वहां होता क्या है क्या स्टैंडर्ड वहां का है, कैसे लड़के पढ़कर बनते हैं। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो यह दस परसेंट काटा जाता है वह न काटा जाय, इस तरह की सेविंग न दिखाई जाय और जिसको वह सेविंग कहते हैं और वाहवाही और शाबासी लेते हैं वह ठीक नहीं है। सन् ४८ से उनको कोई बिलडिंग ग्रांट नहीं दिया गया है लाइब्रेरी को कुछ नहीं दिया गया है। नतीजा क्या है बनी हुई चीज बिगड़ती जाती है और मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह सोचे और बनी हुई चीज को न बिगाड़े।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। वित्त मंत्री की स्पीच में प्लानिंग में पेज ५ पर दिया हुआ है कि :

"I would like to tell that the various development schemes which are being undertaken to wipe out poverty from the country can be implemented only in stages. Since poverty is to be removed, our main objective is to increase the national wealth and to reduce the inequalities of income and wealth."

स्पीच में मुल्क की पार्वटी का जिक्र है लेकिन यहां पर मैं समझता हूं पार्वटी जो है वह : "Poverty is not of the stomach but it is only of the mind." जो शिक्षा कमेटी में है और जो मेरे साथ सब जगह घूमे हैं वह बता सकते हैं और मैंने पूरा यू० पी० देखा है कि क्या हो रहा है। हमें मालूम है कि आपके टीचर फेड अप हैं, रोज कुछ न कुछ नई चेंज होती है, वह नहीं जानते कि क्या हो रहा है। पहले रिटर्न एक था अब रिटर्न इतने हो गये हैं कि उसके लिये दो बाबू रखना पड़ते हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि फाइव ईयर प्लान में जो हम लोगों का पेट और पीठ मारा गया है लेकिन हमारे दिमाग को भी देखना चाहिये नहीं तो पेट और पीठ तो हमारा भर जायगा लेकिन हम लोग गदहे की तरह घूमेंगे, न अक्ल न दिमाग। मैं आपकी परमिशन से पढ़ना चाहता हूं :

"To secure community participation in the fullest measure an understanding of the plan and its aims and values by every citizen is, therefore, essential. Keeping this in view, an integrated publicity programme has been undertaken by the State Government."

सिर्फ पब्लिसिटी, और स्लोगन्स काफी नहीं है अभी एक नया स्लोगन हमारे नेहरू जी ने क्वाइन किया है "सोशलिस्टिक पैटर्न आफ स्टेट" स्लोगन बहुत अच्छा है लेकिन क्या पबलिसिटी और स्लोगन से ही काम चल जायेगा? हमारे हिस्टोरियान्स जब इस पीरियड की हिस्टरी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। ऐक्चुअल फैक्ट्स से तो यह पता चलेगा कि स्टेट के फाइव ईयर्स में गल्ला बहुत हो गया है। मैं भी कहता हूं कि हां हो गया है लेकिन कानपुर में ढाई सेर का गेहूं बिक रहा है। गल्ला ज्यादा हो गया है और आप लोग उसे बाहर भेज रहे हैं यह क्यों, यह मेरी समझ में नहीं आता। मेरे पास इतने आंकड़े नहीं है कि मैं श्री परिपूर्णानन्द जी की तरह से देता चला जाऊंगा मैं तो केवल इतना ही प्रार्थना करूंगा कि पबलिसिटी कम करें और एक्चुअल वर्क पर थोड़ा ज्यादा चलें।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी का यह सौभाग्य है कि उनके वित्तमंत्रित्व काल में एक ऐसा बजट पेश हुआ जिसपर बहस की दौरान में समाजवाद के ऊपर भी आज इस सदन में चर्चा शुरू हो गई है। अन्यथा इसके पहले जब कभी इस शब्द का प्रयोग भी हो जाता था तो एक अजीब किस्म का विरोध उस तरफ के सदस्यों में पैदा होता था और विशेषकर माननीय परिपूर्णानन्द जी न मालूम कहां-कहां की बातें पहले कह दिया करते थे। लेकिन आज यह बहुत ही ऐतिहासिक बहस है, सदन की हमारे देश और इस प्रदेश का किस तरह का भावी सामाजिक ढांचा होगा। इसकी रूपरेखा पर कम से कम सदन के हर एक सदय ने अपना विचार प्रकट करना तो शुरू किया। आज इस बात की होड़ है कि कौन असली समाजवादी है और कौन वास्तविक समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहता है। अवाड़ी सेशन में जो प्रस्ताव पास हुआ था उसमें सोशलिस्टिक पैटर्न की बात कही गयी थी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के दस्तावेजों "सोशलिस्ट पैटर्न शब्द" मैंने पढ़ना शुरू किया और वह शब्द आना भी शुरू हुआ। मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक कदम और आगे बढ़कर सोशलिस्ट सोसाइटी स्थापित करने की बात कही है। उनके भाषण में कई जगह पर स्पष्ट रूप से सोशलिस्ट सोसाइटी शब्द आया है। लेकिन हमको देखना होगा कि समाजवाद की तरफ जो चन्द कदम बढ़ाने की बात मंत्री जी ने कही है क्या वह सचमुच समाजवादी कदम है। मैं समझता हूं कि पिछले वर्षों में पूंजीवादी सुधारवादी कदम सरकार की ओर से उठाये गये हैं। इन्हीं को समाजवादी प्रकार के कदम कह कर माननीय वित्त मंत्री जी या तो अपने आपको धोखा दे रहे हैं या बाहर की जनता को धोखा देना चाहते हैं। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी के भाषण में हम कुल विषयों को देखें तो १८ विषय गिनाये गये हैं जो समाजवाद के कदम कह कर बताये गये हैं। उनमें से ट्रांसपोर्ट बिजली, सीमेंट फैक्ट्री, प्रेसीजन फैक्ट्री और कुछ कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज को छोड़कर जिनमें शायद कुछ समाजवाद की गंध मिल जाय, खोजने पर, बाकी को विशुद्ध बोर्जुआ डेमोक्रेटिक पेटी रिफार्म्स कहा जायगा। जहां तक बिजली, ट्रांसपोर्ट, प्रेसिजन फैक्ट्री और कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज का संबंध है, दीक्षित जी ने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि यह समाजवाद की ओर कदम है। मैं समझता हूं कि उन्हीं की परिभाषा के मुताबिक यह स्टेट कैपिटलिज्म की ओर कदम जरूर है लेकिन समाजवाद की ओर कदम नहीं है। उनको समाजवाद की परिभाषा के मुताबिक मुख्य उत्पादन के साधनों के ऊपर समाज का अधिकार हो, उसके वितरण और उसके विनिमय पर भी, उस ओर मैं समझता हूं कि सरकार का कदम नहीं उठ रहा है। मुझे डर लगता है कि लाहौर और करांची के प्रमुख प्रस्तावों की तरह कहीं इस प्रकार समाजवाद की परिभाषा की गई, तो समाजवाद वाला प्रस्ताव भी खटाई में न पड़ जाय। १९३० में लाहौर में कहा गया था कि हमारी आजादी का अर्थ होगा ब्रिटिश कामनवेल्थ से संबंध विच्छेद। वह आज तक नहीं हुआ। करांची में जो कहा गया था तनख्वाहों के बारे में वह भी नहीं हुआ। यों तो बचाव के लिये बहुत से तर्क उस संबंध में दिये जा सकते हैं। तो कहीं यह प्रस्ताव भी ऐसे न हो रह जाय। माला की मणियों की तरह जपने मात्र से कोई लाभ नहीं। यह सही है कि समाजवाद किसी भी देश में दूसरे देश की नकल से नहीं होगा। इस पर मैं अध्यक्ष महोदय आपकी आज्ञा से संसार में सर्वप्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना करने वाले लेनिन का यह उद्धरण पढ़ना चाहता हूं।

"All nations will arrive at socialism. It is inevitable. But not all will do so in exactly the same way, each will contribute something of its own in one or another form of democracy, one or another variety of the dictatorship of the proletariat" वित्त मंत्री ने इसे पीपुल्स कहा है। मैं समझता हूं कि यह पीपुल्स प्लान नहीं बल्कि यह देश के या प्रदेश के पूंजीवाद के आधार पर विकास का प्लान है। भाषण में जितनी मुख्य बातें हैं उनको देखने के बाद हम उसी परिणाम पर पहुंचते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने १८५७ के सैनानियों के स्मारक की बात कही है। यह सचमुच प्रशंसनीय कदम है। समाजवादी कदम नहीं है, बल्कि एक अच्छी चीज है। वित्त मंत्री और वर्तमान सरकार के कर्णधार माननीय गुप्त जी से कहूंगा कि ५७ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने देश के साथ

[श्री झारखंडे राय]

दुश्मनी की और अंग्रेजों का साथ दिया और जिनके हाथ में बहुत बड़ी-बड़ी सम्पत्तियां इस प्रदेश में हैं उनको जब्त करने की और वे साहस से बढ़ें। जब वे सैनानी जो प्रथम आजादी की लड़ाई के अग्रगण्य नेता थे और उनके लिये आप स्मारक बनाते हैं तो फिर उन्होंने देश के साथ गद्दारी की न उनके पास वह सम्पत्ति नहीं रहनी चाहिये। वह पाप की सम्पत्ति है। वह देश की और जनता की होनी चाहिये।

माली खुशहाली का जिक्र माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है इसके विषय में काफी आंकड़े दिये हैं। परिपूर्णानन्द जी ने तो आंकड़ों का जाल ही बिछा दिया। पता नहीं कि आंकड़े कहां से लाते हैं। राष्ट्रीय आय बढ़ी, परकैपिटा इनकम बढ़ी। लेकिन गरीब की गरीबी भी बढ़ गयी और अमीरों की अमीरी बढ़ी। लालबाग में दारुलशफा बना है। लालबाग की पर कैपिटा इनकम लगायी जाय तो हम लोगों के आने के बाद बढ़ी मालूम होगी लेकिन लालबाग के जो आदि निवासी हैं उनकी इनकम कितनी बढ़ी है हमारी इनकम बढ़ जाने से मैं समझता हूं कि इसी तरह से पर कैपिटा इनकम के जरिये ही करीब जनता के जीवन स्तर को ऊचा समझना भ्रामक है, यह समझ गलत जगह पर पहुंचा दिया करती है। जो पैदावार बढ़ी है, जो चीनी की पैदावार बढ़ी, उसके आंकड़े दिये हैं। लेकिन चीनी का दाम तो कम नहीं हुआ। उससे जो अधिक इनकम हुई वह कुछ लोगों की थैली में रह गयी। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के चुनाव के लिये उसमें से कुछ मिल जाय। लेकिन आम जनता के लिये उसमें से कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ। इसलिये केवल अनाज की पैदावार बढ़ने से, चीनी की पैदावार बढ़ने से हम यह कह कहते हैं कि राष्ट्रीय आय बढ़ी। लेकिन कंटेंट में अगर देखें तो हमारे राज्य में गरीब भी हैं और अमीर भी हैं, उनमें गरीब को कितना हिस्सा मिला और अमीर को कितना हिस्सा मिला, उसके ऊपर हम देश की बहबूदी को आंकते हैं, यह हमारा नजरिया है।

उद्योग धंधों में १७ करोड़ रुपया खर्च होने जा रहा है। लेकिन एक करोड़ रुपया इंडस्ट्रीज पर लगाने, एक करोड़ कोआपरेटिव चीनी मिलों में लगाने और ९ करोड़ ७६ लाख काटेज इंडस्ट्रीज में लगाने के बाद सवा पांच करोड़ ही बच जाता है बड़े उद्योगों के लिये। मैं समझता हूं कि उद्योग मंत्री जी इस रफ्तार से अगर हमारे प्रांत का उद्योगीकरण आप करेंगे तो कितने वर्षों में यह पूरा होगा इसको आप खुद सोचिये। मेरी समझ में बेसिक इंडस्ट्रीज की तरफ यह नजरिया बहुत संकुचित है। इधर और साहसपूर्ण कदम की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष--अब आपके पांच मिनट और रह गये हैं। आप कल भाषण देंगे। मैं एक सूचना देता हूं।

आगामी कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष--आज यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया कि १७ तारीख को इस सदन की बैठक होगी, शनिवार को एक रोज आम बहस का अभी बाकी है, और कल अनुदानों के ऊपर मत लेना था, तो वह कल चूंकि आम बहस जारी रहेगी, तो एक रोज अनुदानों पर मत लेने के प्रारम्भ में बढ़ जायगा। इस तरह से उसका परिणाम यह होगा कि जो अनुदान १ और २ मार्च को लिये जाने वाले थे वे २ मार्च और ५ मार्च को लिये जायेंगे क्योंकि ३ और ४ को छुट्टी रहेगी। जो अनुदान ५,६ और ७ के लिये थे वे ६,७,८ को होंगे। जो अनुदान ८,९ और १२ तारीख के थे वे ९, १२ और १३ को होंगे और जो अनुदान १३,१४ और १५ को लिये जाने वाले थे वे १४,१५ और १६ तारीख को लिये जायेंगे और जो अनुदान १६, १९ और २० को लिये जाने वाले थे वे अब १७, १९ और २० को लिये जायेंगे। और २१

२२ और २३ को जैसे अनुदान लिये जाने वाले थे वैसे ही रहेंगे। इसकी सूचना छपवाकर माननीय सदस्यों को कल या परसों दे दूंगा। लेकिन मैंने सूचना पहले से इस समय भी दे दी है।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय मैं एक बात जानना चाहता हूं अभी आपने जो परिवर्तन किया है उसमें ९ तारीख को और १२, १३ को मेरे विभागों के संबंध में यहां अनुदान उपस्थित होंगे तो मैं यह जानना चाहूंगा कि ९ तारीख को किस विषय का अनुदान यहां लिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—उस वक्त बात यह है कि उस ग्रूप में चिकित्सा है सिविल सप्लाइज भी है

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सभी हैं उसमें। तो क्योंकि अधिकारियों को कुछ बाहर से आना पड़ता है तो फिर उनको कई रोज रहना पड़ेगा। अगर मुझे यह बता दिया जाय कि ९ तारीख को चिकित्सा और सिविल सप्लाईज लिया जायगा या कौन सा लिया जायगा तो फिर उसी तरह से आदेश अधिकारियों को भेजे जायं।

श्री अध्यक्ष—तो मैं समझता हूं कि ऐसा हो जायगा कि यह आप जरा विरोधी दल के नेता से बातचीत करके आप लोग तय कर लें कि कौन सा पहले लिया जायगा और तय करके आप उसके हिसाब से मुझे सूचना दे दीजिये।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ;
२९ फरवरी, १९५[illegible]

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४–५ के उत्तर पीछे पृष्ठ ८८ पर)

नाम केन्द्र	स्पिनिंग सुपरवाइजर की संख्या	स्पिनिंग गाइड की संख्या	स्थानीय कार्यकर्त्रियों की संख्या	योग	सूत की खरीद का वजन	
					१९५४-५५	१९५५–५६
	वेतन-क्रम ६५–५–१२० रु०	वेतन-क्रम ३५–१–४० रु०	वेतन-क्रम ३५ रु० माहवार		मन	मन
१—जहानाबाद . .	. .	१	१	२	४	२१	३५
२—दोहरीघाट	. .	. .	१	..	१	२९	११
३—करहा . .	. .	. .	१	४	५	२०	१६
४—मुहमदाबाद	. .	. .	१	४	५	. .	७
५—बरूआगोदाम	. .	. .	१	४	५	. .	८
६—कोपागंज . .	. .	. .	१	४	५	. .	१०
७—मेहनाजपुर . .	. .	. .	१	४	५	. .	२
८—मार्टिनगंज	. .	. .	१	४	५	. .	. .
९—कोयलसा . .	. .	. .	१	४	५	. .	२
१०—रौनापार . .	. .	. .	१	४	५	. .	१३
११—भंरोदासपुर (महराजगंज)		१	१	४	६	. .	९
१२—घोसी . .	. .	१	. .	४	५	. .	४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८९ पर)

जिला उन्नाव में सरकारी एलोपैथिक और आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सालयों की सूची

एलोपैथिक--

१--जिला अस्पताल, उन्नाव	साधारण
२--बरखेरा अस्पताल	
३--भगवन्तनगर अस्पताल	
४--सुमेरपुर अस्पताल	
५--शुक्लागंज अस्पताल	
६--गंज मुरादाबाद अस्पताल	
७--मौरावां अस्पताल	
८--कटरा दीवान खेड़ा अस्पताल	
९--बांगरमऊ अस्पताल	
१०--एल० पी० अस्पताल, उन्नाव (जनाना)	
११--मौरावां अस्पताल (जनाना)	

आयुर्वेदिक यूनानी--

१--हैदराबाद औषधालय	साधारण (आयुर्वेदिक)
२--बंथथर औषधालय	
३--नेवन्ना औषधालय	
४--पाठकपुर औषधालय	
५--नवाबगंज औषधालय	
६--जगजीवनपुर औषधालय	
७--करदहा औषधालय	
८--मझगवां सेवक औषधालय	(साधारण यूनानी)
आयुर्वेदिक यूनानी जनाना	कोई नहीं ।
होमियोपैथिक . .	कोई नहीं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९० पर)

(तारांकित प्रश्न संख्या १२ से सम्बन्धित तालिका 'क' चुर्क सीमेंट फैक्टरी के स्टाफ के वेतन का ब्योरा)

क्रम-संख्या	पद	वेतन	विवरण
१	संचालक, चुर्क फैक्टरी	(विचाराधीन)	
२	उपसंचालक, चुर्क फैक्टरी	८००--५०--१,०००--७५-(१,७५०--५०--१,८०० रु०	२०० रुपये स्पेशल पे तथा १० प्रतिशत Compensatory एलाउन्स)
३	चीफ इंजीनियर तथा असिस्टेंट मैनेजर	१,५००--५०--१,८०० रु०	
४	मैकेनिकल इंजीनियर	६००--४०--१,००० रु०	
५	पावर स्टेशन इंजीनियर	,,	
६	इलेक्ट्रिकल इंजीनियर..	(५००--५०--१०००ई बी--५०-१२००--निजी)	ग्रेड पे पर २५ प्रतिशत स्पेशल पे
७	ऐडमिनिस्ट्रेटिव अफसर	२५०--२५--४००--ईबी--३० ७००-ई बी--५०--ईबी--८५० रु०	
८	पर्सनल अफसर ..	,,	ग्रेड पे पर २० प्रतिशत स्पेशल पे तथा १० प्रतिशत Compensatory एलउन्स ग्रेड पे पर २५ प्रतिशत स्पेशल पे।
९	एकाउन्ट्स अफसर ..	,,	
१०	असिस्टेन्ट इंजीनियर ..	,,	
११	सिनेन्ट केमिस्ट ..	२००--१०--२५०--ई बी--१०--३१०--ई बी--१४--४५० रु०	
१२	मेडीकल अफसर ..	२५०--२५--४००--ई बी--७०० रु०	
१३	ज्योलाजिस्ट ..	५००--५०--१,०००--ई बी--५०--१,२०० रु०	
१४	आफीसर इन्चार्ज पर्चेज आर्गेनाइजेशन	२५०--२५--४००--३०--७००--५०--८५० रु०	ग्रेड पे पर २५ प्रतिशत स्पेशल पे तथा १० प्रतिशत Compensatory एलाउन्स।
१५	असिस्टेंट एकाउन्ट आफीसर	२२०--१५--३७०--२० ४५०--२५--६७५ रु०	,, ,,
१६	असिस्टेंट परचेज आफीसर	२००--१०--२५०--१५--४०० रु०	,, ,,

क्रम-संख्या	पद	वेतन	विवरण
१७	प्रभारि अधिकारी विक्रय संस्थापन	२५०--२५--४००-ई बी--- ३०--७००---ई बी---५०--- ८५० रु०	ग्रेड पे पर २० प्रतिशत स्पेशल पे तथा १० प्रतिशत Compensatory एलाउन्स।
१८	सहायक लेखाधिकारी बिक्रय संस्थापन	२२०-- १५-- ३७०--ई बी-- २०--४५०---ई बी---२५-- ६७५ रु०	,, ,,
१९	सीनियर असिस्टेंट ..	१६०--१५---२८०---ई बी-- २०--४०० रु०	,, ,,
२०	सीनियर एकाउन्ट्स क्लर्क	८०--६---११०-- ६--१४० १०--२००--२०--२४० रु०	
२१	रोटीन क्लर्क ..	६०--४---८०---४---१०० रु०	
२२	एकाउन्टेन्ट कम असिस्टेंट कैशियर	७५---५---१२०---८---२०० रु०	
२३	स्टेनोग्राफर ..	१६०--१५---२८०---ई बी --२०---४०० रु०	ग्रेड पे पर २० प्रतिशत स्पेशल पे तथा १० प्रतिशत Compensatory एलाउन्स।
	,,	१००--५---१५०--१०-- २००---२०--२४० रु०	
२४	टाइपिस्ट ..	६०-- ४--८०---४---१०० रु०	
२५	उच्च लेखालिपिक ..	८०---६---११०--ईबी-- ६-- १४०---ई बी---१०---२००--- ई बी---२०---२४० रु०	
२६	खजांची ..	७५---५---१२०---ई बी---८ २०० रु०	
२७	सहायक लिपिक ..	६०---४---८०---ई बी--४-- १०० रु०	
२८	अर्दली ..	२२--१/२--२७ रु०	
२९	चपरासी ..	२२---१/२---२७ रु०	

खदान विभाग के टेक्निकल तथा अन्य स्टाफ

१	फोरमैन ..	..	२००---२०---३००--२५---४५० रु०
२	,,	..	२००---१०--२५०--ई बी--१०---३१०--- ई बी---१४---४५० रु०
३	,,	..	१२०--८---२००---ई बी---१०--३०० रु०
४	,,	..	४०० रु० फिक्स्ड
५	मेकैनिक्स		१२०---६---२१०---१०---२५० रु०
६	शावल आपरेटर	..	१२०---६---१६२---ई बी---६--२१०--ईबी-- १०--२५० रु०
७	चार्जमैन ..	..	८०---५--१२०--७--२०० रु०

क्रम संख्या	पद		वेतन	विवरण
८	बुल डोजर आपरेटर	..	७५--५--१२०--ई बी--८--२०० रु०	
९	डम्पर ड्राइवर	..		,,
१०	वैगन ड्रिलर	..	७५--५--१००--६--१६० रु०	
११	वेल्डर ..	..		,,
१२	इलेक्ट्रीशियन	..		,,
१३	फिटर प्रथम श्रेणी	..		,,
१४	टर्नर प्रथम श्रेणी	..		,,
१५	स्टोर कीपर	..	८०--५--१००--६--१३० रु०	
१६	जूनियर क्लर्क	..	६०--३--९०--४--११० रु०	
१७	असिस्टेंट टाइम कीपर			,,
१८	फिटर द्वितीय श्रेणी	..		,,
१९	कारपेंटर	..		,,
२०	शाट फायर	..	४५--३--६०--ई बी--४--१०९ रु०	
२१	सब ओवरसीयर	..	४५--३--६०--ई बी--४--१०० रु०	
२२	ड्राइवर ..	..	५०--५--९० रु०	
२३	वायर मैन ..	..	५०--२--६०--३--९० रु०	
२४	लाइन्स मैन	..		,,
२५	लोको ड्राइवर	..	४५--१--५०--२--६०--३--७५ रु०	
२६	कम्पाउन्डर	..	४५--२--६५ रु०	
२७	चेकर ..	..	३०--१ १/२--३९--ई बी--१ १/२--४५--२--६५ रु०	
२८	असिस्टेंट शाट फायर	..		,,
२९	ब्लैक स्मिथ	..	३०--१ १/२--३९--ई बी--१ १/२--४५--ई बी २ १/२--६५ रु०	
३०	ट्रिल जैक हैमर मैन	..	४०--१--५०--२--६० रु०	
३१	खलासी	..		,,
३२	सुपरवाइजर	..	४५ रु० फिक्स्ड	
३३	स्टोर अटेन्डेन्ट	..	३०--१--४० रु०	
३४	हेल्पर ..	..		,,
३५	वाचमैन	..		,,
३६	मजदूर ..	..	३०--१/२--३७ १/२ रु०	
३७	असिस्टेंट कम्प्रेसर ड्राइवर	..	३०--१--३५ रु०	
३८	इक्सप्लोजिव कैरियर	..		,,
३९	क्लीनर	..		,,
४०	स्वीपर .	..	२२--१/२--२७ रु०	
४१	डाक रनर ..	..		,,
४२	चपरासी	..		,,
४३	इनफीरीयर सर्वेन्ट	..		,,

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्पादन विभाग का टेक्निकल तथा अन्य स्टाफ

क्रम-संख्या	पद	वेतन	विवरण
१	फोरमैन	२००—१०—३००—१५—३७५—२०—५७५ रु०	मेन प्लान्ट
	,, ..	१५०—१०—३००—१५—३७५ रु०	इलेक्ट्रिकल
२	शिफ्ट इंजीनियर ..	२००—१०—२५०—ई बी—१०—३१०—ई बी—१४—४५० रु०	
३	टेक्सटाइल एक्सपर्ट ..	२००—१०—३५० रु०	ग्रेड पे पर २५ प्रतिशत स्पेशल पे तथा १० प्रतिशत कम्पेंसेटरी एलाउन्स।
४	चीफ एकाउन्टेंट	१५०—१०—२००—ई बी—१०—३५० रु०	
५	शिफ्ट केमिस्ट ..	१२०—८—२००—१०—३०० रु०	
६	बर्नर ..	,,	ग्रेड पे पर २५ प्रतिशत स्पेशल पे तथा १० प्रतिशत कम्पेंसेटरी एलाउन्स।
७	शिफ्ट फोरमैन ..	,,	
८	पैकिंग प्लान्ट फोरमैन	,,	
९	चीफ स्टोर कीपर ..	,,	
१०	चीफ कैशियर ..	,,	
११	ओवरसियर ..	१२०—६—१६२—ई बी—६—२१०—ई बी—१०—२५० रु०	
१२	स्टेनोग्राफर ..	१००—५—१५०—ई बी—१०—२००—ई बी—२०—२४० रु०	
	,,	१००—५—१२५—ई बी—५—१६०—ई बी—१०—२०० रु०	
	,,	७५—४—९५—ई बी—५—१५० रु०	
१३	हेड क्लर्क ..	८०—६—११०—ई बी—६००—१४०—ई बी—१०—२००—२०—२४०+३० रु०	
१४	सीनियर क्लर्क ..	,,	
	एकाउन्टेंट टाइमकीपर	८०—५—१००—६—१३० रु०	
१५	चार्जमैन ..	८०—५—१३०—७—२०० रु०	
१६	असिस्टेंट कैशियर ..	७५—५—१२०—ई बी—४—२०० रु०	
१७	असिस्टेंट स्टोरकीपर ..	,,	
१८	मटीरियल हैंडलिंग सुपरवाइजर	७५—५—१७५ रु०	
१९	टरबाइन ड्राइवर ..	७५—५—१००—६—१६० रु०	
२०	वाइलर अटेन्डेंट ..	,,	
२१	फिटर्स प्रथम श्रेणी ..	,,	
२२	टर्नर प्रथम श्रेणी ..	,,	
२३	वेल्डर प्रथम श्रेणी ..	,,	
२४	पेटर्न मेकर ..	,,	
२५	इलेक्ट्रीशियन ..	,,	
२६	आरमेचर वाइन्डर ..	,,	

सत्यमेव जयते विधान सभा

क्रम-संख्या	पद		वेतन-क्रम	विवरण
२७	असिस्टेंट बर्नर	..	७२—५—१००—६—१६० रु०	
२८	केबल ज्वाइंटर	..	,,	
२९	मिलर	..	,,	
३०	क्रेन ड्राइवर	..	६०—४—१००—५—१२५ रु०	
३१	पैकर	..	,,	
३२	स्वीच बोर्न अटेंडेंट	..	,,	
३३	लोको ड्राइवर	..	,,	
३४	मोल्डर	..	,,	
३५	नर्स	..	६५—५—९०—ई बी—५—१२० रु०	
३६	जूनियर क्लर्क	..	६०—३—९०—४—११० रु०	
३७	टर्नर द्वितीय श्रेणी	..	,,	
३८	वेल्डर द्वितीय श्रेणी	..	,,	
३९	फिटर द्वितीय श्रेणी	..	,,	
४०	ब्लैकस्मिथ द्वितीय श्रेणी		,,	
४१	कारटर	..	,,	
४२	टेस्टर	..	,,	
४३	गेजर	..	,,	
४४	लोडिंग क्लर्क	..	,,	
४५	वैगन ट्रिपलर आपरेटर		,,	
४६	टाइपिस्ट	..	,,	
४७	असिस्टेंट टाइमकीपर		,,	
४८	ट्रेसर	..	४५—२—६५—ई बी—८०—ई बी—४—१०० रु०	
४९	कम्पाउन्डर	..	,,	
५०	मिड वाइफ	..	,,	
५१	मोटर ड्राइवर	..	५०—५—९० रु०	
५२	वायर मैन	..	५०—२—६०—३—९० रु०	
५३	लाइन मैन	..	,,	
५४	लोको फायरमैन	..	४५—१—५०—२—६०—३—७५ रु०	
५५	मेसन	..	,,	
५६	चेकर्स	..	,,	
५७	सेम्पुल ब्वाय	...	४०—१—५०—२—६०—२ १/२—७५ रु०	
५८	खलासी	..	४०—१—५०—२—६० रु०	
५९	फायर मैन वाइलर	..	,,	
६०	कन्डेंसर अटेन्डेंट	..	,,	
६१	हैमरमैन	..	३५—१—५० रु०	
६२	घाघर पंप अटेंडेंट	..	,,	
६३	अटेंडेंट	..	३०—१—४५ रु०	
६४	हेल्पर	..	,,	
६५	क्लीनीयर	..	३०—१—४० रु०	
६६	वाचमैन	..	,,	

विधान सभा उत्तर प्रदेश

क्रम-संख्या	पद		वेतन-क्रम	विवरण
६७	मजदूर	..	३०—१/२—३७ १/२ रु०	
६८	मेठ	..	३२—१—३७ रु०	
६९	दफ्तरी	..	,,	
७०	दफेदार	..	,,	
७१	लेबोरेटरी वियरर	..	,,	
७२	ड्रेसर कम वार्ड ब्वाय	..	२७—१/२—३२	
७३	चपरासी	..	२२—१/२—२७	
७४	स्वीपर	..	,,	

तारांकित प्रश्न संख्या १२ से सम्बन्धित तालिका 'ख'

चुर्क फैक्टरी के स्टाफ का निम्नलिखित मुख्य-मुख्य सुविधायें प्राप्त हैं :

(१) निवास के लिये क्वार्टर, बिजली और पानी।

(२) इलाज के लिये डिस्पेंसरी जहां एक अनुभवी मेडिकल अफसर तथा अन्य स्टाफ हैं।

(३) सफाई (Sanitation) की व्यवस्था कुछ क्वार्टरों के अतिरिक्त सभी के फ्लश पाखानों तथा स्नानागार का प्रबन्ध।

(४) शिक्षा के लिये एक प्राइमरी स्कूल।

(५) कैन्टीन तथा विश्रामगृह।

(६) मनोरंजन के लिये खेलकूद आदि की व्यवस्था तथा लाउडस्पीकर सहित एक रेडियो सेट।

(७) धूल आदि से बचाव के लिये पैकिंग प्लान्ट पर काम करने वालों को चश्मे दिये जाते हैं और उन्हें गुड़, तेल तथा कपड़ा भी निःशुल्क दिया जाता है।

(८) एक सहकारी स्टोर।

संसद सदस्य सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९३ पर)

एन० ई० एस० ब्लाक जोया में ३१-१२-१९५५ तक होने वाले कामों की सूची

मदें	किया गया कार्य
(१) कृषि	
१--खोदे गये कम्पोस्ट पिट्स	१७२९
२--बांटी गई खाद	७८८५ मन
३--बांटे गये बीज	३५० मन
४--बांटे गये औजार	८५
५--किये गये डिमान्स्ट्रेशन	४५१
(२) पशु पालन--	
१--बधिया किये गये बैलों की संख्या ..	४४४
२--अच्छी नस्ल के बैल जो बांटे गये ..	२
३--पशु जिनका इलाज किया गया	२०१४
४--अच्छी नस्ल की चिड़िया जो बांटी गई ..	५७३
५--मछली की फिंगरलिंग जो दी गई ..	८००
(३) कोआपरेशन--	
१--खोली गई कोआपरेटिव सोसाइटियां	१५
२--बनाये गये मेम्बरों की संख्या	१११०
(४) सिंचाई--	
अतिरिक्त क्षेत्र जिसमें सिंचाई की गई ..	९७० एकड़
(५) यातायात--	
कच्ची सड़कों की मरम्मत	३ मील ७ फर्लांग
(६) सामाजिक शिक्षा--	
खोले गये मनोरंजन केंद्र	३
(७) स्वास्थ्य--	
१--बनाये गये सोकेज पिट्स ..	७०
२--बनाई गई पक्की नालियां	७५० गज
३--बनाये गये पानी पीने के कुयें ..	४६
४--पानी पीने के कुयें जिनकी मरम्मत की गई ..	३६
५--वह लोग जिन के टीके लगाये गये ..	७३८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९-२० के उत्तर पीछे पृष्ठ ९४ पर)

उत्तर प्रदेश में १-२-५६ तक खुलने वाले ब्लाक की सूची

क्र० संख्या	जिला	एन० ई० एस० ब्लाक	खुलने की तिथि	सी० पी० ब्लाक	खुलने की तिथि
१	२	३	४	५	६
१	देहरादून	१—दवींवाला	२६-१-५५	चकराता	१-१०-५३
		२—कलसी	२६-१-५६	—	
२	सहारनपुर	१—मुजफ्फरनगर	२-१०-५४	देवबन्द	१-१०-५३
		२—गंगोह	२-१०-५५	—	—
३	मुजफ्फरनगर	१—पुरकाजी* (आई०डी०)	२६-१-५४	—	—
		२—ऊन	२६-१-५६	—	—
		३—भुकहेरी	२६-१-५६	—	—
४	मेरठ	१—लोनिफ* (आई०डी०)	२-१०-५३	—	—
		२—बिनौली	२६-१-५५	—	—
		३—पिलाना	२-१०-५५	—	—
५	बुलन्दशहर	१—उंचागांव* (आई० डी०)	२६-१-५४	—	—
		२—बुलन्दशहर* (ई० पी०)	२-१०-५४	—	—
		३—दनकौर	२६-१-५५	—	—
६	अलीगढ़	१—टपल* (आई० डी०)	२६-१-५४	—	—
		२—हसायान	२६-१-५५	—	—
		३—जवान सिकन्दरपुर	२-१०-५५	—	—
७	मथुरा	१—गोवर्धन* (आई०डी०)	२६-१-५४	—	—
		२—मथुरा	२६-१-५५	—	—
		३—नोझील	२-१०-५५	—	—
८	आगरा	१—वाह* (आई० डी०)	२-१०-५३	अकोला	१-१०-५३
		२—खेरागढ़* (आई०डी०)	२६-१-५४	—	—
		३—बिचपुरी	२६-१-५६	—	—
९	मैनपुरी	१—सिरसागंज	२६-१-५५	सुल्तानगंज	१-१०-५२
		२—एका	२६-१-५४	—	—
१०	एटा	१—आवागढ़	२६-१-५५	अलीगंज	मई, १९५३
		२—कासगंज	२६-१-५६	—	—
११	बरेली	१—भोजीपुरा	२६-१-५४	—	—
		२—मजगवान	२६-१-५५	—	—
		३—फरीदपुर	२-१०-५५	—	—
१२	बिजनौर	१—अफजलगढ़	२६-१-५४	—	—
		२—कोठाली* (आई०डी०)	२-१०-५४	—	—
		३—जलीलपुर	२-१०-५५	—	—
१३	बदायूं	१—आसफपुर	२६-१-५५	उसावां	१-१०-५३
		२—वजीरगंज	२६-१-५६	—	—

क्रम संख्या	जिला	एन० ई एस० ब्लाक	खुलने की तिथि	सा० पो० ब्लाक	खुलने की तिथि
१	२	३	४	५	६
१४	मुरादाबाद	१—जोया* (आई० डी०)	२६-१-५४	—	—
		२—ठाकुरद्वारा	२-१०-५४	—	—
		३—अमरोहा	२-१०-५५	—	—
१५	रामपुर	१—सेदनागर	२६-१-५४	—	—
		२—बीलासपुर	२६-१-५५	—	—
		३—सोअर	२६-१-५६	—	—
१६	शाहजहांपुर	१—कंठ	२६-१-५५	उसावां	१-१०-५३
		२—कुठार	२६-१-५६	—	—
१७	पीलीभीत	१—लिलोरीखेड़ा* (आई०डी०)	२६-१-५४	—	—
		२—पुलनपुर	२६-१-५५	—	—
		३—बिसालपुर	२६-१-५६	—	—
१८	फर्रुखाबाद	१—उमरादा	२६-१-५५	मुहम्मदाबाद	मई, ५३
		२—राजापुर	२६-१-५६	—	—
१९	इटावा	पाइलेट प्रोजेक्ट	—	—	—
२०	कानपुर	१—घाटमपुर	२६-१-५४	—	—
		२—एग्रीकल्चरल कालेज (कल्याणपुर)	२६-१-५५	—	—
		३—अमरोधा	२६-१-५५	—	—
		४—अखबपुर	२६-१-५६	—	—
२१	फतेहपुर	१—मौहा	२६-१-५४	—	—
		२—मलवान	२६-१-५५	—	—
		३—बिजैपुर	२६-१-५६	—	—
२२	इलाहाबाद	१—कौरांव* (आई० डी०)	२-१०-५३	फूलपुर	१-१०-५३
		२—कड़ा	२६-१-५५	—	—
		३—चायल खास	२६-३-५४	—	—
		४—बाहादुरपुर	२६-१-५६	—	—
		५—करछना	२६-१-५६	—	—
२३	झांसी	१—झाकोरा	२६-१-५५	मोठ	१-१०-५२
		२—चिरगांव टी० ई० पी०	२-१०-५४	मोरानीपुर	मई, ५३
				गुरसराय	मई, ५३
२४	जालौन	१—कादोरा	२६-१-५६	—	—
		२—ऐट *(आई० डी०)	२६-१-५४	—	—
		३—खुलन्द	२-१०-५४	—	—
२५	हमीरपुर	१—मोदहा *(आई० डी०)	२६-१-५४	—	—
		२—गाहंड	२-१०-५४	—	—
		३—सुमेरपुर	२६-१-५६	—	—
२६	बांदा	१—महुवा *(आई० डी०	२-१०-५३	—	—
		२—मानिकपुर	२-१०-५४	—	—
		३—टेनस बीगहेल ट्रैक्ट (मऊ)	२६-१-५५	—	—

क्रम संख्या	जिला	एन० ई० एस० ब्लाक	खुलने की तिथि	सी० पी० ब्लाक	खुलने की तिथि
१	२	३	४	५	६
२७	बनारस	१—आरसीलाइनस	२६—१—५४	—	—
		२—ओरई * (आई० डी०)	२६—१—५४	—	—
		३—काशी विद्यापीठ	२६—१—५५	—	—
२८	मिर्जापुर	१—हलाया	२६—१—५५	दुधी	१—१०—५३
		२—रावट्सगंज	२६—१—५६	—	—
२९	जौनपुर	१—बादसहापुर * (आई ०डी०)	२—१०—५३	—	—
		२—डोभी	२६—१—५५	—	—
		३—रामपुर	२—१०—५५	—	—
३०	गाजीपुर	१—गाजीपुर टी०ई० पी०	२—१०—५४	कासिमाबाद	१—१०—५२
		२—देवकली	२६—१—५५	—	—
३१	बलिया	१—गरवाल	२६—१—५५	रतनपुर	१—१०—५२
		२—बारअबारी	२—१०—५५	—	—
३२	गोरखपुर	१—नीछालोल * (आई० डी०)	२—१०—५३	मटठ	१—१०—५२
		२—चीरगांव	२६—१—५५	—	—
३३	देवरिया	१—कैपटेनगंज * (आई० डी०)	२—१०—५३	१—कसिया	१—१०—५२
				२—सलीमपुर	मई, ५३
३४	बस्ती	१—भानवापुर	२—१०—५३	नागर बाहादुरपुर	१—१०—५६
		२—हसनबाजार	२६—१—५५	—	—
३५	आजमगढ़	१—लालगंज	२६—१—५५	घोसी	१—१०—५२
		२—दोहरीघाट	२—१०—५६	—	—
३६	नैनीताल	१—खटीमा	२—१०—५३	—	—
		२—उखालखांढ़ा * (आई० डी०)	२६—१—५४	—	—
		३—रोर्दापुर टी० ई० पी०	२—१०—५४	—	—
३७	अलमोड़ा	१—तारीखेत	२—१०—५३	१—गरुड़—बैज-नाथ	१—१०—५२
		२—माल्लीपीखरी	२६—१—५५	२—कपकोट	मई, ५३
		३—हवालबाग ट्रेनिंग केंद्र	२६—१—५५	—	—
		४—धोरचूला	२—१०—५५	—	—
३८	गढ़वाल	१—दादामंढ़ी (आई०डी०)	२६—१—५४	थराली	मई, ५३
		२—जोशीमठ (पर्वतव्स)	२—१०—५५	—	—
		३—ताल्लीसान	२६—१—५६	—	—
३९	टेहरी-गढ़वाल	१—नानगांव* (आई०डी०)	२—१०—५४	मिलंगना	१—१०—५३
		२—भटवारी	२—१०—५५	—	—
		३—जोनपुर	२६—१—५६	—	—

क्रम-संख्या	जिला	एन० ई० एस० ब्लाक	खुलने की तिथि	सी० पी० ब्लाक	खुलने की तिथि
१	२	३	४	५	६
४०	लखनऊ	१—गोसाईगंज (आई०डी०)	२६-१-५४	—	—
		२—सरोजनी नगर	२०-१०-५४	—	—
		३—बकसी का तालाब और टी० ई० पी०	२-१०-५४	—	—
४१	उन्नाव	१—नवाबगंज* (आई० डी०)	२६-१-५४	—	—
		२—फतेपुर	२६-१-५५	—	—
		३—सोमेरपुर	२६-१-५६	—	—
४२	रायबरेली	१—सलोन* (आई० डी०)	२६-१-५४	—	—
		२—हरिचन्दपुर	२६-१-५५	—	—
		३—महाराजगंज	२६-१-५६	—	—
४३	सीतापुर	१—हरगांव (आई० डी०)	२६-१-५४	—	—
		२—बेहता	२-१०-५४	—	—
		३—सिधौली	२६-१-५६	—	—
४४	हरदोई	१—बिलग्राम* (आई० डी०)	२६-१-५४	—	—
		२—कौनधन	२६-१-५५	—	—
		३—सांडी	२-१०-५५	—	—
४५	खीरी	१—बेहजाय* (आई० डी०)	२६-१-५४	—	—
		२—नीघासन	२-१०-५४	—	—
		३—मीतोली	२-१०-५५	—	—
४६	फैजाबाद	१—जलालपुर	२६-१-५५	माकापुर	१-१०-५२
		२—मसोधा	२-१०-५५	—	—
४७	गोंडा	१—ईनतयालेक	२६-१-५४	—	—
		२—मनकापुर	२६-१-५५	—	—
		३—पारसपुर	२-१०-५५	—	—
४८	बहराइच	१—केसारगंज* (आई० डी०)	२६-१-५४		
		२—सीरसाया	२६-१-५५	—	—
		३—महोमपुरवा	२-१०-५५		
४९	सुल्तानपुर	गोरीगंज	२६-१-५५	१—कूरेमार मई, ५३ २—जैसिंगपुरमई, ५३	
५०	प्रतापगढ़	१—लकछमनपुर	२६-१-५४	—	—
		२—आसपुर दिवसरा	२६-१-५५	—	—
		३—भवानीगंज	२-१०-५५	—	—
५१	बाराबंकी	१—रामनगर	२६-१-५४	—	—
		२—मसौली	२६-१-५५	—	—
		३—रुदौली	२६-१-५५	—	—

* यह राष्ट्रीय प्रसार सेवा केन्द्र २६ जनवरी, १९५६ को इन्टेनिसव डेवलपमेंट ब्लाक बना दिये गये।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६ पर)

अल्मोड़ा जिले में राजकीय चिकित्सालयों की सूची

राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय

१—कान्डा
२—सोमेश्वर
३—कपकोट
४—बेला देवाल साल्ट
५—पिथौरागढ़
६—स्यालदह
७—म्यूनसियारी
८—दनियां
९—कौसानी
१०—धारचुला
११—तेजम
१२—बारीछेना
१३—रानीखेत
१४—जिला अस्पताल (अलमोड़ा)
१५—महिला चिकित्सालय (अलमोड़ा)

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय

१—गनाई गंगोली
२—गाख्यांग (सूंग)
३—परोलिया
४—जलमानी
५—कनालीछिना
६—बड़हा
७—कोशी
८—जागेश्वर
९—शितलाखेत
१०—चौराघुरकी पट्टी
११—सौला
१२—धारचुला
१३—मनौली
१४—नगरखान

राजकीय सहायता प्राप्त एलोपैथिक चिकित्सालय

१—बेरीनाग
२—बैजनाथ
३—देवाधुरा
४—पुल हिन्डोला
५—गंगोलीघाट
६—द्वाराहाट
७—अस्कोट

जिला बोर्ड आयुर्वेदिक चिकित्सालय

१—बसौली
२—लमगारा
३—तेजम
४—जयन्ती
५—मजराली
६—मनीलासामा
७—हरौरा
८—चम्पावत
९—मासी
१०—मडेलामहादेव
११—तमाधम

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एलोपैथिक चिकित्सालय

१—लोहाघाट
२—बागेश्वर
३—गनई
४—भिक्यासैण

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७ पर)

जिला हमीरपुर की जिला नियोजन समिति को (१९५४–५५) में दिये गये अनुदान और व्यय की सूची

क्रम-संख्या	अनुदान का नाम	१–४–१९५४ को बैलैन्स	अनुदान प्राप्त (१९५४–५५)	अन्य मद से धन प्राप्ति	योग	व्यय (१९५४–५५)	१–३–५५ को को बैलैन्स	विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९
		रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	
१	डिस्क्रिश्नरी अनुदान	५६,३३९ ५ ८		५,४५८ ६ ६	६१,७८७ १२ २	४५,६२९ ५ ९	१६,१६७ ६ ५	जिलों को अनुदान साल भर में भिन्न महीनों में मिलती है, कभी-कभी अनुदान जिला नियोजन समितियों
२	अफारेस्टेशन अनुदान	—	२०,००० – –	—	२०,०००	५०० – –	१९,५०० – –	
३	सैन्कसन वर्क्स अनुदान	४२,६२५ – –	—	—	४२,६२५	—	४२,६२५ – –	
४	हरिजनों के हेतु पानी पीने और घरों की व्यवस्था के हेतु अनुदान	४,३०० – –	५,४४५ – –	—	९,७४५ – –	४,३०० – –	५,४४५ – –	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

५ हरिजनों के कल्याण हेतु अनुदान	१,०३८	१०	–	६७७	८	–	—	१७१६	२	९	१०३७	११	–	६७८	७	९	को अनुपूरक अनुदान (Supplementary grant)
६ फिजिकल कल्चर अनुदान	४७६	१५	९	१,०००	–	–	—	१४७६	१५	९	१,२०२	१३	३	२७४	२	६	
७ हिरजनों के मकानों हेतु अनुदान	८००	–	–	१५००	–	–	—	२३००	–	–	—			२३००	–	–	पास होने के बाद दी जाती है। इस कारण जिला नियोजन समितियों के लिये उसी वर्ष में अनुदान को पूरी तरह से व्यय करना असंभव हो
८ सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट अनुदान	८६,८६२	–	–	५०,०००	–	–	—	१३,६,८६२	–	–	५२,५८८	१२	–	८४,२७३	४	–	
९ पब्लीसिटी और प्रोपेगेन्डा अनुदान		—		५००	–	–	—	५००	–	–	—			५००	–	–	
१० एन० ई० एस० मोदाहा के लिये अनुदान	१२,६३०	–	–	७६,४१५	–	–	—	८९,०४५	–	–	८९,०१५	–	–	३०	–	–	
११ अस्पृश्यता सप्ताह के लिये अनुदान	१,०००	–	–	१०००	–	–	—	२०००	–	–	१०००	–	–	१०००	–	–	
१२ हायर सेकेन्डरी स्कूल के हेतु अनुदान	९,९००	–	–	१५,०००	–	–	—	२४,९००	–	–	९,९००	–	–	१५,०००	–	–	
१३ सेल्फ हेल्प अनुदान		—		४१,७५०	–	–	—	४१,७५०	–	–	१८,३१८	४	–	२३,४३१	१२	–	
१४ एन० ई० एस० ब्लाक गोहान्द के हेतु अनुदान		—		१२,५००	–	–	—	१२,५००	–	–	२,५८६	–	–	९,९१४	–	–	
१५ सेन्ट्रल सरकार द्वारा पीने के पानी के लिये अनुदान		—		१,५०,०००	–	–	—	१,५०,०००	–	–	१,०००	–	–	१,४९,०००	–	–	जाता है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६--२७ के उत्तर पीछे पृष्ठ ९८ पर)

उत्तर प्रदेश के वह जिले जिनमें तीन या उनसे ज्यादा राष्ट्रीय प्रसार सेवा केन्द्र खोले जा चुके हैं

नाम जिला	एन० ई० एस० ब्लाक का नाम	ब्लाक खुलने की तारीख	इन्टेन्सिव ब्लाक बनाई जाने की तारीख
१	२	३	४
१--मुजफ्फरनगर	१--पुरकाजी	२६-१-१९५४	२६-१-१९५६
	२--उन	२६-१-१९५५	--
	३--भूकाहेरी	२६-१-१९५६	--
२--मेरठ	१--लोनी	२-१०-१९५३	२६-१-१९५६
	२--बिनौली	२६-१-१९५५	--
	३--पिलाना	२-१०-१९५५	--
३--बुलन्दशहर	१--ऊंचागांव	२६-१-१९५४	२६-१-१९५६
	२--बुलन्दशहर (टी० ई० पी०)	२-१०-१९५४	
	३--दनकौर	२६-१-१९५५	--
४--अलीगढ़	१--थपल	२६-१-१९५४	२६-१-१९५६
	२--इसायां	२६-१-१९५५	--
	३--जवान सिकन्दरपुर	२-१०-१९५५	--
५--मथुरा	१--गोवरधन	२६-१-१९५४	२६-१-१९५६
	२--मथुरा	२६-१-१९५५	--
	३--नवझील	२-१०-१९५५	--
६--आगरा	१--बाह	२-१०-१९५३	२६-१-१९५६
	२--खेरागढ़	२६-१-१९५४	२६-१-१९५६
	३--बिछपुरी	२६-१-१९५६	--
७--बरेली	१--भोजीपुरा	२६-१-१९५४	--
	२--मजगवां	२६-१-१९५५	--
	३--फरीदपुर	२-१०-१९५५	--
८--बिजनौर	१--अफजलगढ़	२६-१-१९५५	--
	२--कोतवाली	२-१०-१९५४	२६-१-१९५६
	३--जलीलपुर	२-१०-१९५५	--
९--मुरादाबाद	१--जोया	२६-१-१९५४	२६-१-१९५६
	२--ठाकुरद्वारा	२-१०-१९५४	--
	३--अमरोही	२-१०-१९५५	--
१०--रामपुर	१--सेदनगर	२६-१-१९५४	--
	२--विलासपुर	२६-१-१९५५	--
	३--सुआर	२६-१-१९५६	--

नाम जिला	एन० ई० एस० ब्लाक का नाम	ब्लाक खुलने की तारीख	इन्टेन्सिवों ब्लाक बनाई जाने की तारीख
१	२	३	४
११—पीलीभीत	१—लिलौरीखेड़ा	२६-१-१९५४	२६-१-१९५६
	२—पूरनपुर	२६-१-१९५५	—
	३—विलासपुर	२६-१-१९५६	—
१२—कानपुर	१—घाटमपुर	२६-१-१९५४	—
	२—कल्यानपुर	२६-१-१९५५	—
	३—अनरौधा	२-१०-१९५४	—
	४—अकबरपुर,	२६-१-१९५६	—
१३—फतेहपुर	१—बहुआ	२६-१-१९५४	—
	२—मलवान	२६-१-१९५५	—
	३—बजैपुर	२६-१-१९५६	—
१४—इलाहाबाद	१—कोरावं	२-१०-१९५३	२६-१-१९५६
	२—कड़ा	२६-१-१९५५	—
	३—चाइल खास	१-३-१९५४	—
	४—चाव बहादुरपुर	२६-१-१९५३	—
	५—करछना	२६-१-१९५३	—
१५—जालौन	१—एट	२६-१-१९५४	२६-१-१९५६
	२—खुटण्ड	२-१०-१९५४	—
	३—कदौरा	२६-१-१९५६	—
१६—हमीरपुर	१—मोदहा	२६-१-१९५४	२६-१-१९५६
	२—गोहन्द	२-१०-१९५४	—
	३—सुमेरपुर	२६-१-१९५६	—
१७—बांदा	१—महुआ	२-१०-१९५३	२६-१-१९५६
	२—मानिकपुर	२-१०-१९५४	—
	३—मऊ	२६-१-१९५५	—
१८—बनारस	१—आराजीलाइनस्	२६-१-१९५५	—
	२—औराई	२६-१-१९५४	२६-१-१९५६
	३—काशी विद्यापीठ	२६-१-१९५५	—
१९—जौनपुर	१—बादशाहपुर	२-१०-१९५३	२६-१-१९५६
	२—दोभी	२६-१-१९५५	—
	३—रामपुर	२-१०-१९५५	—
२०—नैनीताल	१—खतीमा	२-१०१९५३	—
	२—औखलखण्डा	२६-१-१९५४	२६-१-१९५६
	३—रुद्रपुर	२-१०-१०५४	—
२१—अलमोड़ा	१—ताड़ीखेत	२-१०-१९५३	—
	२—मल्लोतेखारी	२६-१-१९५५	—
	३—हवलबाग	२६-१-१९५५	—
	४—धारचूला	२-१०-१९५५	—

नाम जिला	एन० ई० एस० ब्लाक का नाम	ब्लाक खुलने की तारीख	इन्टेन्सिव ब्लाक बनाई जाने की तारीख
१	२	३	४
२२—गढ़वाल	१—डाडामन्डी	२६-१-१९५४	२६-१-१९५३
	२—जोशीमठ (चमोलीखंड)	२-१०-१९५५	—
	३—थल्लीसैंण	२६-१-१९५६	—
२३—टेहरी-गढ़वाल	१—नवगांव	२-१०-१९५४	२६-१-१९५३
	२—भगवाड़ी	२-१०-१९५५	—
	३—जवनपुर	२६-१-१९५६	—
२४—लखनऊ	१—गोसाईगंज	२६-१-१९५३	२६-१-१९५६
	२—सरोजनी नगर	२६-१०-१९५४	—
	३—बक्शी का तालाब	२-१०-१९५४	—
२५—उन्नाव	१—नवाबगंज	२६-१-१९५४	२६-१-१९५६
	२—फतेहपुर	२६-१-१९५५	—
	३—सुमेरपुर	२६-१-१९५६	—
२६—रायबरेली	१—सलोन	२६-१-१९५४	२६-१-१९५६
	२—हरचन्दपुर	२६-१-१९५५	—
	३—महराजगंज	२६-१-१९५६	—
२७—सीतापुर	१—हरगांव	२६-१-१९५४	२६-१-१९५६
	२—बेहता	२-१०-१९५४	—
	३—सिधौली	२६-१-१९५६	—
२८—हरदोई	१—बिलग्राम	२६-१-१९५४	२६-१-१९५६
	२—कोंवा	२६-१-१९५५	—
	३—संडी	२-१०-१९५५	—
२९—खीरी	१—बेहजान	२६-१-१९५५	२६-१-१९५६
	२—निघासन	२-१०-१९५४	—
	३—मिटोली	२-१०-१९५५	—
३०—गोंडा	१—इंटियाठोक	२६-१-१९५४	—
	२—मनकापुर	२६-१-१९५५	—
	३—परसपुर	२-१०-१९५५	—
३१—बहराइच	१—केसरगंज	२६-१-१९५४	२६-१-१९५६
	२—सिरसिया	२६-१-१९५५	—
	३—महिमपुरवा	२-१०-१९५५	—
३२—प्रतापगढ़	१—लक्षणपुर	२६-१-१९५४	—
	२—आसपुर-देवसारा	२६-१-१९५५	—
	३—भवानीगंज	२-१०-१९५५	—
३३—बाराबंकी	१—रामनगर	२६-१-१९५४	—
	२—मसौली	२६-१-१९५५	—
	३—सिधौली	२६-१-१९५५	—

ऊपर दिए हुए २६ इन्टेन्सिव ब्लाकों के अलावा निचलोल ब्लाक (गोरखपुर) और कैप्टेनगंज ब्लाक (देवरिया) भी २६-१-१९५६ से इन्टेन्सिव ब्लाक हो गए हैं। इस तरह २८ इन्टेन्सिव ब्लाक खोले गए हैं।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२४८ एल० ए०—१९५६—७९६।